चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 26 अक्टूबर–1 नवंबर 2009

शिक्षा की बदहाली का ज़िम्मेदार कौन?

सियासी दुनिया पेज 3

रक्षक से भक्षक बन गई यूपी पुलिस

सियासी दुनिया पेज 6

दूध संग्रहण केंद्र से ज़िंदगी हुई ख़ुशहाल

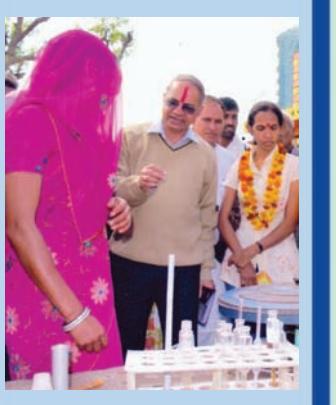

अपनी दुनिया पेज 7

पाकिस्तान में लोकतंत्र पर मंडराता ख़तरा

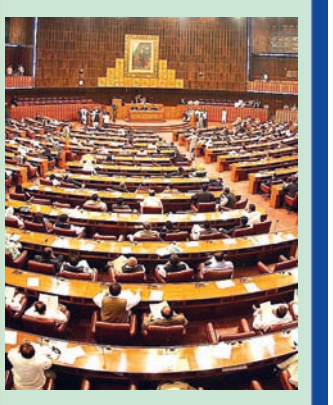

बाक़ी दुनिया पेज 11

विंध्य की अवैध खदानें बनीं मौत का कुआं

परिवार का पेट भरने की चिंता उन्हें मौत के उस दरवाजे तक खींच लाती है, जहां से सही सलामत घर लौटने की कोई गारंटी नहीं है. उनकी इसी मजबूरी का जमकर फायदा उठाते हैं अवैध खदानों के संचालक, जिन्हें संरक्षण दे रहे हैं सत्ताधारी दल के कुछ नुमाइंदे. कब चेतेगा शासन-प्रशासन?

शिवदास

विंध्य क्षेत्र के आदिवासी ग़रीबी और बेरोज़गारी से बेहाल हैं, साथ ही उनकी संस्कृति भी ख़तरे में है. अनोखी लोकनृत्य कला करमा और झूमर के जरिए अपने फन का लोहा मनवा चुके इन आदिवासियों की संस्कृति मौत का कुआं बन चुकीं अवैध खदानों में दम तोड़ रही है. विंध्य पर्वत माला की गोद में आबाद सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और सिंगरौली (मध्य प्रदेश) आदि जनपदों की पत्थर खदानों में हर दिन औसतन एक मजदूर की मौत हो रही है. नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र के खनन क्षेत्रों में ही प्रति माह औसतन एक दर्ज़न आदिवासी और परंपरागत वनवासी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं.

सोनभद्र के विभिन्न खनन क्षेत्रों में बीती 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के दौरान लगभग आधा दर्ज़न लोग काल के गाल में समा चुके हैं. नौ अक्टूबर को ओबरा थाना क्षेत्र के रासपहाड़ी स्थित एक अवैध खदान में टीपर पलटने से झारखंड निवासी 24 वर्षीय जगतपाल की मौत हो गई. इसी दिन डाला स्थित एक खदान में घायल हुए 27 वर्षीय नारसिंह की भी मौत हो गई. वह राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुर का निवासी था. सात अक्टूबर का दिन चालीस वर्षीय महावीर के लिए अच्छा नहीं रहा. बिल्ली–मारकुंडी खनन क्षेत्र की एक खदान में काम करते समय वह गंभीर रूप से घायल हो गया. खदान संचालक घायल महावीर को लेकर ग़ायब हो गए. अभी तक महावीर का कोई पता नहीं चल पाया है. करमा थाना अंतर्गत खैरपुर गांव निवासी 35 वर्षीय कमला पांच अक्टूबर को अपने ही गांव की पहाड़ी पर हो रहे अवैध खनन का शिकार हो गया. वह पत्थर की खदान में हुए विस्फोट में अपनी जान गंवा बैठा. चार अक्टूबर को भदोही जनपद के कपसेठी निवासी 42 वर्षीय पेटी ठेकेदार राकेश सिंह का पैर काशी मोड़ स्थित पहाड़ी पर फिसल गया और वह मौत का कुआं बन चुकी एक खदान में गिरे तो फिर उठ नहीं सके.

मध्य प्रदेश के बैढन थाना अंतर्गत पवर गांव निवासी 30 वर्षीय लल्लन एक ट्रक पर खलासी का काम करता था. दो अक्टूबर की रात वह ट्रक के साथ डाला खनन क्षेत्र स्थित एक क्रशर प्लांट में गिट्टी लोड करने के लिए गया था. ट्रक के डापा में सोते समय लल्लन के ऊपर पोकलैन से गिट्टी लोड कर दी गई. इससे उसकी मौक़े पर ही मौत हो गई. एक सप्ताह के अंदर खनन क्षेत्र में ताबड़तोड़ मौतों के बाद भी अवैध खदान संचालकों के प्रति जिला प्रशासन का रवैया उदासीन बना हुआ है. जिला प्रशासन के इसी रवैये के कारण अक्तूबर माह के पूर्व में भी कई मौतें हो चुकी हैं. बीती 29 सितंबर को ओबरा थाना अंतर्गत बिल्ली–मारकुंडी खनन क्षेत्र में 11000 वाट की विद्युत लाइन की चपेट में आकर एक मज़दूर की मौत हो गई. पंतनगर (मिर्ज़ापुर) निवासी शिवनाथ यादव 22 सितंबर को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत खनन क्षेत्र में बोल्डर लदे ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था. ट्रैक्टर–ट्राली अचानक बेक़ाबू होकर एक खदान में पलट गई और शिवनाथ की मौत हो गई.

दुद्धी कोतवाली अंतर्गत रन्नो गांव निवासी 32 वर्षीय उमाशंकर 18 अगस्त को बारी स्थित पत्थर की खदान में ड्रिलिंग का काम कर रहा था. अचानक एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई. 12 अगस्त का दिन भी खनन क्षेत्र के मजदूरों के लिए अच्छा नहीं रहा. जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जुटा था, उस समय कुछ मजदूर अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहे थे. ओबरा थाना अंतर्गत बैरपुर निवासी 30 वर्षीय कैलाश और राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के खैराही गांव निवासी 20 वर्षीय छोटेलाल बिल्ली–मारकंडी खनन क्षेत्र स्थित एक खदान में काम कर रहे थे. अचानक दोनों लोग पैलोडर की चपेट में आ गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे.

घोरावल थाना क्षेत्र के मझली–हिनौती गांव निवासी 24 वर्षीय संजय 27 जून को अमिलौधा गांव स्थित एक खदान में भगवान को प्यारा हो गया. संजय के ऊपर मोरम का ढुहा गिर गया और उसने मौक़े पर ही दम तोड़ दिया.

26 जून को चोपन थाना क्षेत्र के पटवध गांव के पास बोल्डर लदी एक ट्रैक्टर–ट्राली पलट गई, जिससे भटवा टोला निवासी 20 वर्षीय पप्पू सिंह की मौत हो गई. दो अन्य मज़दूर 18 वर्षीय नागेंद्र और 55 वर्षीय डंगर भी गंभीर रूप से घायल हो गए. पन्नूगंज थाना अंतर्गत किरहुलिया ग्रामसभा के कटरी टोला निवासी दो सगे भाई अर्जुन चेरो व बल्ली चेरो और शिव कुमार यादव 21 जून को वन विभाग की ज़मीन पर बन रहे चेकडैम में ख़ुदाई कर रहे थे, तभी उनके ऊपर मिट्टी का टीला गिर गया. हादसे में तीनों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

12 मई को डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के बारी स्थित एक अवैध खदान में ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से चालक अखिलेश कुशवाहा की मौत हो गई. कुछ दिनों पहले बारी खनन क्षेत्र की ही एक अन्य खदान में पत्थर का टीला गिरने से दो मज़दूरों की मौत हो गई थी.

25 अप्रैल को काशी मोड़ स्थित एक अवैध खदान में टीला गिरने से पन्नूगंज थाना क्षेत्र के दिनारे गांव निवासी 40 वर्षीय राम चरित्र गोंड़ व चोपन थाना अंतर्गत कुशहिया टोला निवासी 45 वर्षीय जयराम अगरिया की मौत हो गई थी. हादसे में पांच अन्य मज़दूर भी घायल हो गए थे. इससे पूर्व काशी मोड़ स्थित एक पत्थर खदान में हुए विस्फोट में तीन मज़दूरों की मौक़े पर ही मौत हो गई थी और दर्ज़नों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इससे पहले बारी स्थित एक खदान में एक महिला का शव संदिग्धावस्था में मिला था. इसके अलावा कुछ दिनों पहले बारी स्थित जय बजरंग क्रशर प्लांट के डग में ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से युवक की मौत, कोठा टोला स्थित श्यामलाल केशरी के क्रशर प्लांट के डग की दीवार ढहने से तीन मज़दूरों की मौत, काशी मोड़ स्थित संजय तिवारी की खदान में ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से चालक की मौत, लंगड़ा मोड़ स्थित खदान में एक मज़दूर की मौत, सुभाष स्टोन की खदान में एक मज़दूर की मौत, बारी स्थित गिरीबाबा के पास एक पत्थर खदान में बाइक सवार और ट्रैक्टर चालक की मौत और माता प्रसाद की खदान में टीला गिरने से एक पेटीदार की मौत आदि जैसी दर्जनों घटनाएं इस खनन क्षेत्र में घट चुकी हैं. ये वे घटनाएं हैं जो मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचीं. इसके अलावा खनन क्षेत्र में अन्य सैकड़ों मौतें होती हैं जिनका पता मीडिया प्रतिनिधियों को नहीं हो पाता है. कुछ का पता हो भी पाता है तो पुलिस इन मौतों का अन्य कारण बताकर मामले को रफादफा कर देती है. भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे प्रशासन की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की वादाखिलाफी ने मजदूरों में भय पैदा कर दिया है. एक के बाद एक हो रही आदिवासियों समेत मजलूमों की मौतों की सच्चाई कोई भी बताने को तैयार नहीं है.

क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश परिवार ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं. इनमें शिक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का घोर अभाव है. क्षेत्र में कल-कारखानों की स्थापना के बाद विस्थापन और भूमिहीनता का दंश झेल रहे आदिवासियों, परंपरागत वनवासियों और दलितों के सामने रोज़गार का संकट है.

विंध्य क्षेत्र खासकर सोनभद्र के खनन क्षेत्र में हो रही मजदूरों की मौत के लिए प्रशासन की भूमिका संतोषजनक नहीं है. सोनभद्र के ज़िला ख़ान अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों की मानें तो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्रावधानों के तहत डोलो स्टोन के 138 खनन पट्टे, सैंड स्टोन के 89 खनन पट्टे व बालू/मोरम के 42 खनन पट्टे यानी कुल 269 खनन पट्टे स्वीकृत हैं. बुनियादी तौर पर खान विभाग के आंकड़े वास्तविकता से कोसों दूर हैं. बिल्ली, मारकुंडी, डाला, चोपन, बारी, रासपहाड़ी, सलखन, खैराही, सुकृत, घोरावल, पकरहट और बहुअरा आदि का निरीक्षण करने पर इनकी संख्या हज़ारों में पाई जाती है, जो पूरी तरह अवैध हैं. खनिज पदार्थों के परिवहन में भी खनन माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी की जा रही है. फिर भी प्रशासन मौन है. अवैध परिवहन की बात कई बार जिला प्रशासन के छापे में सामने आ चुकी है. खनन क्षेत्र में अवैध खनन की पुष्टि जिला खान अधिकारी भी कर चुके हैं. ज़िला ख़ान अधिकारी ए के सेन द्वारा अपना दल के अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंच के जिलाध्यक्ष राधेश्याम भारती को बीती 11 जून को लिखे गए पत्र के जवाब में बिल्ली–मारकुंडी के आराजी संख्या 4596, 4597, 4599, 4845 व 4838 में अवैध खनन की बात स्वीकार भी की जा चुकी है. सेन अवैध खनन को बंद कराने का दावा भी करते हैं, लेकिन उक्त आराजी संख्या वाली जमीनों पर अवैध खनन और परिवहन बेरोकटोक जारी है. इतना ही नहीं, खनन क्षेत्र में हो रही ताबड़तोड़ मौतों और अवैध खनन के बाद भी जिला प्रशासन रॉबर्ट्सगंज तहसील के अंतर्गत बरदिया, बिल्ली मारकुंडी, सुकृत आदि में डोलोस्टोन, सैंडस्टोन और लालमोरंग के खनन के लिए बाकायदा टेंडर जारी कर पट्टा आवंटन को अंजाम दे रहा है. वैध खदानों की आड़ में अवैध खनन व परिवहन कर रहे खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने में असफल प्रशासन की कारगुजारियों के कारण खनन क्षेत्र में मजदूरों की मौतों में इजाफा हो रहा है. विंध्य क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर यथाशीघ्र अंकुश लगाने की जरूरत है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब आदिवासियों की लोक संस्कृति इतिहास के पन्नों में ही पढ़ने को मिलेगी.

क्यों होती हैं मौतें?

यह एक पहेली की तरह है. अब तक हुई मौतों की रोशनी में विचार करें तो इस दिशा में कई बातें सामने आती हैं. विंध्य क्षेत्र की इन पत्थर, मोरम, मिट्टी, बालू और कोयला आदि की अवैध खदानों में काम करने वाले अधिकतर मज़दूर विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल से अनभिज्ञ होते हैं और उन्हें खनन के लिए प्रशिक्षित भी नहीं किया जाता. परिणामस्वरूप ज़रा सी चूक होने पर वे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं. यहां की पत्थर खदानें 50 मीटर से **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

सत्ताधारी पार्टियों के नुमाइंदों और सफ़ेदपोशों ने विंध्य क्षेत्र से धन उगाही के लिए बाक़ायदा अपने एजेंट तैनात कर रखे हैं और क़ानून की धज्जियां उड़ाकर अवैध खनन एवं परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

और अब सीएमओ...

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज्य के विकास कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की स्थापना की है. इसमें कोई शक़ नहीं है यह क़दम प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और मायावती के उत्तर प्रदेश की देखा–देखी उठाया गया है. यह तो ज़ाहिर है कि सीएमओ बुद्धदेव की प्रिय परियोजना है, लेकिन इस मामले में उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है. यह विरोध ख़ासतौर से उन लोगों का है, जिन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इस कार्यालय की स्थापना से मुख्यमंत्री सचिवालय, पार्टी कार्यकर्ताओं और नियमित बाबुओं से ज़्यादा सशक्त हो जाएगा, लेकिन हाल–फ़िलहाल के लिए तो मुख्यमंत्री ने इससे बचने का तरीक़ा निकाल लिया है.

सीएमओ को कैबिनेट और आम जनता की शिकायतों से जुड़े मामलों से निपटने के अलावा मुख्यमंत्री के विवेकाधीन अनुदान और राहत कोष से संबंधित अधिकार भी मिल गए हैं. यह किसी भी विकास परियोजना की प्रगति की निगरानी के साथ–साथ राज्य सरकार के मार्फत प्रेस बयान भी जारी कर सकता है. यह कार्यालय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबेश दास के नेतृत्व में काम करेगा. इधर बुद्धदेब भी पीएमओ की कार्य– शैली की तर्ज़ पर, सीएमओ में सहायक के तौर पर बोर्ड विशेषज्ञ, सेवानिवृत अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को लाने की योजना बना रहे हैं. कोलकाता का सीएमओ राज्य प्रशासन को कितना बेहतर बना पाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

मित्तल की उम्मीदों पर बाबुओं ने फेरा पानी

नौ करशाहों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने मिलकर, झारखंड में लक्ष्मी मित्तल की चिरिया लौह अयस्क खानों की योजनाओं पर पानी फेर दिया है. सेल और निजी क्षेत्रों के बीच खानों के बटवारे को तय करते हुए, इस्पात सचिव पी के रस्तोगी, झारखंड के मुख्य सचिव ए के बसु और सेल के निवर्तमान अध्यक्ष एस के रुंगटा, बड़े ही प्रभावी तरीक़े से मित्तल की खान संबधी योजनाओं को विफल करने में कामयाब रहे. हालांकि उन्हें अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है. ग़ौरतलब है कि मित्तल पहले ही साफ़ कर चुके हैं कि यदि उनकी कंपनी आर्सेलर मित्तल को चिरिया से अयस्कों के लिए इंकार किया गया और साथ ही झारखंड और उड़ीसा में प्रस्तावित संयत्रों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को शीघ्र नहीं सुलझाया गया तो वे भारत से अपना बोरिया–बिस्तर भी बांध सकते हैं .

जिस तरह से सरकार ने खनन संबंधी लीज को सरकारी कंपनी सेल के पक्ष में देकर अपनी विस्तार योजनाओं को बरक़रार रखा है, उससे साफ़ है कि सरकार की दयादृष्टि किस तरफ़ ज़्यादा है. वह भी तब जब उक्त निर्णय उदारीकरण की तुलना में संरक्षीकरण का ज़्यादा लगता है .

और इधर बाबू अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं. अब देखना है कि मित्तल अपनी भारत छोड़ने की धमकी पर अड़े रहते हैं या फिर भारत सरकार की शर्तों के मुताबिक़ चलने का फ़ैसला लेते हैं.

विंध्य की अवैध खदानें बनीं मौत का कुआं

पृष्ठ 1 का शेष

लेकर 200 मीटर तक गहरी हो चुकी हैं. इन खदानों में काम करना अप्रशिक्षित मज़दूरों के लिए शेर की मांद में घुसने के बराबर है. दूसरी वजह यह कि विंध्य क्षेत्र में डोलो स्टोन, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, कोयला, बालू और मोरम आदि का अकूत भंडार है. इन खनिज पदार्थों के दोहन के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के माफ़ियाओं और सफ़ेदपोशों ने अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है. सत्ताधारी पार्टियों के नुमाइंदों और मलाईदार मंत्रालयों की कुर्सी संभाल रहे कुछ सफ़ेदपोशों ने विंध्य क्षेत्र से धन उगाही के लिए बाक़ायदा अपने एजेंट तैनात कर रखे हैं और क़ानून की धज्जियां उड़ाकर अवैध खनन एवं परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं. माफ़ियाओं ने पूरे विंध्य क्षेत्र में अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है. वे विंध्य की पहाड़ियों पर खुलेआम अवैध खनन करा रहे हैं. साथ ही खनन विभाग द्वारा जारी एमएम–11 परमिट के बिना मिट्टी, मोरम, बालू और बोल्डर आदि का परिवहन करा रहे हैं. शासन द्वारा निर्धारित मानकों को खनन क्षेत्र का कोई भी खदान संचालक पूरा नहीं कर रहा है. खदानों में सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम नहीं हैं. खदान अथवा क्रशर प्लांट को जाने वाले रास्ते तारकोल और खड़ंजायुक्त नहीं हैं और न ही किसी खदान के चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाई गई है. अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन ने टास्क फोर्स की टीमें तो गठित की हैं, लेकिन वे औपचारिकता मात्र बनकर रह गई हैं. सोनभद्र के खनन क्षेत्रों में पूर्वांचल के माफ़ियाओं की दख़लंदाज़ी ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया है. सत्ताधारी लोगों की शह पाकर वे ख़ान विभाग की टीम पर भी हमला करने लगे हैं. कुछ दिनों पहले विभाग के एक सर्वेयर ने ज़िलाधिकारी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी.

सोनभद्र के ज़िला ख़ान अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों की मानें तो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्रावधानों के तहत डोलो स्टोन के 138 खनन पट्टे, सैंड स्टोन के 89 खनन पट्टे व बालू/मोरम के 42 खनन पट्टे यानी कुल 269 खनन पट्टे स्वीकृत हैं, लेकिन बिल्ली, मारकुंडी, डाला, चोपन, बारी, रासपहाड़ी, सलखन, खैराही, सुकृत, घोरावल, पकरहट और बहुअरा आदि का निरीक्षण करने पर इनकी संख्या हज़ारों में पाई जाती है, जो पूरी तरह अवैध हैं. ज़िला ख़ान अधिकारी ए के सेन द्वारा एक पत्र के जवाब में बिल्ली–मारकुंडी के आराजी संख्या 4596, 4597, 4599, 4845 व 4838 में अवैध खनन की बात स्वीकार भी की जा चुकी है.

कौन हैं खदानों में आने वाले मज़दूर

सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सिंगरौली (मध्य प्रदेश), गढ़वा (झारखंड) और भभुआ (बिहार) आदि जनपद आदिवासी बहुल हैं. विंध्य क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश परिवार ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं. इनमें शिक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का घोर अभाव है. क्षेत्र में कल–कारखानों की स्थापना के बाद विस्थापन और भूमिहीनता का दंश झेल रहे आदिवासियों, परंपरागत वनवासियों और दलितों के सामने रोज़गार का संकट है. बेरोज़गारी और ज़िम्मेदारी से बेहाल लोगों के लिए यह अवैध खदानें पेट में लगी आग को शांत करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना समेत केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं भ्रष्ट नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों की वादाख़िलाफ़ी के चलते इन परिवारों को कोई भी राहत नहीं दे पा रही हैं.

हाल बेहाल हैं दिवंगत मज़दूरों के परिवार

चोपन थाना अंतर्गत मारकुंडी ग्राम सभा के आदिवासी बहुल कुशहिया टोला निवासी चालीस वर्षीय जयराम अगरिया अपने 11 सदस्यीय परिवार का ख़र्च चलाने के लिए डाला खनन क्षेत्र की पत्थर की खदानों में मज़दूरी करते थे. चालू वर्ष की 25 अप्रैल को डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के काशी मोड़ स्थित पत्थर की एक खदान में जयराम अगरिया, पन्नूगंज थाना क्षेत्र के दिनारे गांव निवासी 45 वर्षीय रामचरित्र गोंड़ की पत्थर का टीला गिरने से मौत हो गई. इस दुर्घटना में अन्य पांच मज़दूर की गंभीर रूप से घायल हो गए. जयराम अगरिया की मौत का कहर इन दिनों उनके परिवार पर कहर बनकर टूट रहा है. जयराम के परिवार में उनकी पत्नी जिरमन, तीन लड़के बाबूलाल (20 वर्ष), पिन्टू (15 वर्ष), बहू सुकुवारी (18 वर्ष), पोती सोनिया (एक वर्ष), दो पुत्रियां अनीता (8 वर्ष) व सुनीता (5 वर्ष) हैं. इसके अलावा जयराम के 70 वर्षीय विकलांग ससुर लक्ष्मण और 65 वर्षीय सास सुकुवारी की ज़िम्मेदारी भी परिवार के मुखिया पर है. मिट्टी की दीवार पर टूटी–फुटी छाजन के घर में रहकर पूरा परिवार अपने जीवन की नैया पार लगाने की कोशिश कर रहा हैं. सरकारी काग़ज़ पर जयराम के नाम क़रीब सात बीघा पथरीली ज़मीन तो दर्ज़ है लेकिन वास्तविकता में इस ज़मीन से परिवार को दो वक़्त की रोटी नसीब नहीं होती. जयराम अगरिया के 11 सदस्यीय के कुनबे के मुखिया के नाम ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का राशन कार्ड बना है लेकिन सरकारी राशन की दुकान से अनाज ख़रीदने के लिए समय पर पैसे की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत बनने वाले जॉब कार्ड का भी लाभ परिवार को नहीं मिल रहा हैं. जयराम अगरिया की पत्नी के नाम महामाया आवास तो मिला है लेकिन 11 सदस्यीय कुनबे का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है. क़रीब बीस वर्षो से रह रहे जयराम अगरिया के वृद्ध सास व ससुर को आज तक एक भी सरकारी सहायता का लाभ नसीब नहीं हो पाया है. बच्चों की पढ़ाई–लिखाई बंद हो गई हैं. जयराम अगरिया की मौत के बाद परिवार के ख़र्चे की ज़िम्मेदारी जिरमन और बाबूलाल पर आ गई है. बेरोज़गारी की दंश झेल रहे परिवार के दोनों सदस्य मौत का कुआं बन चुकी पत्थर की खदानों में पत्थर तोड़ने अहले सुबह डाला चले जाते है और देर शाम क़रीब 50 मीटर की दूरी तय कर वापस घर आते हैं. पत्थर की खदानों में काम करते समय परिवार के दोनों व्यक्तियों की कब मौत हो जाए और पूरा परिवार दाने–दाने को मोहताज हो जाए, इस बात का भय पूरे परिवार को हमेशा सालता रहता है. कुछ ऐसा ही हाल रामचरित्र गोड़ समेत अन्य आदिवासी एवं परंपरागत वन निवासी उन मज़दूरों के परिवार का भी है जो पत्थर की खदानों में दम तोड़ चुके हैं. कुछ ऐसा ही हाल पन्नूगंज थाना अंतर्गत किरहुलिया ग्राम सभा के कटरी टोला निवासी अर्जुन चेरो (40 वर्श) व बल्ली चेरो (35 वर्श) के परिवार का भी है. अर्जुन चेरो और बल्ली चेरो बीती 21 जून को पास में वन विभाग की ओर से बन रहे चेकडैम में अपने साथी मज़दूर शिव कुमार यादव के साथ काम कर रहे थे. अचानक तीनों के ऊपर मिट्टी का दूहा गिर गया और तीनों की मौत हो गई. शासन की ओर से तीनों के परिवार वालों को एक–एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई लेकिन सरकार की अन्य सुविधाओं का लाभ परिवारों को नहीं मिल पाया है. इस कारण अर्जुन चेरो और बल्ली चेरो के परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भूमिहीन अर्जुन चेरो के परिवार में उनकी 32 वर्षीय पत्नी फुलझरी, 65 वर्षीय मां भगमतिया, दो बेटियां समुन (12 वर्ष) व रीना (6 वर्ष), पुत्र शुजुल (एक वर्ष), रामबाबू (3 वर्ष) है. वहीं बल्ली चेरो के परिवार में उनकी 30 वर्षीय पत्नी कौशिल्या (33 वर्ष) व एक वर्षीय पुत्री चंद्रावती है. पूरा परिवार मिट्टी के घर में रहकर जीवन यापन करता है. अर्जुन चेरो की मौत के बाद से ही उनकी पत्नी फुलझरी बीमार चल रही है. 12 वर्षीय बेटी सुमन समेत सभी भाइयों एवं बहनों की पढ़ाई छूट गई है. सुमन परिवार के नाम बने जॉब कार्ड पर काम करती है. पूरे परिवार को अभी तक मात्र 14 दिन का रोज़गार मिला है. ग़रीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करने वाले परिवार का कार्ड बना है लेकिन अनाज सिर्फ़ एक बार ही मिल पाया है. इस समय पूरा परिवार दाने–दाने के संकट से जूझ रहा है.

अर्जुन चेरो और बल्ली चेरो का परिवार एक मामले में ख़ुशनसीब रहा कि शासन ने तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया करा दी, लेकिन अवैध पत्थर की खदानों में मरने वाले मज़दूरों को ये ख़ुशनसीबी हासिल नहीं होती. मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन के बाद जयराम अगरिया, रामचरित्र गोंड़ के परिवार को तो खदान संचालकों की ओर से एक–एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता तो मिल गई लेकिन अन्य मज़दूरों के परिवार वालों को एक फूटी कौड़ी भी मयस्सर नहीं होती है. खनन माफ़िया पुलिस की मिलीभगत से पूरे मामले को ही रफा–दफा कर देते हैं. पत्थर की खदानों में मरने वाले सैकड़ों मज़दूरों के परिवार इन दिनों दाने–दाने को मोहताज हो गए हैं और भुखमरी के कगार पर हैं. अगर समय पर इन परिवार के सदस्यों को रोज़गार और सरकारी योजनाओं की सहायता नहीं मिली तो विंध्य क्षेत्र में भुखमरी और कुपोषण से मरने वालों की संख्या में इज़ाफ़ा हो सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 1 अंक 33, 26 अक्टूबर–1 नवंबर 2009

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तरप्रदेश – 201301

फोन न.
संपादकीय 011–47149999
विज्ञापन + 0120–4783999
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सबसे घटिया है. लोकसेवक और कनिष्ठ स्तर के नौकरशाह ईर्ष्यापूर्वक बजट और राशियों की निगरानी करते हैं. जिन स्कूलों को अधिक फंड मिलता है, वहां इन प्रभावशाली शिक्षक संगठनों की तो चांदी ही चांदी है.

शिक्षा की बदहाली का ज़िम्मेदार कौन?

प्रयाग अकबर

पिछले महीने राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश यात्रा ने कई वजहों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन उनकी इस भव्य यात्रा का एक अहम हिस्सा पूरी तरह अंधेरे की गर्त में छुपा ही रह गया. आदतन, राहुल बग़ैर किसी पूर्व सूचना के श्रावस्ती ज़िले के तिलहर माजरा गांव पहुंचे. फिर यहां से उन्होंने पास के ही सरकारी स्कूल की ओर रुख़ किया, जहां उनके सामने एक विचित्र नज़ारा था. इस स्कूल में बच्चों की तादाद तो कुल 250 थी, लेकिन शिक्षकों की संख्या शून्य. मीडिया ने किसी भी लिहाज से इसे ख़बर के लायक़ नहीं माना. भारत में एक आम आदमी भी जो शिक्षा व्यवस्था से थोड़ा-बहुत वाक़िफ़ है, उसके लिए सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत कतई आश्चर्य की बात नहीं है. हमारे गांव, छोटे शहर, शहर और महानगर ऐसी बुरी कहानियों से भरे पड़े हैं.

भारत में शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ा मिथक है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने कम वेतन की वजह से हतोत्साहित रहते हैं. लेकिन, हाल की लैंट प्रिशेट और रिक्ष्मु मुर्गइ द्वारा तैयार विश्व बैंक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक पंजीकृत निजी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में तीन गुना अधिक वेतन का लाभ उठा रहे हैं. जबकि अपंजीकृत निजी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में यह आंकड़ा सात गुना अधिक है. इसी रिपोर्ट के मुताबिक़, छात्र और माता-पिता सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था से अधिक संतुष्ट नज़र आए. और, यह सब छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के लागू होने के बाद की कहानी है, जिसके तहत शिक्षकों के वेतन में बेतहाशा वृद्धि हुई.

भारत में बड़े पैमाने पर शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षकों पर किया जाने वाला ख़र्च इस योजना का सिर्फ़ एक पहलू है. नौकरशाही का एक बड़ा तबका इस क्षेत्र पर अपना क़ब्ज़ा जमाए हुए है. प्राय: हर स्तर पर इसका इतना असर है कि देश के ग़रीब बच्चों के लिए आवंटित राशि की लूटखसोट करना इसके लिए कतई मुश्किल नहीं है.

भारत में बड़े पैमाने पर शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षकों पर किया जाने वाला ख़र्च इस योजना का सिर्फ़ एक पहलू है. नौकरशाही का एक बड़ा तबका इस क्षेत्र पर अपना क़ब्ज़ा जमाए हुए है. प्राय: हर स्तर पर इसका इतना असर है कि देश के ग़रीब बच्चों के लिए आवंटित राशि की लूटखसोट करना इसके लिए कतई मुश्किल नहीं है. हमें इससे यह सीख मिलती है कि नागरिकों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से चलने वाले सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सबसे घटिया है. लोकसेवक और कनिष्ठ स्तर के नौकरशाह ईर्ष्यापूर्वक बजट और राशियों की निगरानी करते हैं. जिन स्कूलों को अधिक फंड मिलता है, वहां इन प्रभावशाली शिक्षक संगठनों की तो चांदी ही चांदी है. जबकि काम के नाम पर ये अक्सर नदारद रहते हैं. और, जब इन स्कूलों में दाख़िले की बात आती है तो योग्यता को ताक पर रख दिया जाता है. अंतत: सर्व शिक्षा एवं मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं के सकारात्मक नतीजों के साथ-साथ नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं.

तानाशाही और नौकरशाह

प्राय: हर व्यक्ति , चाहे वह शिक्षा क्षेत्र से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हो या सरकारी अथवा निजी स्कूल का शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या अभिभावक, इस बात पर ज़ोर देते हैं कि शिक्षा में नौकरशाहों का दबदबा कुछ ज़्यादा है. पूरी व्यवस्था में सरकारी और नगर निगम स्कूलों के हेड मास्टरों को छोटी राशि के आवंटन या बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ख़ुद से भी निचले स्तर के नौकरशाहों की जी-हुज़ूरी करनी पड़ती है. उन्हें इतनी भी आज़ादी नहीं होती कि वे ख़ुद कोई भी फ़ैसला ले सकें. नौकरशाही की ऐसी बर्बर कहानी हर जगह मिलती है. दिल्ली में शिक्षकों से जुड़े इस तरह के कई मामले हैं. यहां तक कि नौकरशाही द्वारा यह सख्त निर्देश दिया गया है कि सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल मीडिया से बात नहीं करेंगे. जो बातें हम आपको बता रहे हैं, यह सारी कहानी शिक्षकों ने हमें गुप्त तौर पर बताई और यह शर्त भी रखी कि हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे. एमसीडी के एक पूर्व शिक्षा निदेशक ने बताया कि यदि उनका नाम छाप दिया गया तो उन्हें अपनी पेंशन से ही हाथ धोना पड़ेगा.

प्राथमिक विद्यालय के एक प्रिंसिपल ने हमसे एक बेहद ही सनसनीख़ेज अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि एक बार चना बेचने वाला हमारे स्कूल में पहुंच गया और उसने कक्षा तीन की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. हमने एक जांच टीम गठित की और संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत कराया. साथ ही हमने इन अधिकारियों से यह मांग भी की कि 12 घंटे तक दो शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों के लिए गार्ड उपलब्ध कराए जाएं. इस पर उनके ऑफिस में हमारा मज़ाक उड़ाया गया. जब हम अपनी मांग पर अड़े रहे तो हमें तबादले और यहां तक कि बर्ख़ास्त करने जैसी धमकियां दी गईं. लेकिन उन्होंने हमारे आग्रह पर क्यों नहीं विचार किया? प्रिंसिपल ने बताया कि मैं नहीं जानता. यह ख़र्च बजट के बाहर आता. शायद इसीलिए.

शिक्षा क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है विभिन्न शिक्षक संगठनों का प्रभाव, जो बड़े शहरों और कुछ राज्यों में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है. शिक्षा से जुड़े एक ग़ैर सरकारी संगठन की निदेशक यामिनी अय्यर का कहना है कि भारत में सरकारी स्कूलों की यह सबसे प्रमुख समस्या है. वह कहती हैं कि छुटभैये नेता और शिक्षक संगठनों के बीच खुली मिलीभगत है. इनके बढ़ते प्रभाव की वजह से ही सरकारी शिक्षक अपनी नाक के नीचे हो रही लापरवाही के प्रति भी आंखें मूंदे रहते हैं. अय्यर बिहार में नीतीश सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों की चर्चा करती हैं. नीतीश पूरे सिस्टम को फिर से चुस्त-दुरुस्त कर रहे थे. राज्य स्तर पर शिक्षकों की बहाली की जगह प्रखंड अधिकारियों ने पंचायत स्तर पर शिक्षकों की बहाली शुरू की. इस योजना के तहत लगभग दो लाख शिक्षकों की बहाली की गई और यह प्रक्रिया बिल्कुल उपयुक्त और कम ख़र्च वाली भी है, लेकिन शिक्षक संगठन से जुड़े कुछ लोग इस मामले को न्यायालय में ले गए(क्योंकि इससे उनके अधिकार समाप्त हो जाते). अब न्यायालय ने अपना फ़ैसला इन संगठनों के पक्ष में दिया है और इस तरह एक बेहद महत्वपूर्ण योजना अपनी पटरी से उतर गई. इस उदाहरण को ऑक्सफोर्ड के शोध छात्र गीता किंगडॉन और मोहम्मद मुज्जमिल ने अपने शोध में शामिल किया, जो 2009 में प्रकाशित भी हुआ.

सबसे दिलचस्प तो यह है कि शिक्षक संगठनों ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक राज्य विधान मंडल के ऊपरी सदन में 8.5 फ़ीसदी सीटें शिक्षकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए. सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक भी इसी योजना के तहत आते हैं. हालांकि ऐसा प्रावधान है कि लाभ के पद पर रहते हुए कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन उक्त शिक्षक न केवल इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं, बल्कि एमएलसी से लेकर स्थानीय स्तर पर जैसे नगर निगम, नगरपालिका के साथ-साथ विधान सभा और संसद तक के चुनावों में खड़े हो रहे हैं.

दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ख़ासतौर पर इन दो राज्यों में शिक्षक संगठनों की स्थिति काफ़ी मज़बूत है और सभी संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं. टीचर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन कांग्रेस पार्टी के बेहद क़रीब है. जबकि अध्यापक परिषद को आरएसएस संचालित संगठन माना जाता है. अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ भी बीजेपी/संघ परिवार से जुड़ा हुआ है. दिल्ली में 2.5 लाख शिक्षकों में से 60 फ़ीसदी इन संगठनों के सदस्य हैं और यदि आप उनके परिवारों को भी इसमें शामिल करते हैं तो यह एक व्यापक वोट बैंक में तब्दील हो जाता है.

ज़रा उन राजनेताओं की ओर नज़र डालिए, जो स्कूल में शिक्षक या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं. इनमें मायावती, साहिब सिंह वर्मा, जगदीश मुखी, किरण वालिया और योगानंद शास्त्री शामिल हैं. यह सूची काफी लंबी है.

इन शिक्षक संगठनों के नेता चुनाव के वक़्त राजनेताओं के लिए बेहद मददगार साबित होते हैं. वह भी इसलिए कि इन्हें आंकड़ों को तोड़मरोड़ कर पेश करने में महारत हासिल है. एक नौकरशाह ने इनकी सारी राम कहानी हमें बताई. दिल्ली विधानसभा चुनावों के पहले राज्य सरकार ने इनसे अपनी असफलताओं को छुपाने और छात्रों के प्रदर्शन का बेहतर आंकड़ा पेश करने के लिए कहा. यह आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला था, लेकिन संगठन किसी भी तरह अपेक्षित आंकड़ों को सामने लाने में सफल रहा, जिसे बाद में दिल्ली सरकार ने मीडिया के सामने भी पेश किया. 2007 में पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर ने एक समाचारपत्र में राजनेताओं और शिक्षकों की साठगांठ से जुड़े साक्ष्यों का ख़ुलासा किया, जिसमें नेताओं द्वारा इन संगठनों को व्यापक अधिकार देने की वजहों का ज़िक्र किया गया. चुनावों के समय उक्त शिक्षक बूथ पर मौजूद होते हैं. ऐसे में वे उनके विरोधियों की मदद कर सकते हैं. इसलिए नेता इनकी नाराज़गी नहीं झेलना चाहते. नहीं तो इन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं.

भारत में सरकारी स्कूलों की शिक्षा इस बदबूदार दलदल में तब तक फंसी रहेगी, जब तक छात्रों और अभिभावकों के साथ दूसरी ताक़तें अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करतीं. पहले से भी अधिक शक्तिशाली नौकरशाही और शिक्षक संगठनों के राजनीतिक संबंध उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, जहां सर्वाधिक अधिकार इन्हीं दोनों संस्थाओं के पास हैं. स्वाभाविक तौर पर बदलाव की कोई भी कोशिश यदि होती भी है तो उक्त दोनों उनके रास्ते में रुकावटें डालेंगे.

यह सलाह कतई नहीं दी जा सकती कि शिक्षा का निजीकरण ही इसका समाधान है. निजी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर व्यापक मतभेद हैं. निजी स्कूलों की शिक्षा कभी-कभी सरकारी स्कूलों से भी बदतर होती है. इसके अलावा कई दूसरे कारक भी हैं. मसलन ग़ैर जवाबदेह होना, जिसकी वजह से शिक्षा औद्योगिक घरानों और उन लोगों के हाथों में चली जाती है जिनका सिर्फ़ एक ही मक़सद होता है, अधिकतम मुनाफ़ा कमाना. और, यह कतई एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती. फिर भी यह स्पष्ट है कि सरकार वाक़ई सभी को शिक्षा की गुणवत्ता उपलब्ध कराना चाहती है तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनके तहत सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचों में सुधार लाकर ऐसा किया जा सकता है.

यह पूरा तंत्र किस तरह काम करता है, इस पर नई दिल्ली के प्राथमिक स्कूल की एक प्रिंसिपल ने कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी, इन सभी समस्याओं का बच्चों पर, जिन्हें हम शिक्षा देते हैं, क्या असर पड़ता है, हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है. यदि देखा जाए तो कई मायनों में हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने जैसी ही है.

आज के राजनीतिक वर्ग के बहुसंख्यकों को ही देखिए, क्या वे वाक़ई चाहते हैं कि समाज का सबसे निचला तबका शिक्षित हो, उन्हें ज्ञान हासिल हो? नहीं. वे सभी ऐसे वोटर चाहते हैं, जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सके और अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जा सके. वे भयभीत हैं, क्योंकि वे इन स्कूलों से निकलने वाली मायावती, लालू प्रसाद यादव और यहां तक कि अंबेडकर जैसी कोई दूसरी पीढ़ी नहीं चाहते हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा संकट की सिर्फ़ यही वजह मानी जा सकती है कि सरकार भारत के सबसे ग़रीब तबके तक सामाजिक न्याय पहुंचाने में असफल रही है.

feedback@chauthiduniya.com

बिना सोचे समझे मनमाने फैसले उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं. स्थितियां लगातार उसके ख़िलाफ़ जा रही हैं. कैसे? पढ़िए नीचे एक रिपोर्ट में.

मध्यप्रदेश

आदिवासियों की इज़्ज़त दांव पर

नाबालिग बच्ची मां बनी, प्रशासन बेख़बर

संध्या पाण्डे

राज्य में चलने वाले विकास कार्यक्रमों से यहां के विभिन्न आदिवासी क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित हैं और सरकारी अमला सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है. इस क्षेत्र में नक्सलवाद की समस्या के सिर उठाने की यही सबसे बड़ी वजह है. पिछले दिनों यहां के जनपद मंडला में एक नाबालिग आदिवासी लड़की द्वारा एक बच्चे को जन्म देने से खलबली मच गई. राज्य शासन के सभी विभागों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इस घटना को छुपाने की पूरी कोशिश की. घटना ने आदिवासियों के जीवनयापन की समस्या के निदान और सामाजिक संस्कारों की पूर्ति में शासकीय सहयोग के दावे की कलई खोल दी है.

मंडला ज़िले की ग्राम पंचायत खारी के कुणोपानीग गांव के आदिवासी रोज़गार की तलाश में गांव से दूसरे शहरों को चले जाते हैं. यहां एक आदिवासी परिवार की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने एक संतान को जन्म दिया. बताया जाता है कि लड़की अपने माता-पिता की अनुप-स्थिति में दूसरे के खेतों पर काम करने जाती थी. इसी दौरान कुछ दबंग लोग उसका शारीरिक शोषण करते थे. मां-बाप के साथ न रहने के कारण लड़की अपने शारीरिक शोषण के बारे में थाने में रिपोर्ट दर्ज़ नहीं करा पाई. वह गर्भवती हो गई और फिर उसने बच्चे को जन्म दे दिया. उस लड़की के अल्पवयस्क होने के कारण नवजात शिशु कुपोषण का शिकार था. इस घटना के बाद शासन-प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई है.

मंडला राज्य के उन आदिवासी ज़िलों में है, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है. ज़िले के आला अधिकारियों को छोड़िए, यहां विभिन्न विभागों में कार्यरत बाबू स्तर के कर्मचारियों की कोठियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि विभिन्न योजनाओं और विश्व बैंक से मिलने वाले पैसों का आम आदमी के हित में कितना उपयोग किया जाता है. अधिसूचित आदिवासी ज़िला होने के कारण कई योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाला अनुदान नियमानुसार सीधे ज़िला प्रशासन को ही जारी किया जाता है. सरकारी आंकड़ों में मंडला की साक्षरता दर 72 प्रतिशत दर्ज़ है, जबकि वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत है. ग्राम कुणोपानीग में हुई घटना के संदर्भ में चौथी दुनिया ने जब यहां के महिला एवं बाल विकास अधिकारी शशि उईके से बातचीत की तो उन्होंने घटना के बारे में कोई जानकारी होने से मना कर दिया. हां, उन्होंने यह जानकारी ज़रूर दी कि इस क्षेत्र में महिला कार्यकर्ता कार्यरत हैं, परंतु उनके संदर्भ में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई. प्रश्न यह उठता है कि इस नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास अधिकारी, ज़िला पंचायत एवं आदिवासी विकास से संबंधित कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया?

सूबे के मंडला ज़िले की ग्राम पंचायत खारी के कुणोपानीग गांव के आदिवासी परिवार की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया. बताया जाता है कि वह लड़की अपने माता-पिता की अनुपस्थिति में दूसरे के खेतों पर काम करने जाती थी. उसी दौरान कुछ दबंग लोग उसका शारीरिक शोषण करते थे.

पीड़िता के पिता एवं मां द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, भुखमरी के चलते गांव के ज्यादातर परिवार रोज़-गार की तलाश में पलायन कर जाते हैं. गांव में अकेले केवल उनके बच्चे ही रहते हैं. इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शारीरिक शोषण जैसी घटना को अंजाम देना आसान हो जाता है.

राज्य में पंचायतीराज प्रणाली लागू होने के बाद से समस्याओं के निराकरण के लिए पंच और ग्रामीण आपस में बैठकर मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, नतीजतन आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली इस तरह की घटनाएं पुलिस तक नहीं पहुंच पाती हैं. मध्य प्रदेश में आदिवासियों के शोषण की घटनाएं आम हैं. इन घटनाओं के विरुद्ध सुनवाई के लिए कोई भी सक्षम तंत्र नहीं है.

संविधान में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार, अधिसूचित ज़िलों को सर्वाधिक संवेदनशील मानते हुए इनके विकास और सुरक्षा की सबसे अधिक ज़िम्मेदारी ज़िला प्रशासन की ही होती है.

ग्राम कुणापानीग में पैदा संतान अपनी मां के नाबालिग होने के कारण पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकी. ज़िला प्रशासन ने उस बच्चे को इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा, लेकिन चार दिनों तक ज़िंदगी और मौत से लड़ने के बाद नवजात ने दम तोड़ दिया. ज़िला प्रशासन ने उपरोक्त घटना की न तो कोई जांच की है और न ही आदिवासियों के लिए किसी नए सुरक्षातंत्र की स्थापना का कोई प्रयास किया. सरल प्रवृत्ति के आदिवासी भी ऐसी घटनाओं को एक दुर्घटना मानकर भूल जाते हैं. लेकिन यह समस्या का निदान तो कतई नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

जैसी करनी, वैसी भरनी

अजय कुमार

काफी समय के बाद शुक्रवार, 10 अक्टूबर का दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए थोड़ी ख़ुशी-थोड़ा गम लेकर आया. बसपा के संस्थापक कांशीराम की तृतीय पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के दौरान दो ऐसी ख़बरें आईं, जिनमें से एक ने बसपा सुप्रीमो के चेहरे को लालिमा प्रदान की, लेकिन कुछ समय बाद आई दूसरी ख़बर ने माथे पर बल डाल दिए. दोनों ही मामले अदालत के आदेश से जुड़े हुए थे. पहली ख़बर यह थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना यमुना एक्सप्रेस वे की अधिसूचना को न केवल वैध ठहरा दिया, बल्कि इससे जुड़ी कंपनी को अपना काम जारी रखने की छूट दे दी. दूसरी ख़बर यह थी कि सुप्रीमकोर्ट ने नोएडा पार्क में दलित महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मारकों के निर्माण पर रोक लगा दी. इस तरह अब प्रदेश में स्मारक निर्माण संबंधी लगभग सभी कामों पर अदालती आदेश से रोक लग चुकी है. इन झटकों से मायावती की स्थिति माया मिली न राम जैसी हो गई है.

बसपा सुप्रीमो की ग़लत रणनीति का ही परिणाम है कि उनके दोस्तों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और दुश्मनों की लिस्ट लंबी. विरोधी दलों के नेताओं को तो वह मौक़े-बेमौक़े फटकार लगाती ही रहती हैं, मीडिया से भी उनकी कम ही बनती है. यही वजह है कि कई बार सरकार की नेकनीयती की जानकारी भी जनता को नहीं हो पाती. अब तो उन्हें संवैधानिक संगठनों में भी खोट नज़र आने लगे हैं. लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने चुनाव आयोग को ख़ूब खरी-खोटी सुनाई थी, जिसके चलते काफी किरकिरी हुई थी.

जानकार कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो को यह बात कभी रास नहीं आती कि उनके कामकाज के तरीक़े में कोई दूसरा हस्तक्षेप करे. जो ऐसा करता है, उसे वह अपना बैरी मान लेती हैं. प्रदेश की जनता के लिए मायावती की यह ख़ूबी एक अच्छी मिसाल बन सकती थी, अगर वह इसका इस्तेमाल सार्थक कार्यों के लिए करतीं और अपने उस उद्देश्य को न भूलतीं, जिसके लिए उनके राजनीतिक गुरु कांशीराम ने अपना पूरा जीवन बिता दिया था. कांशीराम चाहते थे कि वर्षों से दबे कुचले दलित समाज का बसपा के माध्यम से उद्धार किया जाए. वह ताउम्र दलितों के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे. जब उनके शरीर ने साथ देना बंद कर दिया तो उन्होंने कमान मायावती को सौंप दी. कांशीराम के जीते जी तो मायावती ने दलितों के सम्मान के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनकी आंख बंद होते ही वह बदल गईं.

भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला मौक़ा था, जब अदालत ने किसी राज्य सरकार को चेताया हो कि वह आग से न खेलें. बार-बार की अदालती फटकार ने बसपा सरकार को हिलाकर रख दिया है. 4 अक्टूबर को स्मारकों के निर्माण मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का रुख़ काफी कड़ा दिखा.

फोटो- प्रभात पाण्डेय

जो समाज मायावती के सख्त तेवरों से उद्वेलित हुआ था, वह चिंगारी एक शोला बनती, इससे पहले ही मायावती ने अपना रास्ता बदल लिया. उनके विरोधी दलित की नहीं, दौलत की बेटी कहकर उनका उपहास उड़ाने लगे. बसपा में बदलाव की ऐसी आंधी आई कि संगठन और सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर अगड़ी जाति के लोग आसीन हो गए. दलित समाज और उसके नेता सिर्फ़ तमाशबीन बन कर रह गए. बदलाव के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई पत्थर की मूर्तियों पर लुटाने, विरोधियों को सबक सिखाने के लिए जेल में ठूंस देने और पुरानी इमारतों को नेस्तनाबूत करने जैसे कृत्यों से सरकार की छवि लगातार दाग़दार हो रही है, लेकिन वह इससे निकलने के बजाय उलझती जा रही है. प्रदेश में विकास का पहिया थम गया है. उद्योगपति राज्य में निवेश से डर रहे हैं. जनता बिजली-पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है.

मायावती सरकार के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना काफी कष्टदायक रहा. सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अंबेडकर सामाजिक समरसता स्थल पर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ताज़ कारीडोर मामले में मायावती और प्रदेश शासन के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस जारी किया. वहीं 18 सितंबर को इसी मामले की सुनवाई करते हुए जब सुप्रीमकोर्ट ने मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया तो प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सियासत गरमा गई. सुप्रीमकोर्ट ने मायावती और उनके मंत्रियों व अधिकारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ करने के लिए सीबीआई को निर्देशित किया. इससे पहले 11 सितंबर को सुप्रीमकोर्ट ने गोमती नगर स्थित अंबेडकर सामाजिक समरसता स्थल पर छह घंटे के अंदर काम बंद करने को कहा और मुख्य सचिव को नोटिस दे दी. मायावती सरकार ने काम रोकने का हलफ़नामा तो कोर्ट में दे दिया, लेकिन वहां काम रोका नहीं गया. बाद में सुप्रीमकोर्ट की फटकार के बाद पूरी तरह काम बंद हुआ. इससे पहले 8 सितंबर को सुप्रीमकोर्ट ने लखनऊ में कांशीराम, डॉ. अंबेडकर और मायावती की प्रतिमाएं लगाने पर 2600 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि ख़र्च करने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह करदाताओं के धन से ऐसे स्मारकों के निर्माण की संवैधानिक वैधता की जांच करेगी.

इसी बीच नोएडा में दलित नेताओं के नाम पर बन रहे पार्कों का मामला भी अदालत में पहुंच गया. 4 सितंबर को सुप्रीमकोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के रुख़ का समर्थन करते हुए एक समिति का गठन करने के बाद उसकी सिफ़ारिश पर नोएडा के भीमराव अंबेडकर पार्क का निर्माण कार्य रुकवा दिया. इसी दिन सुप्रीमकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मायावती सरकार को निर्देशित किया कि लखनऊ के आदर्श कारागार परिसर में स्थित जो मंदिर बचे हैं, उन्हें तोड़ा न जाएं. हालांकि बाद में इसकी इजाज़त दे दी गई.

भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला मौक़ा था, जब अदालत ने किसी राज्य सरकार को चेताया हो कि वह आग से न खेलें. बार-बार की अदालती फटकार ने बसपा सरकार को हिलाकर रख दिया है. 4 अक्टूबर को स्मारकों के निर्माण मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का रुख़ काफी कड़ा दिखा. अदालत को पता चला था कि मायावती सरकार ने हलफनामा देने के बाद भी वहां काम बंद नहीं किया था. न्यायमूर्ति बी एन अग्रवाल और न्यायमूर्ति आफ़ताब आलम की पीठ ने अवमानना के आरोप में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर लिया. पीठ ने मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि उन पर अदालती आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए. पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उच्चतम स्तर से निर्देश आए थे. यदि सरकार इसी तरह से नियमों का उल्लंघन करती रही तो निर्माणस्थल पर अर्द्ध सैनिक बलों को तैनात किया जा सकता है. अदालत ने चार नवंबर को मुख्य सचिव से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

मीडिया को धमकी

सुप्रीमकोर्ट में मिली फटकार की ख़बर जब बीती 7 अक्टूबर को अख़बारों में छपी तो प्रदेश सरकार के कान खड़े हो गए. उसने पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा को डैमेज कंट्रोल के लिए आगे बढ़ा दिया. एनेक्सी के मीडिया सेंटर पहुंचे मिश्रा के हावभाव बदले हुए थे. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में न्यूज़ चैनलों और समाचारपत्रों ने कोर्ट में हुई बहस के आधार पर ख़बरें बना दीं हैं. जबकि बहस के दौरान हुई टीका-टिप्पणी को आदेश नहीं माना जाता. उन्होंने कहा कि मीडिया एकपक्षीय रिपोर्टिंग कर रहा है. कोर्ट की बहस के अंशों के आधार पर विपक्षी दलों के नेता जिस तरह से मीडिया के ज़रिए उलजुलूल की बातें कर रहे हैं, वह मुख्यमंत्री की मानहानि और कोर्ट की अवमानना है. सरकार ऐसे मामलों में अवश्य कार्रवाई करेगी.

feedback@chauthiduniya.com

राहुल गांधी के झारखंड दौरे से युवा वर्ग में नई ताक़त का संचार हुआ है. संगठन को भी मज़बूती मिली है. चुनाव में पार्टी को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा. झारखंड चुनाव में राहुल गांधी फैक्टर काफी प्रभावी रहेगा और यहां राहुल का जादू चलेगा.

झारखंड में राहुल का जादू चलेगा : सुबोधकांत सहाय

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

झारखंड में चुनाव की घंटी किसी भी दिन बज सकती है. इस संभावना को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां अब ज़ोर पकड़ने लगी है. राहुल गांधी के झारखंड दौरे के बाद पार्टी अब पूरी तरह चार्ज नज़र आ रही है. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सुबोध कांत सहाय भी इन दिनों राज्य की जनता का दुख-दर्द सुनने में मशगूल हैं. सूबे की सियासत के बड़े खिलाड़ी सहाय का मानना है कि जनता कांग्रेस की तरफ़ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है. पिछली सरकारों के क्रियाकलापों से बेहद नाराज़ सहाय की राय है कि झारखंड को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो यहां की मूल समस्याओं को पहचाने और इसके समाधान के लिए अपना सब कुछ लगा दे. भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की ख़राब हुई छवि पर उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए जो सपना मैंने देखा था उसके पूरा न होने का मुझे दुख है, पर आने वाला दिन झारखंड का होगा. चुनावी मुद्दे व कांग्रेस की रणनीति पर भी उन्होंने ढेर सारी बातें कीं. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश–

आगामी विधान सभा चुनाव में कांग्रेस कितनी मज़बूती से चुनावी जंग में कूदेगी?

चुनाव मैदान में हमारी पार्टी पूरे दमखम से उतरेगी. राज्य में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है. संगठन की स्थिति मजबूत हुई है. पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से पार्टी को सबक मिला है. विधान सभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल एवं एनएसयूआई सहित अन्य सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट हो कर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार करेंगे. पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और उद्देश्यों को पार्टी कार्यकर्ता जन-जन तक पहुंचाएंगे. विकास के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जनता के बीच जाएगी.

चुनाव में राहुल गांधी फैक्टर कितना प्रभावी होगा?

देश के युवा राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं. राहुल गांधी के झारखंड दौरे से युवा वर्ग में नई ताक़त का संचार हुआ है. संगठन को भी मज़बूती मिली है. राहुल गांधी देश के युवाओं के प्रेरणास्रोत के तौर पर जाने जाते हैं. आने वाले विधान सभा चुनाव में पार्टी को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा. झारखंड चुनाव में राहुल गांधी फैक्टर काफी प्रभावी रहेगा, यहां राहुल का जादू चलेगा.

क्या कांग्रेस अन्य दलों के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी?

चुनावी गठबंधन के मुद्दे पर पार्टी आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि और सर्वमान्य होगा. वैसे तो प्रदेश नेतृत्व व झारखंड के प्रदेश प्रभारी द्वारा इस संबंध में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई है, लेकिन इस मुद्दे पर आलाकमान की मुहर नहीं लगी है. इतना साफ़ है कि कांग्रेस राज्य के विकास की अनदेखी करने वालों से कोई समझौता नहीं करेगी. विकास के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है. विकास के साथ कांग्रेस समझौता नहीं कर सकती. समान विचारधारा वाली पार्टियों से तालमेल किया जा सकता है. वैसे इस मुद्दे पर फ़ैसला पार्टी आलाकमान ही करेगा.

क्या कांग्रेस सीएम पद के लिए दावेदारी करेगी?

देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता की कमान ऐसे कर्मठ, ईमानदार जननेता को देने के पक्ष में है, जिसके नेतृत्व में राज्य के विकास का पहिया तेजी से घूम सके. विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अगर सफलता मिलती है और उसे यदि सरकार बनाने को आमंत्रित किया जाता है तो वैसी स्थिति में पार्टी चाहेगी कि सीएम की कुर्सी किसी दूरदर्शी राजनेता के हाथों में सौंपी जाए. कांग्रेस किसी भी व्यक्ति को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए सामने लाकर चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी. चुनाव के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर पार्टी आलाकमान आम सहमति से इस पर निर्णय लेगी.

कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या होगा?

आगामी चुनाव में झारखंड से भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाना तथा बेरोज़गारी दूर करना कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा. विकास योजनाओं के आधार पर कांगेस चुनावी मैदान में आएगी. विकास की दौड़ में झारखंड काफी पीछे छूट गया है. राज्य की जनता ने अगर जनादेश दिया तो कांग्रेसी सरकार यहां विकास का नया अध्याय लिखेगी.

जिस मक़सद से अलग झारखंड राज्य बना, वह पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है. इसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानते हैं?

इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ज़िम्मेदार है. भाजपाइयों ने जनहित में ऐसे एक भी सकारात्मक क़दम नहीं उठाए जिससे झारखंड का विकास हो सके. इसका ख़ामियाजा जनता आज तक भुगत रही है. भाजपा ने झारखंड में भ्रष्टाचार की नींव डाली. विकास की राशि का बंदरबांट हुआ. जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज़ किया गया.

राज्य के विकास के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए?

झारखंड के विकास के प्रति कांग्रेस पार्टी कृतसंकल्प है. विकास के लिए केवल ठोस नीतियां बनाना ही काफी नहीं, नीतियों का अनुपालन ज़रूरी है. विकास योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाना ज़रूरी है. योजनाओं के क्रियान्वयन में नौकरशाहों की लापरवाही के प्रति सख्त क़दम उठाया जाना चाहिए, तभी विकास का पहिया गति पकड़ेगा. इस दिशा में हमारी पार्टी की नीतियां काफी हद तक सहायक है. जनहित में केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां मील का पत्थर साबित हो रही है.

भ्रष्टाचार से राज्य की छवि ख़राब हुई है, इस पर आप क्या सोचते हैं?

बहुत दुख होता है जब कोई राज्य की स्थिति के बारे में पूछता है. इस राज्य के लिए जो सपना हमलोगों ने देखा था उसे कुछ भ्रष्ट नेताओं ने चूर-चूर कर दिया. सूबे की सरकार में शामिल निर्दलीय मंत्रियों की कारस्तानियां जगज़ाहिर हैं. निर्दलीय नेताओं ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दीं. अरबों रुपये की विकास की राशि को लूटने में मस्त रहे राजनेताओं पर अब क़ानूनी शिकंजा कसा जा रहा है.

झारखंड को आपके मंत्रालय से क्या लाभ मिला?

देश के अन्य राज्य मेरे मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं, मगर दुख की बात है कि कमज़ोर नेतृत्व के कारण झारखंड इस मामले में पीछे है. झारखंड के फल व सब्ज़ी उत्पादकों और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मंत्रालय द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. किसानों को उनके उत्पाद को बिचौलियों के पास कौड़ियों के भाव बेचने को विवश न होना पड़े और फल व सब्ज़ी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके, इस दिशा में मंत्रालय प्रयासरत है. फल व सब्जियों को संरक्षित रखने तथा उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने और बाज़ार की व्यवस्था कराने के उद्देश्य से राज्य में फूड पार्क की आधारशिला रखी गई है.

फ़र्ज़ी एनकाउंटर के आरोप में दारोगा जेल गए

राजकुमार शर्मा

सूबे की राजधानी देहरादून के बहुचर्चित रणवीर एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी दारोगा जी डी भट्ट और सिपाही को जेल तो भेज दिया है, लेकिन पुलिस की साख पर जो बट्टा लगा है, उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए. विदित हो कि बीती तीन जुलाई को देहरादून पुलिस ने रणवीर को एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया था. गाजियाबाद निवासी रणवीर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था. वह देहरादून स्थित जैन धर्मशाला में ठहरा हुआ था. रणवीर के पिता को उसकी पुलिस द्वारा हत्या किए जाने की ख़बर मीडिया से मिली थी. चार जुलाई को देहरादून के तत्कालीन एसएसपी अमित सिन्हा ने रणवीर के एनकाउंटर को जायज़ बताते हुए उसे एक अपराधी घोषित कर उसके परिवारीजनों के साथ दुर्व्यव्यहार भी किया था.

रणवीर के पिता रवींद्र पाल और भाई संदीप ने सूबे के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलकर उन्हें बताया कि एसएसपी का कथन सरासर झूठा एवं निराधार है. रणवीर पहली बार देहरादून आया था. उसका न तो कोई आपराधिक इतिहास है और न ही पुलिस से कोई अदावत. यह एनकाउंटर उस समय हुआ था, जब राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल देहरादून आई थीं. घरवालों का आरोप है कि पुलिस ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए रणवीर को मौत के घाट उतार दिया. प्रकरण की सीबीसीआईडी जांच के आदेश मुख्यमंत्री निशंक ने चार जुलाई को ही दे दिए थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी रणवीर की हत्या होने की पुष्टि कर दी थी. शासन ने प्रकरण में पुलिस की पैरवी करने वाले एसएसपी अमिताभ सिन्हा का तबादला करने के साथ ही 14 पुलिसकर्मियों को लाइन हाज़िर कर दिया था. इसके अलावा उन सभी पर रायपुर थाने में हत्या का मुक़दमा भी दर्ज़ किया गया. सबसे दुखद पहलू यह रहा कि देहरादून पुलिस के मुखिया ने इस मामले को सही ठहराने के साथ ही हत्या के आरोपी पुलिसकर्मियों की खुलेआम तारीफ़ करते हुए उन्हें सात हज़ार रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की थी. सिन्हा की इस घोषणा से देहरादून के नागरिकों एवं मीडिया में भूचाल आ गया था. इस घटना को जहां राष्ट्रपति ने खुद संज्ञान में लिया, वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सीबीआई जांच की मांग के समर्थन में उत्तराखंड बंद करने की घोषणा कर दी थी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ग़ाज़ियाबाद के सांसद राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री निशंक से इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने के लिए कहा था. आठ जुलाई को मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने के लिए पत्र लिखा था. 30 जुलाई को सीबीआई टीम देहरादून पहुंची और 31 जुलाई को उसने जांच शुरू भी कर दी. इस फ़र्ज़ी मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन न्यायमूर्ति बी सी कांडपाल ने सीबीआई को 22 अक्टूबर तक विवेचना की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश देते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया. अभी तक इस प्रकरण से जुड़े एक दर्ज़न पुलिसकर्मी सीबीआई के हत्थे नहीं चढ़ सके हैं. इस प्रकरण में मुख्य गुनहगार के रूप में दारोगा जी डी भट्ट को मीडिया ने चिन्हित किया था, जिसे जेल भेजकर सीबीआई ने जनता में अपना विश्वास पुख्ता कर लिया है. वहीं पूर्व एसएसपी अमित सिन्हा की सर्वत्र निंदा हो रही है. इस कांड से देहरादून पुलिस की मित्र पुलिस वाली छवि को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और जनसामान्य का विश्वास उससे उठ गया है.

रणवीर हत्याकांड

feedback@chauthiduniya.com

जिस तंत्र पर समाज की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है, अगर वही अपने कर्तव्य को भूलकर आतताइयों की भीड़ में जा खड़ा हो तो स्थिति का अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं.

रक्षक से भक्षक बन गई यूपी पुलिस

सुरेंद्र अग्निहोत्री

व्यायमूर्ति आनंद नारायण मुल्ला एक बार फिर याद आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में. आम आदमी उनके कथन को आज अक्षरश: सच होता अपनी आंखों से देख रहा है. कौन है इस स्थिति का ज़िम्मेदार?

यूपी में दलित उत्पीड़न के मामले सबसे ज़्यादा–सत्या बहन, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग. इलाहाबाद में चलती कार में युवती से सामूहिक दुष्कर्म. लखनऊ में बसपा पार्षद ने अभियंताओं पर तानी रिवॉल्वर. आढ़ती की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या. मेरठ में क्रिकेटर सहित दो की हत्या. पुलिस की अवैध वसूली के चक्कर में जीप पलटी, 12 घायल. बिजनौर में सिपाही और दारोगा ने एक दूसरे पर तानी बंदूक. बुलंदशहर के बर्खास्त सिपाही ने लूटे थे ठेकेदार से 13.5 लाख.

चौंकिए नहीं, यह खबरों के शीर्षक हैं, जो पिछले दिनों अखबारों के पन्नों पर प्रमुखता से दिखाई दिए. इन्हें देखकर आपके मन में भी एक सवाल उभर सकता है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है तो शासन में बैठे आला अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं? राजधानी लखनऊ में लापरवाही के आरोप में 42 पुलिसकर्मियों का निलंबित किया जाना कहीं न कहीं हमें डराता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि सूबे की पुलिस आखिर किस दिशा में जा रही है. पुलिस की पिटाई से लखीमपुर में एक दलित की मौत हो जाती है तो दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही कर दी जाती है, लेकिन शामली में महिलाओं के साथ अपनी मर्यादा लांघने वाले पुलिस अधिकारियों के मामले में चुप्पी कहीं न कहीं प्रदेश शासन पर सवालिया निशान लगाती है. जिन कंधों पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आज वे ही दमन चक्र चलाने को बेचैन हैं. इससे जहां एक ओर यूपी पुलिस का आंतरिक ढांचा कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वह जनता का विश्वास भी खोती जा रही है.

हरदोई जनपद की बघौली पुलिस ने मात्र आठ वर्ष के बच्चे जगन्नाथ पुत्र रज्जू पर गुंडा एक्ट लगा दिया. आगरा पुलिस ने मासूम इस्माइल को 36 घंटे तक बंधक बनाकर उसे मारा पीटा. कानपुर में जेके कॉटन मिल और एलएमएल के चार मज़दूरों पर रासुका लगा दी गई. इसी तरह जेपी चुनार सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों को दबाने के लिए पुलिस ने 23 कर्मचारियों पर रासुका लगा दी. लेकिन कमज़ोर नागरिकों पर अपनी बहादुरी दिखाने वाली यूपी पुलिस का दूसरा पहलू यह है कि उसके चार सौ जवान एक डाकू से तीन दिनों तक लोहा नहीं ले सके. पुलिस का असली चेहरा तो जेल के रिकॉर्ड में दर्ज़ है. यहां की विभिन्न जेलों में बंद हैं 375 पुलिस वाले. अपराधियों के दामन पर ख़ून की छीटें दिखें तो बात समझ में आती है, लेकिन यह हालत अगर खाकी वर्दी की हो तो स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं. प्रदेश भर में पुलिसिया तांडव बेधड़क जारी है. थाने बिक रहे हैं. यह कथन किसी ऐरे गैरे का नहीं है, बल्कि खुद यह आरोप सूबे की मुख्यमंत्री मायावती ने सार्वजनिक तौर पर यूपी पुलिस पर लगाया है. सच भी यही है कि गरीबों, किसानों और जरूरतमंद लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अपराध बेतहाशा बढ़ रहे हैं.

कुछ वर्ष पहले वाराणसी में एक डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने माफ़ियाओं से पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. विभाग की कलई खोलने वाले इस पुलिस अधिकारी को राजधानी में देर रात घर का दरवाज़ा तोड़कर गिरफ़्तार किया गया.

हरदोई के 65 वर्षीय मूलचंद की कहानी यूपी पुलिस के चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफी है. मूलचंद ने बताया कि भाई श्यामचरण उर्फ बल्ला, उसकी पत्नी और पुत्र 40 वर्षों से मेरी सेवा करते आ रहे हैं. मैं 65 साल का वृद्ध हूं. न जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए, यह सोचकर मैं अपनी जायदाद छोटे भाई श्यामचरण के नाम लिखाने तहसील संडीला गया. मैं अपना बयान सब रजिस्ट्रार को दर्ज़ कराने जा ही रहा था कि इतने में गांव के हींगा मुल्ला, विक्रम, रमेश, जनाका और दिलदार आदि आ गए. वे लोग मुझे मारपीट कर अपने साथ उठा ले गए. हंगामा होने की खबर पाकर मौके पर आई चौकी संडीला की पुलिस हींगा और बल्ला को थाने ले गई. थाने में पहले समझौते की कोशिश चलती रही, उसमें नाकाम रहने पर पुलिस ने हींगा और बल्ला का चालान कर परगनाधिकारी संडीला की अदालत में भेज दिया, ताकि मैं अपनी जमीन जायदाद छोटे भाई के नाम न कर सकूं. मवाना (मेरठ)में सठला–ततीना मार्ग पर मिले तीन शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के दावों की कलई खोल दी. पुलिस ने दंपत्ति और बालिका का शव मिलने के बाद उनकी मौत की वजह सड़क हादसा बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई है. पुलिस अधिकारी अब हत्याकांड के जल्द ख़ुलासे का दम भर रहे हैं. अति संवेदनशील इस क्षेत्र में तीन शव मिलने से पुलिस अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए थे. आईजी ज्ञानसिंह सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मवाना की तरफ दौड़ पड़े थे. फिर भी पुलिस इसे महज एक सड़क दुर्घटना बताकर अपना पल्ला झाड़ रही थी.

भूटान के चिरांग गोसलिग निवासी प्रताप सिंह के सबसे छोटे पुत्र यम बहादुर के साथ मथुरा पुलिस ने ऐसा सलूक किया कि लोगों की रूह कांप उठे. जयपुर स्थित मिशनरी कॉलेज से निकाले जाने के बाद यम बहादुर भटकता हुआ मथुरा पहुंच गया. यहां चोरों ने उसका बैग और पहनने के कपड़े चोरी कर लिए. मात्र अंडरवियर पहने इस युवक को पुलिस बदमाश समझ कर पकड़ ले गई. चार दिनों तक मथुरा कोतवाली में पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा. यम बहादुर नग्नावस्था में वहां बैठा रहा. किसी ने उसे पहनने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं दिया. यम बहादुर ने बताया कि वह बदमाश नहीं है, उसका सामान चोरी हो गया है. बाद में मीडिया की कोशिशों से उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सकी. घरवाले अपने बच्चे की यह हालत देखकर दंग रह गए. बड़ौत रेलवे स्टेशन पर पहले टिकट लेने के लिए हुए विवाद में पुलिसकर्मी और जीआरपी जवान आपस में भिड़ गए. जीआरपी ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर उन्हें हवालात में डाल दिया. बाद में जनता ने ही पुलिसकर्मियों को छुड़ाने के लिए रेलवे थाने का घेराव किया.

पुलिस के विरुद्ध बनारस में व्यापारियों द्वारा चलाए गए अनूठे आंदोलन ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस राह पर चल रही है. शहरों के चौराहे और तिराहे बेचती पुलिस वसूली के बाक़ायदा एंट्री पास भी जारी करती है, ताकि एक बार शुल्क चुकाने के बाद किसी को शिकायत न रहे. अंबेडकर नगर में गाएं पकड़ कर कसाई को सौंपने के मामले में तीन सिपाही निलंबित हो चुके हैं. महोबा में नशेबाज सिपाहियों ने एक पत्रकार को ही पीट दिया. गाज़ियाबाद में संतराम, फैज़ाबाद में रोहित और लखीमपुर में एक अन्य दलित पर कहर बरपाने वाली पुलिस के कारनामे अनंत हैं. प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भानु सहाय कहते हैं कि पुलिस में परिवर्तन की पहल आज की सबसे बड़ी जरूरत है. कुछ वर्ष पहले वाराणसी में एक डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने माफ़ियाओं से पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. विभाग की कलई खोलने वाले इस पुलिस अधिकारी को राजधानी में देर रात उसके घर के दरवाज़े तोड़कर पकड़ा गया. उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हृदय नारायण दीक्षित कहते हैं कि अंग्रेजी राज्य के बूढ़े पुलिस ढांचे पर भारत की आंतरिक सुरक्षा का दारोमदार है. कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव का कहना है कि क्षेत्रीय दलों के कारण राजनीतिक दबाव की जो नीति राजनेताओं ने प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में बनाई, उसी के चलते अपराधी मस्त और जनता त्रस्त है. इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदितराज कहते हैं कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन वह अपने स्वार्थ के चलते सत्ता की चेरी बन जाती है. जब तक देश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नज़र रखने वाला एक स्वतंत्र आयोग नहीं बनता, तब तक नागरिक अधिकार इसी तरह रौंदे जाते रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

राजस्थान के भरतपुर जिले के कई गांवों में सहकारी दुग्ध संग्रह केंद्र काम कर रहे हैं. इसका संचालन महिलाएं कर रही हैं और बख़ूबी कर रही हैं. इसने वहां के लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी. कल तक जो परिवार तंगहाली में जी रहा था, आज अच्छे पैसे कमा और ख़ुशहाल ज़िंदगी जी रहा है.

दूध संग्रहण केंद्र से ज़िंदगी हुई ख़ुशहाल

उमाशंकर मिश्र

सुबह का समय है. कई जगहों पर लोगों की लंबी कतार लगी है. सभी के हाथों में दूध के बर्तन हैं. दूध जमा कराने के लिए वे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. एक महिला वहां खड़े प्रत्येक व्यक्ति के लाए दूध को नापती है और उसमें वसा की मात्रा जांचने के लिए एक छोटी–सी परखनली में थोड़ा–सा दूध भर लेती है. यह क्रम प्रतिदिन चलता है.

राजस्थान के भरतपुर ज़िले के क़रीब 68 गांवों में यह नज़ारा हर दिन देखने को मिलता है. यहां महिलाएं सहकारी डेयरी, मदर डेयरी या महान प्रोटीन के दुग्ध संग्रहण केंद्रों का संचालन कर रही हैं. कुम्हेर तहसील के बौरई गांव की मनोरमा भी इन्हीं ग्रामीण महिलाओं की जमात का हिस्सा हैं. वह अपने गांव में ही पति सत्येंद्र की मदद से एक दुग्ध संग्रहण केंद्र का संचालन करती हैं. 12 बीघे ज़मीन के काश्तकार सत्येंद्र के परिवार में माता, पिता, पत्नी, बच्चों, भाई एवं भौजाई समेत कुल नौ प्राणी हैं. रेतीली ज़मीन, वर्षा पर निर्भर खेती–बाड़ी और उस पर सिंचाई सुविधाओं का घोर अभाव के चलते मुनाफ़ा बेहद कम हो पाता था. जैसे–तैसे निजी उपभोग के लिए अनाज तो मिल जाता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, आवागमन, अन्य पारंपरिक ख़र्च इत्यादि के लिए धन जुटाना उनके लिए बेहद मुश्किल भरा काम था.

मनोरमा के परिवार में बदलाव की कहानी तब शुरु हुई जब वह गांव में संचालित महिला समूह की सदस्य बनीं. कुछ समय बाद मनोरमा की सास भी ऐसी ही एक महिला समूह में शामिल हो गईं. यही नहीं उनके पति सत्येंद्र एवं ससुर सोहन सिंह भी अपने गांव बौरई में संचालित पुरुष समूहों के सदस्य बन गए. उल्लेखनीय है कि अकेले बौरई में महिलाओं के नौ और पुरुषों के दो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं. बौरई के सभी समूह मिलकर सीजन में दो सौ लीटर से ढाई सौ लीटर तक दूध इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे मनोरमा द्वारा संचालित दुग्ध संग्रहण केंद्र पर ले जाकर महिलाएं जमा करा देती हैं. वसा के मुताबिक़ निर्धारित दर से दूध का भुगतान महिलाओं को कर दिया जाता है.

सत्येंद्र बताते हैं कि यहां 18 रुपये से लेकर 29 रुपये प्रति लीटर तक दूध का भुगतान महिलाओं को किया जाता है. हालांकि मनोरमा और सत्येंद्र के लिए संसाधनों के अभाव में दुग्ध संग्रहण केंद्र के बारे सोचना भी सपने की तरह था. लेकिन लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की मदद से मनोरमा की राह आसान हो गई. इस संस्था द्वारा गांव में सबसे पहले स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया गया. दुग्ध संग्रहण केंद्र पर काम करने वाली महिला का चयन गांव में संचालित स्वयं सहायता समूह की सामूहिक बैठक में किया जाता है. इसके लिए ऐसी महिला का चयन किया जाता है जिसके पास कम से कम तीन–चार दुधारू पशु हों. यदि महिला कार्यकुशल हुईं तो उसे स्वयं सहायता समूह बनाने वाली लुपिन ह्यूमन वैलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन संस्था राष्ट्रीय महिला कोष अथवा एचडीएफसी बैंक के सहयोग से दुधारू पशु ख़रीदने के लिए ऋण उपलब्ध करा देती है. चयन के बाद लुपिन दुग्ध क्रय करने वाली संस्था के सहयोग से महिला को दुग्ध संग्रहण केंद्र संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिलाती है. मनोरमा समेत उनकी सास और भाभी तीनों को मिलाकर 75 हज़ार रुपये का ऋण राष्ट्रीय महिला कोष की ओर से स्वीकृत हो गया. यही नहीं, सत्येंद्र और उनके पिता सोहन सिंह को भी अपने समूह के मार्फत 15–15 हज़ार रुपये का ऋण मिल गया. इस पैसे से मनोरमा एवं सत्येंद्र ने चार गाय और तीन भैंसे ख़रीद लीं. इससे घर में ही क़रीब 35 लीटर दूध उत्पादन होने लगा.

मदर डेयरी द्वारा दिए गए चिलिंग प्लांट को रखने के लिए क़रीब सवा लाख रुपये की लागत से बिल्डिंग का निर्माण कराया गया. सत्येंद्र बताते हैं कि इस दुग्ध संग्रहण केंद्र पर सीजन के समय में क़रीब 800 लीटर दूध एकत्रित हो जाता है. घर में उत्पादित दूध से प्राप्त आमदनी के अलावा मनोरमा और उनके पति सत्येंद्र को 80 पैसे प्रति लीटर की दर से मदर डेयरी की ओर से कमीशन भी मिल जाता है. बिल्डिंग के किराए के रूप में मदर डेयरी सत्येंद्र को ढाई हज़ार रुपये का भुगतान करती है. इस तरह से उन्हें महीने में क़रीब 20 से 25 हज़ार रुपये की आमदनी होने लगी है.

दुग्ध संग्रहण केंद्र चलाने वाली महिला यह सारा कार्य सुबह के समय मात्र दो–तीन घंटे में पूरा कर लेती है. शेष समय में घर का कामकाज करती है. दुग्ध संग्रहण केंद्र चलाने वाली कुछ महिलाएं संग्रहण केंद्र पर पशु आहार एवं पशुओं से संबंधित अन्य उत्पादों की बिक्री भी करती हैं जिससे उनकी आय में और वृद्धि हो रही है.

भरतपुर ज़िले की कुम्हेर तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक महिला दुग्ध संग्रहण केंद्र संचालित हैं जिन्हें गांव की ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चला रही हैं. ये केंद्र नगला इंदू, कूम्हा, अवार, हिंगौली, बांसरौली, अस्तावन, बाबैन, बौरई, पला, गांगरौली, आजऊ, हेलक, सैंह, तमरेर, बैलाराकला, सैंत सहित 38 गांवों में राजस्थान सहकारी डेयरी फाउंडेशन अथवा मदर डेयरी के सहयोग से संचालित हैं. इसके अलावा कामां तहसील में गुरीरा, पथवारी, नेतवाड़ी सहित 23 गांवों में महान प्रोटीन डेयरी के सहयोग से, वैर तहसील में खिरनी, अतरामपुरा, चैंटौली, भोपर, नरहरपुर, जगवीनपुर, टूंडपुरा, नया बरखेड़ा, सीता सहित 18 गांवों में मदर डेयरी के सहयोग से महिला दुग्ध संग्रहण केंद्र संचालित हैं. दुग्ध संग्रहण केंद्र चलाने वाली महिलाओं की आय में वृद्धि होने से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है. इन महिलाओं ने आय वृद्धि के लिए और दुधारू पशु ख़रीदे हैं तथा बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना शुरू किया है. दुग्ध संग्रहण केंद्र संचालित करने वाली माया एवं कमलेश के कार्य को देखकर राजस्थान सहकारी डेयरी फाउंडेशन ने इन्हें करनाल (हरियाणा) में उन्नत पशुपालन प्रक्रिया की जानकारी दी है. पुरुषों के मुक़ाबले महिलाएं अधिक ज़िम्मेदारी एवं मेहनत से कार्य करती हैं, लेकिन काम उनकी क्षमता, योग्यता एवं पसंद के अनुरूप होना चाहिए. महिलाएं दुग्ध संग्रहण केंद्र को संचालित कर अपनी आय में वृद्धि कर रही है. ऐसे ही कृषि एवं पशुपालन आधारित अन्य कार्यों के संचालन की ज़िम्मेदारी महिलाओं को देकर उन्हें रोज़गार संचालन में भागीदार बनाया जा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

spice
www.spice-mobile.com
अब सब खल्लास!
मल्टी–सिम M-4580 की आकर्षक कीमत और भरपूर खूबियाँ करे सबको खल्लास।
M-4580
किलर खूबी: बड़ी बैट्री
25 दिनों का स्टैंड–बाइ टाइम और 10 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी–सिम (GSM/GSM)
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
वन–टच टॉर्च और करैन्सी चेकर
4 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 2149
M-5252
10 दिनों का स्टैंड–बाइ टाइम और 4 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी–सिम (GSM/GSM)
डिजिटल कैमेरा
बिल्ट–इन FM एंटेना
ड्यूअल LED टॉर्च
8 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 3049
C-5300
सभी CDMA कनेक्शन के साथ चले
बड़ी स्क्रीन
डिजिटल कैमेरा
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
एक्सपैन्डेबल मैमोरी
वन–टच टॉर्च
BEST BUY PRICE: Rs. 2999
बड़ी स्क्रीन | बड़ी मैमोरी | बड़ा साउण्ड | बड़ी बैट्री
big series
Spice Mobiles come loaded with:
emergic email2sms Mail on Mobile | Shuffle Ring tone | mGurujee | ibibo i build · i bond | REUTERS | Mobile Tracker
Registered Office: Spice Mobiles Ltd., D-1, Sector-3, Noida 201301, Uttar Pradesh, India. Fax: +91-120-4363845. E-mail: contactus@spicemobile.in. Spice Mobile Phones are available at all leading telecom outlets. *Conditions apply. Price features and specifications are subject to change without prior notice. Some of the listed capacity is used for phone functions and thus available capacity could be less than the quoted figure. Battery operation time may vary depending on network usage, environment, music and video formats.
www.itsaugust.com

एम जे अकबर

चुनाव भविष्य का आईना है

चुनावी विज्ञान में आंकड़े भ्रामक, व्याख्याएं आलोचनात्मक और सब कुछ अनिश्चित ही होता है. राजनीति एक विकासात्मक प्रक्रिया है और विकास एक सिद्धांत है, तथ्य नहीं. यहां तक कि डार्विन का विकासवाद भी. कोई भी चुनाव अतीत की प्रतिध्वनि नहीं होता है, यह सिर्फ़ भविष्य का आईना होता है.

शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), जो अपनी ही समस्याओं से जूझ रही है, उसे इस साल हुए आम चुनावों के आंकड़े पुष्ट नहीं करते. इन चुनावों में एनसीपी (19.3%) को कांग्रेस (19.6 %) जितना ही वोट मिला. जबकि एनसीपी का जनाधार पूर्व में कहीं अधिक था. 2004 के चुनाव में एनसीपी 18.8% वोटों के साथ कांग्रेस से भी अव्वल थी, वहीं कांग्रेस को 1.5% वोटों का नुक़सान झेलना पड़ा था.

और अब, सीटों का झुकाव भी विपरीत दिशा में गया है. कांग्रेस 2004 में मिली 69 सीटों की अपेक्षा 2009 में 79 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है तो एनसीपी 71 से सीधे 55 सीटों पर लुढ़क गई. आश्चर्य इस बात का है कि शरद पवार हर निर्वाचन क्षेत्र के आतंरिक ढांचे को नहीं समझ सके. जबकि वह अपना करिश्मा पहले साबित कर चुके थे. लोकतांत्रिक जीवविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण जीन के शानदार प्रबंधन से ही कांग्रेस को चुनावी आत्मविश्वास मिलता है. इसने अपना जनाधार एकजुट किया, जबकि शरद पवार का जनसमर्थन तितर–बितर हो गया. चुनावी भूगोल के लिहाज़ से ग़ैर–मराठी और मुसलमानों का वोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यह स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को मिला. नतीजतन, उसके उम्मीदवारों ने बढ़त बनाए रखी. कांग्रेस की यह मज़बूती उसे अगले विधानसभा चुनाव में भी मुंबई–पुणे–ठाणे की क़रीब 40 सीटें दिलाएगी. यदि एनसीपी के वोट में किसी तरह का बिखराव होता है, साथ ही यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि बिखराव की जगह वोटों का ध्रुवीकरण यदि एनसीपी के पक्ष में होता है तो इससे सीटों की संख्या में फेरबदल जारी रहेगा.

यह कम रोमांचक नहीं है कि गठबंधन की सीमा आंकड़ों के मुताबिक़ तय नहीं होती. आख़िर बीजेपी भगवा गठबंधन के छोटे सहयोगी के रूप में क्यों जानी जाती है? मई के आम चुनावों में इसे शिवसेना के 17% की अपेक्षा 18% वोट मिले थे. 2004 के बाद पिछले पांच सालों में सेना ने अपना जनाधार तीन फ़ीसदी खोया है, वहीं बीजेपी ने इस मामले में 4.5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हासिल की है. लेकिन, फिर भी सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में नहीं हुआ. दोनों ने 62 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बढ़त बनाई. यदि शिवसेना 2004 की तरह अपने वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखती तो निश्चित तौर पर संसद में इसकी संख्या अलग होती. राज ठाकरे का प्रभाव आप देख सकते हैं, जो सेना के तीन फ़ीसदी और अन्य पार्टियों के एक फ़ीसदी वोटों ...

आंकड़ों के लिहाज़ से क्षेत्रीय चुनावों की अपेक्षा राष्ट्रीय चुनावों की सटीक भविष्यवाणी करना ज़्यादा आसान है. इससे पहले देश के मतदाता केंद्र में स्थाई सरकार बना चुके हैं, लेकिन हित समूह और न्याय के मुताबिक़ महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य इतने असंगतित हो चुके हैं कि इनका सुसंगत विश्लेषण कर पाना बेहद ही मुश्किल है.

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

ख़तरे की घंटी, वहां भी और यहां भी

हिंदुस्तान में एक बार आतंकवाद और बेकसूरों की हत्या को लेकर आवाज़ उठी थी, पर अब आम लोगों को उठना होगा. आज पाकिस्तान का मुसलमान आतंकवादियों या तालिबानियों से घबराया हुआ है. कल यही हिंदुस्तान में होने वाला है. हिंदुस्तान के मुसलमानों को क़ुरान शरीफ़ की रोशनी में तालिबानी और आतंकवादी विचारों को जांचना परखना होगा और अपनी रणनीति तैयार करनी होगी.

संपादक editor.chauthiduniya.com

रवि किशोर

जानबूझ कर हुई लापरवाही निस्संदेह अपराध

पिछले अंक में आपने पढ़ा कि एक डॉक्टर की लापरवाही के लिए उसे दंडित करने का भी प्रावधान है, लेकिन उसकी हर चूक को लापरवाही मानकर उस पर मुक़दमा किया जाए तो वह अपने पेशे से कभी न्याय नहीं कर पाएगा. इस बार हम आपको बता रहे हैं कि आख़िर किन परिस्थितियों में डॉक्टर की चूक लापरवाही हो सकती है. साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या फ़ैसले दिए हैं.

चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित बुनियादी सिद्धांत को बोलाम नियम के तौर पर जाना जाता है. यह नियम जस्टिस मैक्नेयर द्वारा बोलाम बनाम फ्रायन अस्पताल प्रबंधन समिति के संदर्भ में दिया गया था. इसके मुताबिक़ सामान्य कुशलता वाले व्यक्ति और विशेष कुशलता वाले व्यक्ति के बीच जांच के स्तर के अंतर को स्पष्ट किया गया है. यह सर्वविदित क़ानून है कि यदि कोई शख़्स अपनी क्षमता के मुताबिक़ प्रदर्शन करता है तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त है, न कि उसे बहुत बड़ा विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत है.

इन सामान्य बातों से स्पष्ट है कि एक पेशेवर व्यक्ति को अपने पेशे से जुड़े सभी विषयों और उपकरणों की उतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, जो उस पेशे के लिए न्यूनतम ज़रूरत होती है. साथ ही, उसे अपने क्षेत्र में होने वाले सभी विकास और नई–नई खोजों से भी वाक़िफ़ होना ज़रूरी है. यदि किसी गंभीर बीमारी या इलाज के दौरान कोई डॉक्टर वैकल्पिक तरीके अपनाता है और इस दौरान कोई हादसा होता है तो चिकित्सक को सीधे तौर पर लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता. वह अपराधी तभी साबित हो सकता है, जबकि उसके द्वारा किए गए प्रयास अपेक्षाकृत लापरवाही भरे हों. उदाहरण के तौर पर, यदि चिकित्सक मरीज के शरीर में कोई सर्जिकल औजार छोड़ दे तो उसे दोषी माना जा सकता है. जैसा कि अच्युतराव हरिभाऊ खोडवा एवं अन्य ...

हर चूक लापरवाही नहीं है, लेकिन हर लापरवाही को भी निर्दोष नहीं करार दिया जा सकता. अगर जानबूझ कर ऐसा होता है तो संबंधित डॉक्टर को उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा. ऐसा क़ानून का मानना है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

सांप्रदायिक ताक़तों का कमज़ोर होना ज़रूरी है

सौमित्र मोहन

फोटो–प्रभात पाण्डेय

दरअसल, सांप्रदायिकता जैसे मसलों और इससे हमारे राष्ट्रवाद को होने वाले ख़तरे की जांच से पहले हर किसी को अपनी क्षमताओं, ख़ामियों, ख़ूबियों, दायित्वों और संपत्ति की बात अपने जेहन में रखनी चाहिए, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 के शुभ दिन अपनी आज़ादी को हासिल किया तो इसे अपने औपनिवेशिक शासक से न सिर्फ़ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, बल्कि सामाजिक तानावाना भी बिखरी अवस्था में मिला.

(लेखक प. बंगाल में आईपीएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

ध्यान दे शासन–प्रशासन

चितनीय है विषय

गांव, खेत और खलिहान

देवभूमि की दुर्दशा

ज्ञानवर्द्धक जानकारी

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

मोसाद अपने मिशन को बड़ी सफ़ाई से इस तरह अंजाम देता है कि उस पर शक़ भी यदि किया जाए तो उसके ख़िलाफ़ सबूत जुटाना मुश्किल ही नहीं, नामुकिन-सा लगता है.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

मोसाद की काली करतूत का काला चिट्ठा

इज़रायल का ख़ुफ़िया आतंक

इ से ख़ुफ़िया एजेंसियों की ख़ौफ़नाक दास्तां ही मानें कि वह हमेशा ऐसे अवसरों की ही तलाश में रहती है, जिससे पूरी दुनिया में दहशत क़ायम हो सके. कुछ ऐसा ही कहानी है, इस तेज़तर्रार और शातिर ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद की. जो हमेशा अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ऐसे अवसरों की फिराक़ में रहता है. इस बार तारीख़ थी, 14 फरवरी, 2005. जब दुनिया के कई देश वैलेंटाइन डे मना रहे थे. लेकिन एक ऐसा भी मुल्क था जो अपने मशहूर नेता की मौत का मातम मना रहा था. जी हां, हम बात कर रहे हैं, लेबनान के प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी की. 14 फरवरी 2005 को ही रफ़ीक हरीरी की सनसनीख़ेज़ हत्या की गई. लेबनानी प्रधानमंत्री की हत्या ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी. हर तरफ़ कयास लगाए जाने लगा कि आख़िर प्रधानमंत्री की हत्या की क्या वजह हो सकती है? कहीं यह सत्ता पलटने की साज़िश तो नहीं? कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि लेबनान के प्रधानमंत्री की हत्या की जा सकती है. वह भी तब, जबकि उनके आसपास सुरक्षा का चुस्त घेरा हर वक़्त मौजूद रहता हो. सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद होने के बावजूद रफ़ीक़ हरीरी की हत्या ने लेबनानियों के दिलों में ख़ौफ़ भर दिया. हालांकि, चर्चा का विषय तो यह भी था कि इसमें ज़रूर किसी न किसी विदेशी ताक़त का हाथ है.

लेबनान के प्रधानमंत्री रफ़ीक़ हरीरी.

शक़ की सूई तुरंत लेबनान के पड़ोसी देश सीरिया की ओर घूमने लगी. इसकी वाजिब वजह भी नज़र आ रही थी, उस वक़्त सीरिया के तक़रीबन 14,000 सैनिक लेबनान में अपना डेरा जमाए हुए थे, और सबसे अहम बात यह कि हत्या से पहले रफ़ीक हरीरी ने लेबनान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा भी इसी मसले पर दिया था. जी हां, वह मसला था, लेबनान के आंतरिक मामलों में सीरिया की बढ़ती दख़लंदाज़ी. दूसरी ओर, फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिरॉक ने भी रफ़ीक की बर्बर हत्या की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग कर दी. इसका नतीजा यह हुआ कि संदेह के दायरे में अब सीरिया बुरी तरह फंस चुका था. लेकिन, लेबनानियों और मध्य एशिया के दूसरे देशों की मानें तो रफ़ीक हरीरी की हत्या के पीछे सीरिया का हाथ नहीं था. शक़ की सूई पड़ोसी देश इज़रायल पर ही टिक रही थी. आख़िर, इस इलाक़े में चारों तरफ़ अरब देशों से घिरे होने के बाद ऐसी हिमाकत इज़रायल ही कर सकता था. लेबनानियों के इस शक़ को थोड़ा पुख्ता किया ईरान और सीरिया ने. जबकि सीरिया ख़ुद इस संगीन आरोपों के ज़द में था. इन दोनों देशों ने ख़ुलेआम आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी की हत्या इज़रायल ने ही करवाई है. वह भी अपने ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद के हाथों. मोसाद के हाथों रफ़ीक की हत्या की कई वजहें सामने आ रही थीं. इस हत्या से यदि किसी को सबसे अधिक फ़ायदा होता तो वह था, इज़रायल. राजनीतिक और सामरिक हर लिहाज़ से लेबनान के प्रधानमंत्री की हत्या इज़रायल के लिए काफी अहम थी. इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए, और साथ ही कई दूसरी वजहें भी थीं जिससे शक़ की ज़द में इज़रायल की ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद ही आ रही थी. हालांकि, पुख्ता तौर पर मोसाद पर यह आरोप लगाना मुमकिन नहीं था. उसके ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं थे. एक तरह से देखा जाए तो मोसाद की ख़ूबी भी यही रही है. वह अपने मिशन को बड़ी सफ़ाई से इस तरह अंजाम देता है कि उस पर शक़ भी यदि किया जाए तो उसके ख़िलाफ़ सबूत जुटाना मुश्किल ही नहीं, नामुकिन-सा लगता है. कुछ इसी तरह मोसाद ने लेबनानी प्रधानमंत्री की हत्या की साज़िश रची.

रफ़ीक की हत्या को अंजाम देने के लिए मोसाद ने अपने तीन शातिर एजेंटों की एक टीम बनाई. जिनका सबसे पहला मक़सद था, लेबनान की सीमा में दाख़िल होना. ताकि वो लेबनानी शहरों के चप्पे-चप्पे से वाक़िफ़ हो सकें. लेबनान की सीमा में घुसने के बाद इन तीनों एजेंट्स ने अपने मिशन को अंजाम देने की सारी कवायद शुरू कर दी. उन तीनों में एक एजेंट ने एक कार किराए पर लिया, तो दूसरे ने इस कार को 300 किलोग्राम विस्फोटों से लैस कर दिया. मतलब अब यह कार मौत का एक चलता-फिरता सामान बन चुकी थी. इससे ज़ाहिर है कि मोसाद के इरादे कितने नापाक़ और ख़तरनाक थे. ख़ैर, सुनियोजित प्लान के तहत, तीसरे एजेंट ने इस कार को बेरूत के एक होटल के सामने पार्क किया. यह वही रास्ता था जिससे रफ़ीक हरीरी हर सुबह अपने ऑफिस जाते थे. जब रफ़ीक इस रास्ते गुज़र रहे थे तब अचानक एक ज़बरदस्त धमाका हुआ. पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां में एक-एक कर धमाका होने लगा. धमाके की तीव्रता इतनी थी कि कई गाड़ियां सामने की होटल में तीन मंजिले पर जाकर गिरी. इस दर्दनाक हादसे में कुल 14 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, जिनमें एक लेबनान के प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी भी थे. क़रीब 135 लोग बुरी तरह ज़ख्मी हो गए. इस धमाके के असर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस विस्फोट की वजह से आसपास की सड़कों में 15 फुट गहरी और 44 फीट चौड़ी खाई बन चुकी थी. उसके बाद तो पूरी दुनिया में रफ़ीक की हत्या से सनसनी मच चुकी थी. लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम सवाल यह था कि आख़िर लेबनानी प्रधानमंत्री की हत्या से इज़रायल को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर क्या फ़ायदा होता?

दरअसल, रफ़ीक हरीरी लेबनान की राजनीति में एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे. साथ ही, वह मध्य एशिया में लेबनान को एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर स्थापित करना चाहते थे ताकि, लेबनान भी दुनिया में एक अहम देश के तौर पर शुमार हो सके. यहीं से इज़रायल के लिए परेशानियां शुरू होने लगी थीं. यदि रफ़ीक अपने इस मक़सद में सफल हो जाते तो इज़रायल अब तक अरब देशों में आतंकवाद के प्रश्रय के नाम पर जो मनमानी करता आ रहा था, उस पर अंकुश लग जाता. उसके मुताबिक़, इसका सीधा असर इज़रायली यहूदियों की सुरक्षा पर पड़ता. वह चारों तरफ़ से अरब राज्यों से घिर जाता. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हरीरी जैसे नेताओं द्वारा लेबनान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर इज़रायल तिलमिला गया. साथ ही, हरीरी के इस क़दम से मोसाद इन इलाक़ों में इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर अपनी ग़ैर-ज़िम्मेदार ख़ुफ़िया गतिविधियों को अंजाम भी नहीं दे सकता था. ऐसा करने पर वह सवालों के घेरे में तो आता ही, इज़रायल पर भी अंतरराष्ट्रीय शिकंजा कसने लगता और मध्य एशिया में इज़रायल की पकड़ कमज़ोर हो जाती. इज़रायल इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था. अपने इसी दबदबे को क़ायम रखने के लिए इज़रायल ने रफ़ीक हरीरी को रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया है. इस मिशन की ज़िम्मेदारी इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद को दी गई और मोसाद ने अपने इस मिशन को बख़ूबी अंजाम दिया.

मोसाद का यह मिशन इतना चालाकी भरा था कि रफ़ीक की हत्या के बाद भी गुनहगारों को लेकर भ्रम का माहौल बना रहा. कोई सीरिया पर आरोप लगा रहा था तो कोई इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग कर रहा था ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके. दरअसल, मोसाद की ख़ासियत भी यही है वह अपने मिशन को इतनी सफ़ाई से अंजाम देता है कि शक़ की गुंज़ाइश ही नहीं बचती. कुछ इसी तरह मोसाद ने लेबनानी प्रधानमंत्री को इज़रायल के रास्ते से हटाया. मोसाद की यह कहानी उसके शातिराना चाल और ख़ौफ़ की कहानी है. इससे एक बात तो ज़ाहिर है इज़रायल के रास्ते में आने वाले किसी भी कांटे को मोसाद पलक झपकते ही साफ़ कर देता है और आरोपों से भी बड़ी सफ़ाई से बच निकलता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

ग़लती से बने करोड़पति

अ हमदाबाद का एक शख़्स रातोंरात करोड़पति बन गया. सुनने में तो यह बात किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रही है, लेकिन बात सौ फ़ीसदी सच है. धनतेरस के दिन भाग्य ने जुगल किशोर का पूरा साथ दिया. कहते हैं न, भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. मगर इस शख़्स ने लालच की जगह ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे पढ़कर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.

जुगल किशोर कारपेंटर का काम करते हैं. उनके साथ और स्टाफ भी इस काम में लगे हुए हैं. दरअसल हुआ यह कि जुगल किशोर क्लॉथ मार्केट के नज़दीक पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गए थे, ताकि स्टाफ को दीवाली के पहले ही पैसे दे दिए जाएं. लेकिन जब उन्होंने अपने खाते में कुल जमा धनराशि देखी तो वह आश्चर्य में डूब गए. उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. उनकी जमा धनराशि 2.5 लाख से अचानक 59 करोड़ रुपये हो गई थी. यह रक़म उनके खाते में कहां से आई, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी. एक बार उन्हें भी लगा कुछ न कुछ गलत जरूर है, इसलिए वह दूसरे एटीएम गए. लेकिन वहां भी जांचने पर खाते में उतनी ही रकम मिली. इसके बाद वह इतना डर गए कि अपने स्टाफ को देने के लिए 20 हज़ार रुपये भी नहीं निकाल पाए.

वह मूल रूप से जयपुर के देवेन गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 13 वर्षों से वह अहमदाबाद में रह रहे हैं. उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त अनुज से संपर्क किया और उन्हें सारी कहानी बताई. अनुज उन्हें चार्टर एकाउंटेंट पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पास लेकर गया. यह सुबह की घटना थी और बैंक चूंकि दस बजे खुलता है इसलिए सलाह मशविरा करने के लिए उनके पास काफी वक़्त था. खंडेलवाल ने उन्हें दुर्गेश बुच के पास जाने की सलाह दी, जो चार्टर एकाउंटेंट के साथ-साथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री केएक्जक्यूटिव मेंबर हैं. उन्हें इसकी सूचना तुरंत पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी को दी. आनन फानन में बैंक के अधिकारी ने यह सूचना दिल्ली हेडक्वार्टर को दी. तब पता चला कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण इतनी बड़ी रक़म उनके खाते में चली गई थी. हालांकि बैंक के अधिकारी ने एटीएम ऑपरेट नहीं करने के लिए उनकी तारीफ भी की. वैसे जीसीसीआई इसके लिए उन्हें सम्मानित करने का मन बना रही है.

कचरे और भूसे से रासायनिक ईंधन बनेगा!

जै व वनस्पति तेल से बायो एथानोल और बायो डीजल का उत्पादन हो तो रहा है. मगर, प्रकृति में इसकी मात्रा बहुत सीमित है, सिर्फ़ एक प्रतिशत. इसलिए इसके ख़त्म होने की चिंता शोधकर्ताओं को सता रही है. अब उनकी नज़र अन्य जैव पदार्थों पर है. अब वे लकड़ी के कचरों से, भूसों से, सोया के अवशेषों से और गन्ने के सीरे से रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करना चाहते हैं. इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक जैसे तत्व मिलते हैं.

हालैंड के डेल्फट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वीब्रेन डे योंग का कहना है कि जैव पदार्थ के तीन महत्वपूर्ण अंग है. पहला सेल्यूलोज, जिससे काग़ज़ बनाया जाता है. दूसरा लिगनिन, जो जैव पदार्थों को जोड़ने वाली लेई की तरह होती है और तीसरा महत्वपूर्ण अंग है हेमिसेल्यूलोज. जैव पदार्थों में इसकी मात्रा लगभग एक तिहाई के बराबर है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर अब तक शोध सबसे कम हुआ है. अधिकतर वैज्ञानिक सेल्यूलोज से बायो एथानाल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. हालांकि हेमिसेल्यूलोज के अणु भी सेल्यूलोज की तरह ही होते हैं. इसमें माड़ी, जिसे फरफराल कहा जाता है, नहीं होती है. और अपने मूल रूप में यह एक पीला तरल पदार्थ होता है.

प्रोफेसर डे योंग कहते हैं कि नए सिंथेटिक ईंधन के उत्पादन में यह काफी कारगर हो सकता है. हालांकि अमेरिकी वैज्ञानिक इस विषय पर काम कर चुके हैं. बायो एथानोल और बायो डीजल के विपरीत इस नए ईंधन से लाभ यह होगा कि इसमें वनस्पति तेल जैसे उन पदार्थों का उपयोग नहीं होगा, जिनकी खाद्य पदार्थ के रूप में ज़रूरत होती है. हेमिसेल्यूलोज को खाया नहीं जाता है.

पशु प्रेम में पत्नी ने पति को छोड़ा

क्या कोई पति और पत्नी किसी एक के पशु प्रेम के चलते एक दूसरे को छोड़ सकते हैं? शायद आपका जवाब नहीं में हो सकता है, लेकिन सिडनी में ऐसा ही हुआ है. पति ने पत्नी के सामने ऐसी शर्त रख दी कि वह मजबूर हो गई और अंत में पति की जगह जानवर को चुना.

विकी लोइंग अपने पूरे परिवार के साथ सिडनी में रहती है. जानवरों से उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव है. एक मगरमच्छ से उसे इतना प्यार हो गया कि विकी ने अपने पति को त्याग दिया. विकी के मगरमच्छ प्रेम से उनके पति ग्रेग बहुत परेशान थे. एक दिन उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो विकी ने मगरमच्छ को चुना. दरअसल यह मगरमच्छ उन्हें 13 साल पहले घर के बाहर मिला था. तब से वह उसे अपने साथ ही रख रही हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि वह मगरमच्छ उनकी बिल्ली के साथ टीवी भी देखता है और उनके बेटे के साथ सोता भी है.

क्यूं है न हैरानी वाली बात! इसे आप क्या कहेंगे, प्यार में अंधा हो जाना या जानवर के प्रति विशेष लगाव!! ख़ैर आप जो भी कहें हम तो यही कहेंगे कि उसने पशु- प्रेम के चलते पति को कुर्बान कर दिया. विकी पेशे से नर्स हैं. इस पर उनका क्या कहना है ज़रा गौर फरमाइए, उन्हें पति को छोड़ने का तनिक भी दुख नहीं है. वह कहती हैं पति तो अपना ध्यान रख सकता है, लेकिन जानवर नहीं. देखभाल की जरूरत पति से ज्यादा जानवर को होती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

हकीमुल्लाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कैसे ख़ुद को बैतुल्लाह का सही और बेहतर वारिस साबित करे. इसके लिए उसे ख़ुद को तालिबान का अकेला नेता साबित करना होगा.

पाकिस्तान में लोकतंत्र पर मंडराता ख़तरा

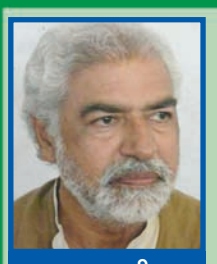

अयाज़ अमीर

अमेरिकी सीनेट के कैरी लूगर विधेयक से भले ही पाकिस्तान अमेरिका संबंध बरक़रार रहे, पाकिस्तान में लोकतंत्र (ख़ासतौर पर फरवरी 2008 के बाद की स्थिति को देखकर) ख़तरे में है. हालांकि इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान में लोकतंत्र को मज़बूत करना बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इस विधेयक को लेकर कवायद चल रही है और हमारे राजनेता और कूटनीतिज्ञ इस विधेयक को पैर–पसारने का मौक़ा दे रहे हैं, उससे साफ़ है कि एक दिन पाकिस्तान का लोकतांत्रिक ढांचा रेत से बने महल की तरह गिर जाएगा. लिहाज़ा, हमें एक बार फिर ऐसे विधेयक के बारे में सोचना होगा, जिसका नतीजा ख़ुद हमें भुगतना पड़ सकता है.

कैरी लूगर विधेयक पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना मुख्यालय के बीच तनाव का एकमात्र प्रमुख कारण नहीं है. तनाव इस विवाद के पहले से है और शक्ति और सत्ता के इन दोनों केंद्रों के बीच बढ़ते अविश्वास पर आधारित है. और कैरी लूगर विधेयक से यह अविश्वास खुलकर सामने आ गया है. आज इन दोनों केंद्रों के बीच समन्वय का दिखावा ख़त्म हो चुका है और व्यवहारिकता को भी तरज़ीह नहीं दी जा रही है– अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है कि आंतरिक मंत्री रहमान मलिक को सेना मुख्यालय में जाने से रोक दिया गया(जबकि वह मुख्यालय पर हुए आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे) तो क्या दोनों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं?

अमेरिकी सिनेटर कैरी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री के जारी साझा बयान से कुछ बदलने वाला नहीं है. यह बयान इस विधेयक में प्रस्तुत एक उपाय को समझाने की कोशिश है और क़ानूनी तौर पर इस बयान की अहमियत इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में बीस रुपये के स्टैंप पेपर पर दिए हलफ़नामे से ज़्यादा नहीं है. ऐसा क्यों है कि हमारे विदेश मंत्री अमेरिकी बिचौलियों से इतना ज़्यादा प्रभावित दिख रहे हैं. जब पहली बार कैरी लूगर विधेयक को सीनेट में पारित किया गया था तो विदेश मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया. सच्चाई यह है कि अगर ख़ुद विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में इस विधेयक पर रुख़ भांपने की कोशिश की होती तो शायद वे इसे इतनी बड़ी उपलब्धि न मान रहे होते. एक बार फिर विदेश मंत्री अपने इस बयान के ज़रिए अपनी क़िस्मत आज़माने की कोशिश कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक करार दे रहे है. इज़राइल, अमेरिका का निकटतम सहयोगी है, लेकिन कोई भी इज़राइली अधिकारी ऐसा बर्ताव नहीं करता है.

अगर हम किसी तरह के ख़ुद को बचाने का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें अगर सेना के हुक्मरान भी शामिल हैं तो कैरी लूगर विधेयक पर उत्साहित हो सकते हैं. लेकिन यह हक़ीक़त नहीं है. सेना के संपर्क में रह रहे पत्रकार मित्रों की बात मानें तो मामले काफी गंभीर हैं. ख़ासतौर पर ऐसे वक़्त में जब सेना की राष्ट्रभक्ति अपने चरम पर है. ऐसा संभव है कि मैं ख़तरे को ज़रूरत से ज़्यादा भांप रहा हूं. लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात नाज़ुक हैं और अगर राजनीतिक वर्ग(पोलिटिकल क्लास) नहीं चेता तो हालात और भी ख़राब हो सकते हैं. आख़िर सेना मुख्यालय का राष्ट्रपति से प्रमुख मतभेद क्या है? जबकि माना जाता है कि राष्ट्रपति और सेना का अमेरिका से रिश्ता एक जैसा है और दोनों के ही पास अमेरिका से संवाद का अपना स्वतंत्र ज़रिया है. लेकिन फिर भी सेना को किसी ख़तरे का अंदेशा है जो उसकी नाराज़गी की वजह बन रही है.

सवाल उठता है कि आख़िर सेना, जिसकी ज़िम्मेदारी सरहद से ज़्यादा विचारधारा की रही है, इतनी परेशान क्यों है? सेना के बीच रह रहे सूत्रों के मुताबिक़, सेना मुख्यालय में दो बातों को लेकर आशंकित है. पहला, पाकिस्तान में अमेरिकी ष्ठ्फिया तंत्र सीआईए की बढ़ती पैठ– जहां कई अमेरिकी व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं और किसी को इसके बारे में पता नहीं है और दूसरा यह कि ये गतिविधियां पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम पर ख़तरा बन सकती हैं.

इससे लगता है कि कैरी लूगर विधेयक पर सेना की आपत्ति राष्ट्रीय सम्मान या संप्रभुता के लिए नहीं है, बल्कि इस बात के डर से है कि इस विधेयक की आड़ में सीआईए पाकिस्तान में अपनी मज़बूत पैठ बना सकता है और पाकिस्तान के नाभिकीय हथियार ख़तरे में पड़ सकते हैं. जहां एक तरफ दुनियाभर में यह ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान के नाभकीय हथियार तालिबान के हाथ लग सकते हैं वहीं सेना मान रही है कि पाकिस्तान के हथियारों को अगर किसी से ख़तरा है तो वह मित्र की आड़ में आने वाले उसके रक्षकों से ही है.

सेना के इस आशंका के पीछे एक और सच्चाई है. इससे पहले अमेरिका से मिलने वाली सभी मदद सेना की संपत्ति रही है, चाहे वह अयूब ख़ान का दौर रहा हो या जनरल जिया उल हक या फिर परवेज़ मुशर्रफ़ का. मदद का यह सिलसिला पहली बार लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है और सेना को पाकिस्तान के लोकतंत्र में कभी भी भरोसा नहीं रहा है. पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने पाकिस्तान में अमेरिकी दष्ठ लंदाज़ी के लिए दरवाज़े खोल दिए थे. यह बात अलग है कि आज हमको पता चल रहा है कि मुशर्रफ़ ने अमेरिका को कितनी रियायतें दी थीं. पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर अमेरिका को बिना किसी जांच के घुसने की इजाज़त थी. इस्लामाबाद में मौजूद सीआईए स्टेशन दुनियाभर में सबसे बड़ा सीक्रेट स्टेशन है. सीआईए को दी गई मदद के लिए अगर इस्लामाबाद स्टेशन पर किसी की मूर्ति लगी तो यकीनन वह मूर्ति पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की होगी.

यह सोचना कि सेना ने मुशर्रफ़ को आठ साल तक क्यों बरदाश्त किया और वहीं मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी को एक साल के बाद ही नकारने लगी है. ज़ाहिर है कि सेना मुख्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा को भांपने के लिए अलग–अलग पैमाने हैं– एक तरफ जहां सेना का शक्तिशाली नेतृत्व है वहीं दूसरी तरफ जब लोकतंत्र मौत के मुंह में है. ज़रदारी एक निर्वाचित राष्ट्रपति हैं– इसमें कोई विवाद नहीं है. लेकिन उनकी कमज़ोरी पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए ख़तरा है. अगर जरदारी को सत्ता पर कायम रहना है और पाकिस्तान में लोकतंत्र को बचाना है तो ज़रदारी को अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाना होगा. ख़ुदा की मंशा भले न हो, लेकिन संकट के बादल कुछ बलिदान की मांग कर रहे हैं और इन बादलों को ख़ुश करने के लिए कुछ बलि देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है. सेना मुख्यालय और लाहौर के पुलिस ठिकानों पर हाल में हुए आतंकी हमलों से साफ़ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ही नाज़ुक बन चुके हैं. इन आतंकी हमलों का यही मतलब निकाला जा सकता है कि लोकतंत्र के दिन लद चुके हैं और तालिबान एक एकीकृत नियंत्रण के अधीन आ रहा है. मुशर्रफ़ के अधीन नियंत्रण की ऐसी ही एकीकृत व्यवस्था थी, और हम देख ही रहे हैं कि यह हमें कहां ले आया.

(लेखक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और नेशनल असेंबली के सदस्य हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

इस धमकी को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

पाकिस्तान में जारी आतंकी हमलों के बीच तहरीक–ए–तालिबान के चीफ हकीमुल्लाह मेहसूद ने भारत को चेतावनी दी है. उसने कहा है कि पाकिस्तान के बाद उसके निशाने पर भारत होगा. हाल में हुए सीरियल ब्लास्ट के पीछे आंतकवादी संगठन तहरीक–ए–तालिबान का हाथ है. एक टेलीविज़न चैनल पर हकीमुल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के बाद वह जिहाद और तालिबानी लड़ाकों का रुष्ठ कश्मीर की ओर कर देगा. हकीम्मुल्लाह के इस बयान के पीछे क्या राज़ है? वह भारत को चुनौती क्यों दे रहा है?

हकीम्मुल्लाह पाकिस्तान में आंतकी नेटवर्क का नया सरगना है. कुछ दिन पहले तक तहरीक–ए–तालिबान का मुखिया बैतुल्लाह मेहसूद हुआ करता था. अमेरिका सेना ने द्रोन हमले में उसकी हत्या कर दी. जिसके बाद हकीम्मुल्लाह इसका नया सरदार बना. बैतुल्लाह ने अफगानिस्तान से सटे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को अपना गढ़ बनाया था. यहां बैतुल्लाह की हुकूमत चलती थी. बैतुल्लाह की मौत और हकीमुल्लाह के हाथ तालिबान की कमान आने के बाद दक्षिणी वजीरिस्तान तालिबान का गढ़ बन गया है. हकीमुल्लाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कैसे ख़ुद को बैतुल्लाह का सही और बेहतर वारिस साबित करे. इसके लिए उसे ख़ुद को तालिबान का अकेला नेता साबित करना होगा साथ ही पाकिस्तान और अमेरिकी सेना के हमलों के बीच तालिबान को मज़बूत करना होगा. अभी तक वह पाकिस्तानी सेना की पकड़ से दूर है. पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं उससे तो यही लगता है तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान में बिना किसी रोकटोक के कहीं भी आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है. पहले संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय और फिर लाहौर में सेना व पुलिस के गढ़ पर आतंकी हमलों को अंजाम देकर हकीमुल्लाह ने यह साफ़ करने की कोशिश की है कि तालिबान पाकिस्तान में किसी भी जगह और कभी भी हमला कर सकता है. हैरानी की बात यह है कि पिछले पंद्रह दिनों में किए गए हमलों के बारे में तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को पहले से चेतावनी भी दे रखी थी. हकीमुल्लाह ने यह घोषणा की थी कि दक्षिणी वजीरिस्तान में अगर पाकिस्तानी सेना हमला करने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब आतंकवादी हमलों से दिया जाएगा. हकीमुल्लाह के मंसूबे इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वह यह भी दावा करने लगा है कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए तालिबान का मोहताज है. हकीमुल्लाह के इन बयानों से साफ़ लगता है कि वह पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिकी आदेशों पर चल रही है, इसलिए तहरीक–ए–तालिबान

बैतुल्लाह मेहसूद हुआ करता था. अमेरिका सेना ने द्रोन हमले में उसकी हत्या कर दी. जिसके बाद हकीम्मुल्लाह इसका नया सरदार बना. बैतुल्लाह ने अफगानिस्तान से सटे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को अपना गढ़ बनाया था. यहां उसकी बैतुल्लाह की हुकूमत चलती थी.

का जिहाद न सिर्फ़ सही है, बल्कि जनता भी उसके साथ है. वह ख़ुद को पाकिस्तान में जिहाद का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहता है. यही वजह है कि वह पश्चिमी देशों के ठिकानों और पाकिस्तान की सत्ता के प्रतीकों को अपना निशाना बना रहा है.

यहां सवाल यह उठता है कि हकीमुल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को क्यों निशाना बना रहा है? दरअसल पाकिस्तान में कई रंग के तालिबान पैदा हो गए हैं. पंजाब में दो तरह के आतंकी संगठन सक्रिय हैं. एक वो जिनका वास्ता अंतरराष्ट्रीय जिहाद से है. ये अलकायदा जैसे संगठन के नज़दीक और अफ़गानिस्तान और फिलीस्तीन के मुद्दों को लेकर जिहाद चलाते हैं. दूसरे क़िस्म के आंतकी संगठन वे हैं जो भारत के ख़िलाफ़ ज़हर घोलते हैं और जो कश्मीर को आतंकवाद की गर्त में ढकेलने के लिए ज़िम्मेदार हैं. इन्हें पाकिस्तान की सरकारी एंजेसियों की मदद मिलती है. फिलहाल, इन संगठनों की गतिविधियों पर अमेरिकी दबाव के चलते ये खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं. पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इन संगठनों के साथ मिल कर आतंकवादियों को भारत भेजती है. इनमें से कई संगठन प्रतिबंध के बाद नए स्वरूप और नए नाम के साथ सामने आ रहे हैं. इनका नेतृत्व करने वाले आतंकवादी, तालिबान के साथ गठजोड़ बनाकर काम करने लगे हैं. दक्षिणी पंजाब में बेरोज़गार युवाओं को गुमराह करके आतंकवाद की आग में ढकेलने की पूरी इंडस्ट्री तैयार हो चुकी है. पंजाब प्रांत शुरू से ही भारत विरोधी संगठनों का गढ़ रहा है, लेकिन यहां तालिबानी तंजीम की पकड़ कभी मज़बूत नहीं हुई. आज पंजाब के आतंकवादियों को तालिबानी तंजीम से कोई गुरेज नहीं है. जहां सरकार अमेरिकी दबाव में आकर आतंकी संगठनों पर लगाम कस रही है वहीं इन संगठनों के बीच तरहीक–ए–तालिबान ने उन्हें फिर से जगा दिया है. हकीमुल्लाह मेहसूद अच्छी तरह जानता है कि महज अमेरिका के खिलाफ बातें करके और पाकिस्तनी सेना और पुलिस से जंग लड़कर उसे पाकिस्तान की जनता का साथ नहीं मिल सकता है. पंजाब के आतंकी संगठनों का हाथ पकड़ कर वह सेना के साथ लुकाछिपी के खेल में अपना दायरा बढ़ा लेगा. कश्मीर मामले को तालिबानी तंजीम में जोड़ने से उसे पाकिस्तान में मौजूद भारत विरोधी संगठनों का साथ मिल जाएगा. यही वजह है कि हकीमुल्लाह की धमकी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता की विरोध के बावजूद वहां ऐसी घटनाएं घटित हो रहीं हैं जो भारत के लिए ष्ठ तरनाक साबित हो सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फोटो– पीटीआई

चौबीस घंटे सक्रिय रहने वाले समाज का अंग बनने की प्रक्रिया में लोगों को अपनी नींद में कटौती करनी पड़ रही है.

क्यों नहीं आती नींद

रीतिका सोनाली

आज के युग में वह शख्स क़िस्मत का धनी है, जिसे अच्छी नींद आती हो. अनियमितता इस भागदौड़ वाली जीवन की सच्चाई हो गई है, जो नींद न आने का मुख्य कारण है. देर तक काम, पार्टीबाजी, पढ़ाई, लेखन या चित्रकारी, इंटरनेट सर्फिंग, चैटिंग एवं अन्य व्यक्तिगत शौक़ पूरे करने व फोन पर बने रहने वाले और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से तंग आ चुके लोगों की नींद लेने का वक़्त कम होता जा रहा है. चौबीस घंटे सक्रिय रहने वाले समाज का अंग बनने की प्रक्रिया में लोगों को अपनी नींद में कटौती करनी पड़ रही है.

विभिन्न शोधों की ओर रूख़ करें तो अच्छी और पर्याप्त नींद लेने के फ़ायदों का पता चलता है. दिल्ली स्थित रॉकलैंड अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. एस सुदर्शनन के मुताबिक़, सोते वक़्त कई प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं जिससे शरीर की सारी थकान, तनाव और आलस्य दूर हो जाता है. यदि प्रतिदिन सुकून भरी नींद न ली जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हर उम्र के व्यक्ति के लिए सोने का अलग-अलग उपयुक्त समय होता है. छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा लगभग 16 से 18 घंटे सोते हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, नींद भी कम होती जाती है. वयस्क के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है.

सोने का समय

यूं तो किसी भी वक़्त सोना अच्छा लगता है, लेकिन एक शोध के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय सोने के लिए उपयुक्त है. इसकी वजह है कि हमारे शरीर में 'मेलाटोनीन' नामक हार्मोन सबसे ज़्यादा इसी समय सक्रिय होते हैं, जिससे बहुत आरामदायक नींद आती है. 10 से 6 की नींद में जितना वक़्त आप सोएंगे, उतनी आपकी 'क्वालिटी स्लीप' होगी. इसलिए सोने का यह वक़्त तय कर लें और दुनिया भुलाकर सोएं.

बेफ़िक्र नींद

नींद का मतलब सिर्फ़ थकान मिटाने का एक ज़रिया भर नहीं है. यह हमारे दिमाग़, शरीर और आत्मा को भी सुकून पहुंचाती है. एक निश्चिंत और बेफ़िक्र नींद आपको अगले ख़ूबसूरत दिन के लिए तैयार करती है. आप अपना काम बेहतर ढंग से ध्यान लगाकर कर सकते हैं. भरपूर नींद आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर सिरदर्द की बीमारी से छुटकारा दिलाती है.

ज़्यादा सोना

नींद लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप हर वक़्त सोते रहें या हर वक़्त आपको नींद आती रहे. यह एक ग़लत संकेत हो सकता है. संभव है कि जिन दवाइयों का सेवन आप कर रहे हैं, वे ग़लत असर कर रही हों या आपको 'स्लीपिंग सिकनेस' जैसी किसी बीमारी ने घेर लिया हो. अगर आपको पर्याप्त से ज़्यादा नींद आए या हर समय आप स्वयं को थका-थका सा महसूस करें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें.

झपकी बनाए ख़ुशगवार

आप काफी थक चुके हों, पर काम अभी भी बाक़ी है और आप सो नहीं सकते तो ख़ुद को रिचार्ज करने के लिए झपकी लें. 15-45 मिनट की झपकी जादुई असर दिखाती है. पश्चिमी देशों और वहां की देखादेखी अब भारत के भी कुछ ऑफिसों में लंच के बाद झपकी लेना एक आवश्यक नियम है. इसके काफी अच्छे नतीजे सामने आए हैं.

नींद के विभिन्न पांच चरण

मनुष्य नींद के लगातार पांच चरणों से गुजरता है, जो क्रमबद्ध होते हैं और जिनका शरीर व मस्तिष्क पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है. इसे निद्रा प्रयोगशालाओं में पॉली सोम्नोग्राफी से मापा जा सकता है. यह विधि नींद की इलेक्ट्रॉनिक और शारीरिक अवस्थाओं के आंकड़े देती है. नॉन-रैपिड आइ मूवमेंट की अवधि नींद के पहले से चौथे चरण तक होती है और 5 से 15 मिनट के हरेक चरण में 90 से 120 मिनट तक रहती है. नींद के ये चरण रात भर चक्रीय क्रम में बार-बार आते हैं. नींद का हर चक्र पहले के चक्र से बड़ा होता है, क्योंकि आखिरी चरण की अवधि बढ़ती जाती है. विशेष बात यह है कि ज़्यादातर लोग एक रात की नींद में ही पांचों चक्र पूरे कर लेते हैं.

पहला चरण-हल्की नींद : मांसपेशियां ढ़ीली पड़ जाती हैं, शरीर का तापमान गिर जाता है, अर्द्धनिद्रा सी रहती है, व्यक्ति चेतन अवस्था में रहता है.

दूसरा चरण- संक्रमण : हृदयगति, श्वांस के साथ मस्तिष्क की विद्युतीय तरंगों की गति भी धीमी. यह अवस्था गहरी नींद के पहले की है.

तीसरा व चौथा चरण- गहरी नींद : श्रवण और स्पर्श इंद्रियां निष्क्रिय, शरीर पूरी तरह शिथिल. इस अवस्था से किसी को जगाना बहुत कठिन होता है.

पांचवा चरण- त्वरित चक्षु गति या आरईएम की अवस्था : आंखें और चेहरा तो गतिशील, पर मांसपेशियां शिथिल. हृदयगति, श्वांस अस्थिर, और मस्तिष्क की हलचल तीव्र. यह गहन सपने की अवस्था, पर मांसपेशियां शिथिल होने से सपनों पर अमल मुमकिन नहीं.

एक रिसर्च के अनुसार, हवाई जहाज की आवाज हो या गाड़ियों की अथवा फिर बगल में सो रहे व्यक्ति के खर्राटों की, किसी भी तरह की आवाज आपकी नींद के लिए हानिकारक है. गहरी नींद सोते वक़्त उन आवाजों से शायद आपकी आंख न खुले, पर मंद-मंद यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है. सोते वक़्त आवाज होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. इसे हाइ-परटेंशन भी कहते हैं, जिससे हार्टअटैक की आशंकाएं बढ़ जाती हैं और स्ट्रोक व किडनी की दिक्कतों से सामना हो सकता है. जितनी तेज आवाज होगी, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. 2 से 4000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवाज नींद के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है. हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. के के अग्रवाल के अनुसार, नींद का संबंध भूख से भी है. नींद भूख को क़ाबू में रखने के लिए ज़िम्मेदार लेपटिन और ग्रेलीन नामक हार्मोन को प्रभावित कर निकलने से रोकती है, जिसके असर से हाइपोगलायसेमिया की शिकायत हो सकती है. रिसर्च द्वारा यह साबित हो चुका है कि रात को सोते वक़्त खर्राटे आने से नींद में खलल पड़ती है. खर्राटे आने के भी कई कारण हो सकते हैं. जैसे नींद की दवा, ताक़त की दवा या एंटी हिस्टामाइन गोलियों का सेवन. धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन. मोटापा, अगर पुरुष हों तो गर्दन की मोटाई 16.5 इंच से ज़्यादा होना. किसी भी तरह की नाक की बीमारी, जिससे सांस लेने में तक़लीफ़ हो और मुंह से सांस लेनी पड़े. उम्रदराज होना, इससे मांस का कसाव घटता है और मांसपेशियों के कणों में कंपन बढ़ने की वजह से आवाज ज़्यादा होती है. पुरुषों में हवा आने की नली संकरी होती है.

ऊंचे तकिए का इस्तेमाल, जिससे गर्दन टेढ़ी हो और गले से हवा के आने-जाने का रास्ता बंद हो जाए. गर्भावस्था के आख़िरी चरण में होना.

असहज नींद की बीमारी होना, जिससे सांस लेने में परेशानी हो. अनियमित धड़कन, ब्लड में ऑक्सीजन कम होना जैसी तकलीफ होना.

सभी बातों पर गौर करने का मतलब यह कतई नहीं है कि नींद की नियमितता की आड़ में जीवन जीना छोड़ दें. अगर देर रात की पार्टी पसंद हो तो हफ्ते में एक बार जरूर 'लेट नाइट पार्टी' करें, बस अगले दिन नींद पूरी कर लें.

ritika@chauthiduniya.com

करना क्या चाहिए

- अगर आप ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते तो अच्छी नींद सोने के लिए 30-45 मिनट तक एक्सरसाइज करें.
- अपनी उनींदी आंखों से झगड़ा न करें. किसी जरूरी काम के एवज में नींद भरी आंखों से लड़ाई मोल न लें. थोड़ी देर सो लें, फिर काम करने के लिए सोचें.
- नियत समय पर सोने-जागने की आदत डालें.
- सोने से पहले चाय, कॉफी या शराब का सेवन कतई न करें.
- रात का खाना हल्का लें और खाने के बाद 40 क़दम ज़रूर टहलें.
- हो सके तो सोने के आधा घंटे पहले स्नान करें.
- सही तरह के गद्दे और तकिए का इस्तेमाल करें. बेडशीट का रंग हल्का रखें.
- बत्ती बुझाकर सोएं. सोने का वातावरण शांत रखें.
- सोने के वक़्त उन बातों का ध्यान न करें, जिनसे आपको तनाव होता हो.
- बेड पर जाने से पहले थोड़ा सा चित्त प्रसन्न करने वाला संगीत सुनें या किताब पढ़ें. लेकिन उनींदी महसूस होने पर फ़ौरन सुनना-पढ़ना बंद कर दें. ऐसा न हो कि म्यूजिक सिस्टम रात भर चलता रहे या दिलचस्प किताब की वजह से आपकी नींद मात खा जाए.

हर उम्र के व्यक्ति के लिए सोने का अलग-अलग उपयुक्त समय होता है. छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा लगभग 16 से 18 घंटे सोते हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, नींद भी कम होती जाती है. वयस्क के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है.

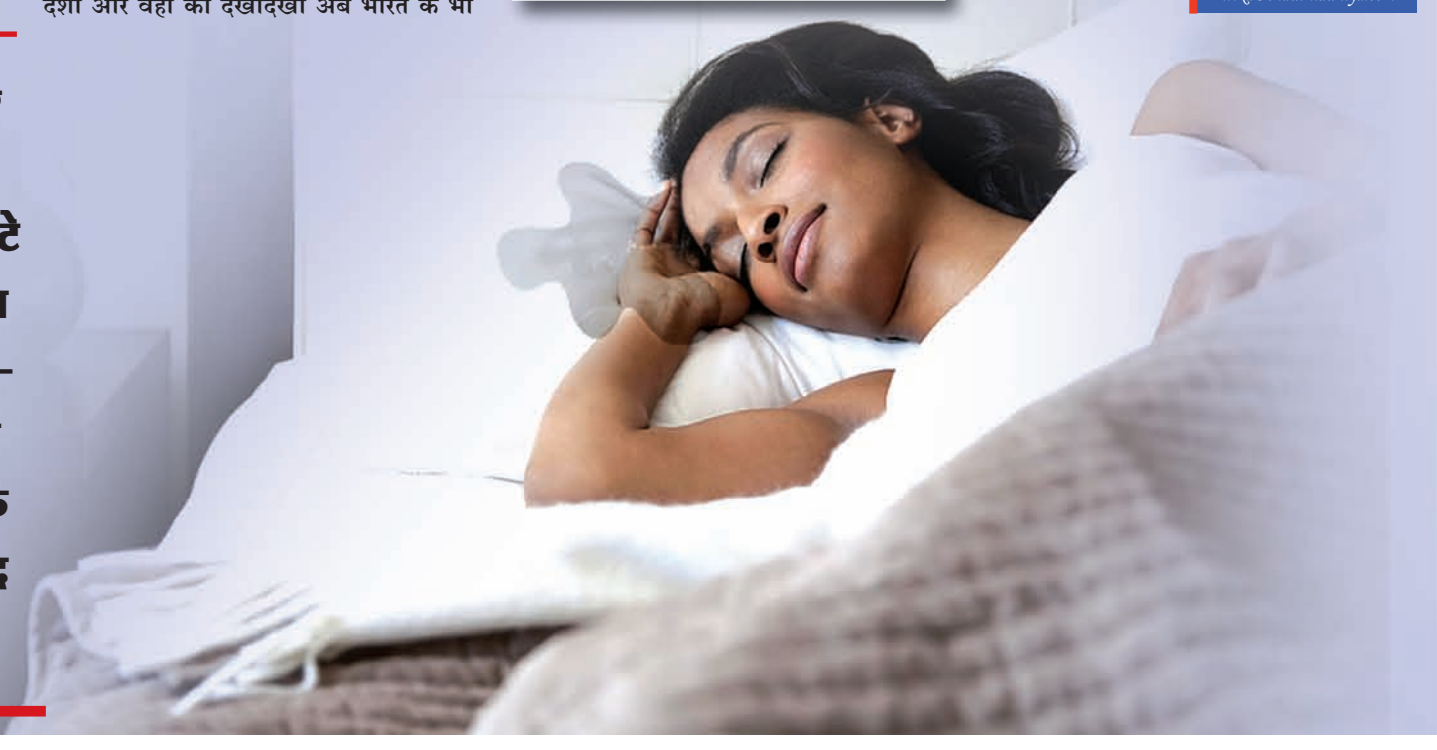

राशिफल

(26 अक्टूबर–1 नवंबर)

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
अनचाहे लोगों से अचानक मुलाक़ात हो सकती है. पारिवारिक मामलों में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. आपके प्रवास की स्थितियां बन रही हैं. यह लाभदायक हो सकती हैं. सामाजिक क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
पारिवारिक क़लह का सामना करना पड़ सकता है. बेहतर होगा बात को आगे न बढ़ाएं. किसी मित्र या संबंधी के साथ चली आ रही ग़लतफहमी दूर हो जाएगी. आर्थिक क्षेत्र में आय के नए अवसर उपलब्ध होंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
सहयोगी जनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. उच्च रक्त चाप से पीड़ित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यस्तता अधिक रहेगी. व्यवसायिक मामलों में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
संबंधित अधिकारी व पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा. दैनिक आमदनी बढ़ेगी. रुके कार्य संपन्न होंगे. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी नए कार्य को करने से पहले सोच-विचार अवश्य कर लें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
प्रतियोगी परीक्षा की दिशा में चल रहे प्रयास सफल होंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी. परिवार में ख़ूब मान-सम्मान मिलेगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. कहीं दूर यात्रा करने की सोच रहें है तो अवश्य ही जाएं, उसमें सफलता के योग बने हुए हैं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
किसी को कोई अप्रिय बात न कहें. सहयोगी जनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आप पारिवारिक उत्सव में आमंत्रित किए जाएंगे. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. विरोधी सक्रिय रहेंगे, सावधान रहें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. अपनेपन का भरपूर अहसास रहेगा. किसी मूल्यवान वस्तु को पाने की अभिलाषा पूरी होगी. उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. आर्थिक क्षेत्र में नई योजना बनाएंगे तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
अपने सम्मान की सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. आपकी सौम्य व्यवहारशीलता आपको लोकप्रिय बनाएगी और साथ ही धन सम्मान का लाभ भी मिलेगा. घर में भौतिक सुख-सुविधाओं की वस्तुएं बढ़ेंगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
संतान के संबंध में को सुखद समाचार मिलेंगे. यथासाध्य किसी प्रकार का ख़तरा न मोल लें, विरोधी सक्रिय रहेंगे. लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा. आर्थिक क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
मांगलिक कार्यों के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. उपहार मिलेंगे. सम्मान बढ़ेगा. आपका मन किसी बात से दुखी हो सकता है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
परिवार के सदस्यों से आज किसी बात पर विवाद हो सकता है. वाणी पर नियंत्रण बनाएं रखें. आप यात्रा करेंगे तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा. राजनीतिक दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
अनचाहे जगह की यात्रा करनी पड़ सकती है. नया वाहन लेने की सोच रहें हैं तो ले लें. कार्य का विस्तार होने से आप व्यस्त अधिक रहेंगे. उत्पादन की दिशा में चल रहे प्रयास सफल होंगे. अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

पुण्यनगरी हरिद्वार में हरकी पौड़ी वह स्थान है जो यूं बारहों महीने श्रद्धालु तीर्थयात्रियों और स्नानार्थियों से घिरा रहता है पर हर बारहवें बरस यहीं पर महाकुंभ का विराट धर्मिक स्नान संपन्न होता है.

सितारों पर लगाओ लगाम

अनंत विजय

देश के दक्षिणी राज्यों में फिल्मी सितारों का अच्छा ख़ासा प्रभाव है. जनता चाहती है तो ज़ाहिर है. राजनेता और राजनीतिक दलों के बीच भी उनकी धाक है. पिछले दिनों जब तमिल दैनिक दिनामलार के न्यूज़ एडिटर बी लेनिन को अख़बार में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर बग़ैर किसी वारंट के पुलिस ने उनके दफ़्तर से गिरफ़्तार किया और रात में ही जज के घर पर पेश कर रिमांड पर लिया तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए. दरअसल दिनामलार में एक तमिल अभिनेत्री के सेक्स रैकेट में शामिल होने की ख़बर छापी गई थी, जिससे पूरा तमिल फिल्म उद्योग एकजुट होकर चेन्नई पुलिस कमिश्नर के दफ़्तर के सामने धरने पर बैठ गया. तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने उक्त अभिनेत्री पर लगाए गए आरोपों को फिल्म फेटरनिटी पर लगा आरोप मानकर एकजुटता दिखाई. तमिल फिल्मों के सुपर स्टार रजनीकांत भी धरने पर बैठे और उन्होंने मीडिया को जमकर नसीहत दी. लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की इजाज़त सबको है, लेकिन जिस तरह से तमिल फिल्मी सितारों ने ज़हर उगला, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है. दिनामलार के संपादक पर तो अख़बार में छपी रिपोर्ट के आधार पर हैरेसमेंट ऑफ वूमन एक्ट लगा दिया गया, लेकिन सरेआम लेनिन के परिवारवालों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने वाले फिल्मी सितारों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत चेन्नई पुलिस नहीं जुटा पाई.

जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें तमिल सितारों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं. श्रीप्रिया तो जोश में होश खो बैठीं और उन्होंने दिनामलार अख़बार के मालिकों के परिवार की औरतों के बारे में जमकर बुरा-भला कहा. विवेख ने तो यहां तक कह डाला कि अगर लेनिन की परिवार की औरतों की तस्वीरें उन्हें मिल जाएं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए वह अश्लील तस्वीरों के ऊपर उनका चेहरा लगाकर पूरे राज्य में दीवारों पर चिपकवा देंगे. यही नहीं, उन्होंने मीडिया को बग़ैर फिल्मों के सीन इस्तेमाल किए पत्रकारिता करने की चुनौती दे डाली. अब इस कॉमेडियन को कौन समझाए कि सितारों की लोकप्रियता मीडिया की बदौलत ही है. किसी भी फिल्म के रिलीज़ होने के पहले उनके पब्लिक रिलेशन एजेंट किस क़दर मीडिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं, यह बताने की ज़रूरत नहीं है. अभिनेता विजय कुमार ने तो सरेआम यहां तक कह डाला कि दिनामलार की उस रिपोर्ट को देखने के बाद उनका ख़ून खौल उठा और वह अख़बार के दफ़्तर में घुसकर हंगामा करने की सोचने लगे थे. हो सकता है कि दिनामलार में छपी उस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां हों और जनता के हित की कोई बात नहीं हो. इसके लिए पीड़ित पक्ष को अदालत की शरण लेनी चाहिए या फिर अख़बार और पत्रकार के ख़िलाफ़ प्रेस काउंसिल जाना चाहिए था. लेकिन विरोध प्रदर्शन का यह कौन सा तरीक़ा है, जहां आप सरेआम गाली गलौच की भाषा इस्तेमाल करते हैं. यह एक ऐसा तरीक़ा है, जिसे अपनाकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और सरकार फिल्मी सितारों की लोकप्रियता के दबाव में बग़ैर सोचे समझे क़ानूनी कार्रवाई कर मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला कर रही है.

पिछले कुछ सालों से मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले लगातार बढ़े हैं. अगर हम ग़ौर करें तो मीडिया संस्थानों, चाहे वे प्रिंट हों या इलेक्ट्रॉनिक, पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमले की कई वारदातें हो चुकी हैं. अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब एक अनाम से संगठन हिंदू राष्ट्र सेना के तीस-चालीस गुंडे सरियों और हथौड़ों से लैस होकर मुंबई के एक टीवी न्यूज़ चैनल के दफ़्तर में घुस गए थे और उन्होंने वहां न केवल जमकर उत्पात मचाया,

फोटो- प्रभात पाण्डेय

बल्कि पत्रकारों के साथ मारपीट भी की थी. इतने पर भी जब उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने दफ़्तर का फर्नीचर और नीचे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तक तोड़ डालीं. इनके गुस्से की वजह बनी उक्त न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई एक ख़बर, जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी और उन्होंने समाज के ठेकेदारों के डर से वहां आकर आत्मसमर्पण कर दिया था. इस हमले की जब राष्ट्रीय स्तर पर घोर निंदा हुई, तब जाकर सरकार हरक़त में आई और अट्ठारह लोगों की गिरफ़्तारी हुई. बाद में पता चला कि हमला करने वाले इस अनाम से गैंग का मुखिया धनंजय देसाई था, जिसके ख़िलाफ़ पहले ही चोरी के तेरह मामले दर्ज़ थे.

उस वारदात के ठीक अगले ही दिन राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर से मारपीट की गई. दरअसल राजधानी के रोहिणी इलाक़े में एक डॉक्टर को महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया और जब रिपोर्टर मौक़े पर पहुंच कर तस्वीर लेने लगे तो डॉक्टर के समर्थकों ने वहां मौजूद मीडियाकर्मियों पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की. इन वारदातों से सकते में आया मीडिया अभी उबर भी नहीं पाया था कि सुदूर दक्षिण के शहर मदुरै से ख़बर आई कि कुछ उत्पाती लोगों ने तमिल दैनिक दिनाकरण के दफ़्तर को फूंक डाला है. इस घटना में तीन लोगों की मौत भी हुई. आरोप लगा था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि के बड़े बेटे और अब केंद्रीय मंत्री अझागिरी के समर्थकों पर. गुस्से की वजह दिनाकरण में छपा एक सर्वे था, जिसमें जनता से यह सवाल पूछा गया था कि करुणानिधि के बाद डीएमके की बागडोर कौन संभालेगा. और, अझागिरी के समर्थक इस बात से भड़क गए कि उनका नाम इस सर्वे में नीचे आया. उनका यही गुस्सा आगजनी और तीन लोगों की मौत की वजह बना. इस घृणित कृत्य के पीछे करुणानिधि के परिवार में चल रहा आपसी विवाद हो सकता है, लेकिन खुलेआम तो एक मीडिया संस्थान को जला कर राख कर दिया गया, उसमें काम करने वाले तीन लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था.

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले और भी जगहों पर व अलग-अलग तरीक़ों से भी हो रहे हैं. अभी कुछ महीने पहले शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने सामना में लिखे अपने संपादकीय में शिवसैनिकों को हुक्म दिया था कि जेम्स लेन की किताब-शिवाजी, हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया की प्रति जहां कहीं भी मिले, उसे जला दिया जाए और शिवसैनिकों के लिए तो बाला साहब का हुक्म पत्थर की लकीर होता है. ग़ौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीमकोर्ट ने इस किताब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था. इसके पहले संभाजी ब्रिगेड के लोगों ने जनवरी 2004 में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुसकर ऐतिहासिक महत्व के कई दस्तावेज़ों को नष्ट करने के अलावा संस्थान में तोड़फोड़ भी की थी. संभाजी ब्रिगेड का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जेम्स लेन की शिवाजी पर लिखी किताब में शोध में सहयोग देने के लिए लेखक ने इस संस्थान का आभार प्रकट किया था. संभाजी ब्रिगेड और हिंदू राष्ट्र सेना जैसे अनाम संगठनों को बाल ठाकरे के इस तरह के उकसाने वाले संपादकीय से बल मिलता है और वे मीडिया पर हमला करने का दुस्साहस कर पाते हैं.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद उन्नीस अन्य बातों के अलावा संघ के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच) का अधिकार प्रदान करता है. लेकिन, साथ ही संविधान अभिव्यक्ति को इस हद तक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जब तक कि वह दूसरों की आज़ादी का हनन न करे. लोग, यहां तक कि सरकारें भी इसी की आड़ में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने का यत्न करती हैं, जिसे बाद में अदालत बहुधा ग़ैरज़रूरी करार देती है. लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है और वर्षों के अपने लंबे संघर्ष के बाद मीडिया ने अपना एक मुक़ाम हासिल किया है तथा लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में ख़ुद को स्थापित भी किया है. लेकिन, अपनी आलोचनाओं से नाराज़ होकर लोग क़ानून ख़ुद हाथ में लेने लगे हैं या अपने समर्थकों को उकसाने लगे हैं और मीडिया संगठनों को डराने धमकाने की कोशिश शुरू हो जाती है.

अब वक़्त आ गया है कि मीडिया को ख़ुद पर हो रहे हमलों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और संगठित होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए. दिनामलार के न्यूज़ एडिटर पर हुए पुलिसिया जुल्म के ख़िलाफ़ सिर्फ़ कुछ पत्रकार संगठनों ने बयान जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, लेकिन पत्रकारों को तमिलनाडु के फिल्मी सितारों से एकजुटता का सबक लेना चाहिए और सरकार पर सख्त क़ानून बनाने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

सच और सत्य में अंतर है

देवेन्द्र झा

अब मानव तन में समाहित होने वाली सातवीं कला आती है. सातवीं कलाधारी जीव की क्रिया का केंद्र-बिंदु होता है सत्य जो तन, दिमाग़ और हृदय की तरह शरीर की परिधि से बंधा नहीं होता. यह तो सत्य और स्थान की सीमाओं से भी स्वतंत्र होता है. यहां सच (फैक्ट) और सत्य (ट्रुथ) के भेद को उजागर करना आवश्यक होगा. सच (फैक्ट) उसे कहा जाता है जो किसी निर्धारित समय तथा स्थान में सही हो, पर सत्य (ट्रुथ) वह है जो सदैव तथा सर्वत्र सही हो. हम शरीर हैं, ऐसा मानना सच (फैक्ट) पर चलना है और हम शरीर नहीं चेतन आत्मा हैं, ऐसा मानना सत्य (ट्रुथ) पर चलना है. इस तरह से जो व्यक्ति शरीर-भाव से मुक्त होकर हम ईश्वर-अंश आत्मा हैं, ऐसा मानकर अपने समस्त क्रिया-जगत को संचालित कर पाते हैं, वे विशिष्ट पुरुष सात कलाधारी बन जाते हैं. अब चूंकि सत परमात्मा का स्वरूप है, अत: इस पर चलने वाले सात कलाधारी विभूति ईश्वर सदृश होकर मुक्तावस्था पा लेते हैं. छह कला तक के भाव-बंधनों को काटे बिना व्यक्ति सात कलाधारी की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता जबकि छह कला तक वह अपना बंधन चार और पांच कलाओं से बनाए रख सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार से छह कला तक क्रिया का केंद्र -बिंदु शरीर में अवस्थित है जबकि सातवीं कला का केंद्र-बिंदु सर्वत्र व्याप्त होता है. अत: शरीर-भाव से जब तक व्यक्ति पूर्णत: मुक्त नहीं होता, वह सात कलाधारी बन नहीं पाता और इस अवस्था को प्राप्त किए बिना मोक्ष पाना संभव नहीं होता.

व्यक्ति सदैव निर्भय हो सकता है

व्यक्ति अपने जीवन, अपने सबंधी-समूह, अपने देह-सुख तथा अपनी सम्पत्ति और वैभव से जुड़ा होता है और यह सब उसे आनंद के साथ-साथ गौरव तथा सुरक्षा का भाव भी देता है. अत: इन सबसे जुड़कर इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि करना अपनी प्रगति समझता है. अगर इनमें प्रगति हो रही होती है तो व्यक्ति आनंदित होता रहता है और इनमें और संवर्धन हो इसके लिए निरंतर प्रगतिशील रहता है. यह एक सामान्य जीवन का चित्रण है. पर असामान्यता तो तब आती है जब इनमें से कुछ नष्ट हो जाए या उत्तरोत्तर वृद्धि की जगह इनका ह्रास होना शुरू हो जाए. ऐसा कुछ होने लगे तो व्यक्ति इस आशंका से ग्रस्त हो जाता है कि कहीं उसका सब कुछ खो तो नहीं जाएगा. खोने का भय ही चिंता का कारण बनता है. संपदा का कुछ भाग हाथ से फिसल न जाए, स्नेहियों के समूह में से कोई बिछड़ न जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा की ऊंचाई कम न हो जाए, आनंद और मनुहार की फ़िज़ाओं पर पतझड़ का आक्रमण न हो जाए, उम्मीदों और अरमानों पर तुषारपात न हो जाए, बनी बनाई जन्नत काफ़ूर न हो जाए- कहीं ऐसा न हो जाए या कहीं वैसा न हो जाए. जब ऐसा होने की संभावना बनती नज़र आए तो व्यक्ति नि:सदेह भयग्रस्त हो जाता है. पर व्यक्ति इस भय से निकल कैसे सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति भयाक्रांत क्यों होता है. इसका मूल कारण है नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य बनाना. व्यक्ति जिन चीज़ों को प्राप्त कर चुका है अथवा प्राप्त करना चाहता है वे सभी चीज़ें नश्वर हैं, चंचल हैं और समय के क्रूर प्रहार से क्षत-विक्षत होती रहती हैं. जब इन चीज़ों की यही नियति है तो नियति के अनुकूल इनका

होना और मिट जाना स्वाभाविक है. फिर इनके मिट जाने का भय हमें क्यों आक्रांत करता है? इसका कारण है कि हम नश्वर चीज़ों को अविनाशी समझने तथा अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व का द्योतक मानने की भूल कर बैठते हैं. इसे अविनाशी मानकर हम सदैव इसे अपना समझने लगते हैं. लेकिन जब यह नष्ट होने लग जाए या बिछड़ने लग जाए तो यह नश्वर जैसा लगने लगता है और इसकी नश्वरता का आभास हमें अपनी नश्वरता की तरफ़ संकेत करने लगता है. यह संकेत हमें भयाक्रांत कर देता है. इस भय से आदमी तभी मुक्त रह सकता है जब वह हर नश्वर चीज़ को नश्वर समझकर ही स्वीकारे. जब वस्तु की नश्वरता सदैव उसके मानस-पटल पर रहेगी तो उसके नष्ट होते समय वह किसी भय अथवा चिंता से ग्रस्त नहीं होगा. इस समझ को क्रिया में और क्रिया को विश्वास में बदलने से व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं के विछोह के भय से सदैव के लिए मुक्ति पा सकता है.

(लेखक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

चर्चा कुंभनगर की

अरबों ख़र्च होंगे, पर हरकी पौड़ी जस की तस रहेगी

डॉ.कमलकांत बुधकर

देश के चार कुंभनगरों में से एक. सिर्फ़ ढाई महीने बाद 2010 की जनवरी से अप्रैल तक यह तीर्थनगर लाखों कुंभ स्नानार्थियों का स्वागत करने के लिए इन दिनों सज-संवर रहा है. शासन-प्रशासन के दावों पर यक़ीन करें तो चार मास की इस अवधि में हरिद्वार को पांच करोड़ मेहमानों का स्वागत करना है. तैयारियां चल रही हैं. सरकार संतुष्ट है पर अनेक कुंभ-अर्धकुंभों के गवाह नागरिक अभी तक आशंकित होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि नवगठित राज्य उत्तराखंड का यह पहला महाकुंभ सकुशल तो संपन्न होगा न?

जहां तक तैयारियों का प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने मेला प्रशासन का स्वरूप अब खड़ा कर दिया है. आयुक्त स्तर के एक वरिष्ठ आई ए एस अधिकारी आनंद बर्धन को महाकुंभ का मेलाधिकारी बनाकर क़रीब तीन-चार सौ करोड़ का भारी-भरकम बजट थमा दिया गया है. अनेक कुंभ-अर्धकुंभों के अनुभवी पुलिस उप-महानिरीक्षक आलोक शर्मा को शासन ने मेला क्षेत्र और स्नानार्थियों की सुरक्षा का ज़िम्मा देकर मेला पुलिस का मुखिया बनाया है. इन दोनों अधिकारियों के अधीन एक बड़ा सरकारी अमला भी है जो इन दिनों कुंभ से जुड़े कार्यों में जुटा हुआ है.

सत्तर बरसों के बाद पहली बार पूरे हरिद्वार की मलजल निकासी व्यवस्था यानी सीवर का जीर्णोद्धार किया गया है. सारी सड़कों का पुनरुद्धार होना है, गंगानहर पर दर्ज़नों स्थायी-अस्थायी पुल बनने हैं, पेयजल आपूर्ति के लिए दर्ज़नों नई टंकियां बनाई गई हैं, कई-कई किलोमीटरों के हिसाब से पाइप लाइनें और रोशनी के लिए बिजली के तार बिछाए जाने हैं, सैकड़ों खंभे गाड़े जाने हैं और सारे शहर को अतिक्रमण से मुक्त किया जाना है. पर अभी तक तो शहर पूरी तरह अव्यवस्थित है. हम इस अव्यवस्था और धीरे-धीरे होती जा रही व्यवस्था से पाठकों को हर सप्ताह अवगत कराते चलेंगे पर सबसे पहले उस स्थल की चर्चा करते हैं जहां महाकुंभ का मुख्य स्नान संपन्न होना है. धार्मिक विश्वासों के अनुसार, जहां अमृतकुंभ छलका था और जहां साधु-संतों की तरह अखाड़े शाही स्नान करते हैं. सन् 2010 के महाकुंभ को ध्यान में रखकर उत्तराखंड सरकार हरिद्वार की इस प्रमुख स्नानस्थली हरकी पौड़ी को एक नया विस्तार देना चाहती थी. ऐसा विस्तार इससे पूर्व भी अनेक मर्तबा किया जा चुका है. पर इस बार हरकी पौड़ी के इस भावी विस्तार को हरिद्वार के पंडों-तीर्थपुरोहितों ने अपने बीच ही पारस्परिक द्वंद्व का एक ज्वलंत मुद्दा बना दिया और विस्तार पर विराम लगवा दिया. इतिहास साक्षी है कि हरिद्वार के इस हृदयस्थल का पिछली शताब्दियों में अनेक मर्तबा विस्तार हुआ है. हर बार विस्तार का कारण स्नानार्थियों की बढ़ती संख्या ही रही है. कारण इस बार भी वही था विस्तार चाहने वालों के मन में. पांच करोड़ स्नानार्थियों और साधुसंतों की विशाल शाहियों तथा उनके साथ आने वाले उनके लाखों भक्त परिवारों का बोझ क्या वर्तमान हरकी पौड़ी उठा पाएगी? इसी प्रश्न का उत्तर शासन प्रशासन ने हरकी पौड़ी के टाल दिए गए विस्तार में ढूंढा था. पर इन दिनों समाज का वह आदरणीय वर्ग, जिसे पंडा समाज कहते हैं, आपस में ही गरिया रहा है. इनकी परस्पर की लड़ाई में हरकी पौड़ी का विस्तारकार्य थम गया है. लोग सोचने पर विवश हैं कि हरकी पौड़ी कहीं अब पंडों का कुरुक्षेत्र तो नहीं बन गई है.

पुण्यनगरी हरिद्वार में हरकी पौड़ी वह स्थान है जो यूं बारहों महीने श्रद्धालु तीर्थयात्रियों और स्नानार्थियों से घिरा रहता है पर हर बारहवें बरस यहीं पर महाकुंभ का विराट धर्मिक स्नान संपन्न होता है. देशभर के हज़ारों साधुसंत अपने-अपने अखाड़ों के शाही जुलूसों में शामिल होकर हरकी पौड़ी पहुंचते हैं और शाही स्नान करते हैं. उन्हें देखने और कुंभस्नान के लिए देश-विदेशों से लाखों की भीड़ हरिद्वार और वह भी हरकी पौड़ी पर ही पहुंचना चाहती है. कुंभ के इस नज़ारे के अलावा भी हरिद्वार आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए हरकी पौड़ी ही हमेशा से प्रमुख आकर्षण स्थल रहा है. अमावस्या हो या पूर्णिमा, एकादशी हो या ग्रहण,

बैसाखी हो या कांवड़ मेला या अन्य कोई त्योहार व पर्व, हरिद्वार में जब भी व्यवस्था की बात आती है तो शासन-प्रशासन दोनों की नज़र सबसे पहले हरकी पौड़ी पर ही पड़ती है.

यही वजह है कि हमेशा से हरकी पौड़ी की व्यवस्था एक संवेदनशील बिंदु रही है. इतिहास उठाकर देखें तो हरकी पौड़ी का रूपाकार हमेशा ही बदलता रहा है. समय समय पर घटी दुर्घटनाओं और युगीन आवश्यकताओं ने कई-कई बार हरकी पौड़ी को तुड़वाया और बनवाया है. तीर्थयात्रियों के भले के लिए हर बार लोगों ने उन परिवर्तनों का स्वागत किया है.

पर इस बार कुछ उल्टा ही हो रहा है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा-सुविधा का दम भरने वाले पंडे ही इस विकास में बाधक बन गए हैं. कहा जा रहा है कि हरकी पौड़ी घाट विस्तार से इसका पौराणिक और पारंपरिक स्वरूप बदल जाएगा. पर इन्हें जानना चाहिए कि अपने बड़े भाई भर्तृहरि की स्मृति में सम्राट् विक्रमादित्य द्वारा पहली बार बनवाई गई हरि की पैड़ी का वह दृश्य न जाने कब का विलुप्त हो चुका है जब बिल्वपर्वत की तलहटी में बने ब्रह्मकुंड तक पहुंचे पहाड़ के पैताने पर विष्णुचरण दिखाई पड़ते थे. इन्हें सातवीं सदी में चीनी यात्री व्हेनत्सांग और तेरहवीं सदी में तैमूरलंग के साथ आए इतिहासकार शर्फुद्दीन ने भी देखा था. वे अब कहां है? ब्रिटिश काल में भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर अजेक्ज़ेंडर कनिंघम की रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी खंडहर हो चुकी हरकी पौड़ी को सोल-हवीं सदी में आमेर नरेश मिर्ज़ाराजा मानसिंह ने बनवाया. मानसिंह की बनाई हरकी पौड़ी भी धीरे-धीरे पहाड़ कटते जाने और रिहायशी हवेलियां बनते जाने के कारण संकरी होती चली गई. वह अब कहां है? 1819 में भारी भीड़ आ जाने के कारण में सुविधाहीन संकरी हरकी पौड़ी पर कुचले जाने से 430 लोगों की जानें चली गई थीं. तब कैप्टन डी. बड ने हरकी पौड़ी को नया रूपाकार दिया. तब गंगा किनारे 34 फुट लंबा घाट बनाया गया जो सीढ़ियों के ऊपर 89 फुट लंबा था. वह अब कहां है? उस वक़्त कोई जनानाघाट हरकी पौड़ी पर था ही नहीं. तब भी ब्रह्मकुंड से सटी हवेलियां मौजूद थीं, जिन्हें बाद में 1938 के कुंभ से पूर्व तोड़कर खुर्जा के सेठ सूरजमल जटिया की मदद से इस हरकी पौड़ी में तब्दील किया गया जो 1986 के कुंभ से पूर्व तक देखी जा सकती थी. वे अब कहां है? 1986 के महाकुंभ से पूर्व हिंदुजा परिवार की मदद से एक बार फिर पुरानी हरकी पौड़ी का उत्तर दिशा में विस्तार किया गया. कई हवेलियों हटाकर पुराने जनानेघाट को तोड़कर नया जनानाघाट बना दिया गया. समझना चाहिए कि पुरातन ढांचों में परिवर्तन होता है, होता रहा है. पर हरकी पौड़ी के प्रति आस्था में परिवर्तन न कभी हुआ है, न कोई कर रहा है और न कभी कर सकता है.

लगातार बढ़ती जा रही भीड़ और समय की मांग के चलते अब ज़रूरी है कि हरकी पौड़ी पर यात्रियों को स्नान के लिए अधिक स्थान मिले. उनके जूते रखने के लिए ज़्यादा जगह हो, उनके शौचालय मूत्रालय घाट से हटकर हों, स्त्रियों को कपड़े बदलने के लिए अधिकाधिक चेंजिंग-रूम्स मिलें. वहां के पूजनीय मंदिरों को भीड़ के नाम पर बंद करवाने की पुलिसिया हरक़तों पर विराम लगे और मंदिर मार्गों व परिक्रमाओं को सुविधासंपन्न बनाया जाए. हरकी पौड़ी को खोखा मुदिरों से मुक्त किया जाए. कुल मिलाकर हरकी पौड़ी अधिक सुविधासंपन्न, सुंदर और विस्तृत बने.

पर हरकी पौड़ी की देखभाल करने वाले पंडे ही इस बात को लेकर दो फाड़ हो गए हैं. उनका एक गुट कभी साधुसंतों को समझाता है कि कुंभ का शाही स्नान ख़तरे में है. तो कभी महिलाओं को भड़काता है कि उनका स्नानस्थल छीना जा रहा है.

जबकि सचाई यह है कि साधुओं का शाही स्नान स्थल ब्रह्मकुंड है. इसी कुंड में शाही स्नान होता है सो अब भी होगा. उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. कुछ है तो यही कि शाहियों के साथ जो ज़्यादा संख्या में साधु और भक्तगण आने लगे हैं उन्हें भी प्रस्तावित विस्तार में एक विस्तृत घाट स्नान के लिए मिल जाता. जहां तक महिलाओं का प्रश्न है उन्हें नया, बड़ा और अधिक सुविधासंपन्न जनानाघाट दिए जाने का प्रावधान था. इतना ही नहीं उस घाट के अलावा पूरे हरकी पौड़ी क्षेत्र में अनेक चेंजिंग-रूम्स देने का भी प्रावधान नई विस्तार योजना में था, जो अब पंडों की संकीर्ण सोच की भेंट चढ़ चुका है.

हरकी पौड़ी के घाट, पौड़ियां और प्लेटफॉर्म दरअसल हरिद्वार नगरपालिका परिषद् की संपत्ति है जिसे उसने साफ़-सफ़ाई की व्यवस्था और अन्य धार्मिक गतिविधियां सुचारु चलती रहें, इस आशय से स्थानीय तीर्थपुरोहितों की संस्था श्रीगंगासभा को सौंप रखा है. श्रीगंगासभा 1916 से अस्तित्व में है और तीर्थमर्यादा बनी रहे, इसके लिए इस संस्था का गौरवशाली इतिहास भी रहा है. पर दुर्भाग्य से अब यह संस्था कतिपय तीर्थपुरोहितों की निजी राजनीतिक स्वार्थपूर्त्ति का मंच बनकर रह गई है. वर्तमान में इस संस्था की सारी सक्रियता अधिकारियों की आपसी उठापटक और रस्साकशी का अखाड़ा बनकर रह गई है. यह पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता हरकी पौड़ी क्षेत्र को यात्रियों के लिए अधिक सुविधासंपन्न बनाने के स्थान पर उनकी अपनी निजी लकीर कैसे ऊंची रह सके, इन प्रयासों तक सिमट गई है. हरकी पौड़ी का विकास और तीर्थयात्रियों की सुविधाएं अब तीर्थपुरोहितों के लिए गौण हो गई हैं. कुल मिलाकर हाल ये है कि महाकुंभ पर अरबों रुपये ख़र्च होंगे पर महाकुंभ की आकर्षण स्थल हरकी पौड़ी की हालत जस की तस रहेगी.

feedback@chauthiduniya.com

पर्वतारोहियों को गर्म रखने के लिए एक ऐसी जैकेट बनाई गई है, जो उन्हें बर्फ़ीली ठंडक से तो बचाएगी ही, साथ-साथ उनके गैजेट्स को भी चार्ज करेगी.

सड़कों पर सरपट दौड़ेगी जेड-4

कार के शौक़ीनों के लिए एक अच्छी ख़बर यह है कि बीएमडब्ल्यू ने एक स्पोर्ट्स कार जेड-4 रोडस्टार लांच की है, जिसका लुक काफी शानदार है और इंजन की क्षमता भी गज़ब की है. जब इंजन की क्षमता ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि इसकी रफ़्तार भी अच्छी होगी. इसके पीछे कंपनी का मक़सद यह है कि वह भारतीय बाज़ार में अधिक से अधिक कार बेच सके और अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी मर्सीडीज बेंज को पीछे छोड़ दे.

लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी बीएमडब्ल्यू ने जेड-4 रोडस्टार नामक जिस नई कार को भारतीय बाज़ार में उतारा है, उसकी एक्स शोरूम क़ीमत 59 लाख रुपये है. दो सीटों वाली इस स्पोर्ट्स कार में 2,979 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है. कंपनी का लक्ष्य अगले तीन महीने में 30 से 40 कार बेचने का है.

कंपनी का कहना है कि वह इस साल 3000 कारें बेचने का इरादा रखती है. सितंबर तक उसकी 2738 कारें बिक चुकी हैं. बीएमडब्ल्यू का मुक़ाबला मर्सीडीज बेंज से चल रहा है. बीएमडब्ल्यू ने जनवरी 2009 से अगस्त के बीच 2305 कारें बेचीं, जबकि मर्सीडीज ने केवल 2026.

भारतीय कार बाज़ार में बीएमडब्ल्यू और मर्सीडीज बेंज के बीच कड़ा मुक़ाबला है. दोनों ही कंपनियां भारतीय बाज़ार पर अधिक से अधिक क़ब्ज़ा जमाना चाहती है. अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग किस कार को ज़्यादा तरजीह देते हैं. अगर आप शानदार लुक और रफ़्तार के दीवाने हैं तो यह कार आपके लिए एकदम फिट रहेगी.

क्लिकफ्री से रखिए डाटा सेव

कॉन जॉन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ने एक ऑटोमेटेड डिवाइस क्लिकफ्री भारतीय बाज़ार में लांच किया है, यह देखने में काफी छोटा है और इसका लुक भी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन आप इसके छोटे आकार पर न जाएं. क्योंकि यह देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन काम बड़ा करता है. इसकी स्टोरेज क्षमता का कोई जवाब नहीं है. यह कई तरह की फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है.

इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसकी स्टोरेज क्षमता 160 जीबी से 2 टीबी (टेराबाइट) तक है. इस डिवाइस के ज़रिए आप आसानी से डाटा इंसटॉल कर सकते हैं. कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट के ज़रिए आप इसे आसानी से प्लग कर डाटा का बैकअप भी रख सकते हैं. हार्ड डिस्क ड्राइव लगभग 400 फाइल फार्मेट को सपोर्ट करता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पॉवर प्वाइंट और अन्य शामिल हैं. इसके अलावा म्यूजिक, वीडियो, फोटो, ई-मेल और इंटरनेट बुकमार्क्स को भी यह सपोर्ट करता है.

क्लिकफ्री एचडीडी 2.5 और 3.5 इंच में उपलब्ध है. इसकी स्टोरेज क्षमता 160 जीबी से 2 टीबी तक है. जो अन्य की तुलना में काफी अधिक है. इस तरह आप अपने महत्वपूर्ण डाटा को सेव रख सकते हैं.

वैसे आप भी कभी-कभी डाटा को सेव रखने के लिए चिंतित हो जाते होंगे, लेकिन क्लिकफ्री ऐसा सॉल्यूशन है, जो आपको टेंशनमुक्त कर देगा. अगर आपको भी इस परेशानी से दो-चार होना पड़ रहा है, तो अब परेशानी को अलविदा कहिए और ले आइए क्लिकफ्री.

नहीं, बल्कि अच्छी तस्वीर भी निकाल सकते हैं. अगर आपके पास छोटी फोटो है और आप इसे प्रिंट के समय और बड़ा करना चाहते हैं तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं

स्कैनर का कमाल फोटो बेमिसाल

कभी-कभी कोई फोटो इतनी ख़ास होती है, जिसे आप हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन दिक़्क़त तब होती है, जब इस फोटो की एक ही प्रति आपके पास होती है और रील (फिल्म) भी कहीं गुम हो चुकी होती है. उस वक़्त आपको टेंशन ज़रूर होती होगी कि इसे कैसे संभाल कर रखा जाए. मन आशंकित भी रहता होगा कि दोबारा बनवाने पर न जाने इसकी क्वालिटी कैसी आए और मूल प्रति का क्या होगा आदि. मगर, अब इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्कैनर के ज़रिए आप सिर्फ़ बड़ी ही है, क्योंकि स्कैनर की डीपीआई (डॉट्स पर इंच) सेटिंग के ज़रिए आप फोटो के आकार और उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं. जैसे आपके पास 4 गुना 6 इंच की फोटो है और आप इसे 81/2 गुणा11 व 8 गुणा 10 इंच और बड़ा करना चाहते हैं, तो फोटो कैप्चर करने के लिए आप स्कैनर को 600 डीपीआई पर सेट करें, ताकि जब आप इसे दोबारा प्रिंट के लिए दें तो फोटो को देखने से यह पता न चले कि यह ब्लर या मूल प्रति से भिन्न है. जब आप किसी फोटो को स्कैन करते हैं, तब अधिक डीपीआई की सेटिंग करते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि फोटो की बारीक से बारीक चीज़ों को यह कैप्चर करता है, जिससे फोटो की क्वालिटी अच्छी होती है और देखने में वह हूबहू मूल प्रति की तरह लगती है. इस स्कैनर की ख़ासियत का पता तो तभी चलेगा, जब आप अपनी फोटो स्कैन कराएंगे और हूबहू परिणाम आने पर यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई स्कैनर के कमाल से फोटो बेमिसाल हो जाता है.

सेलफोन व गैजेट्स चार्ज करेगी जैकेट

ठंड ने दस्तक दे दी है. लोग निश्चित रूप से गर्म कपड़े ख़रीदेंगे. आप भी यही सोच रहे होंगे कि आख़िर इसमें नई बात क्या है. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म पोशाक ख़रीदते ही हैं और वे स्वेटर, शाल व कोट आदि की अपेक्षा जैकेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं. मगर, हम आपको यहां ऐसी जैकेट के बारे में बता रहे हैं, जो अन्य जैकेटों से बिल्कुल अलग है. वैसे तो इसे पर्वतारोहियों की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसका उपयोग आप भी कर सकते हैं. इसके फीचर्स के बारे में पढ़कर आप चौंक जाएंगे.

पर्वतारोहियों को गर्म रखने के लिए एक ऐसी जैकेट बनाई गई है, जो उन्हें बर्फ़ीली ठंडक से तो बचाएगी ही, साथ-साथ उनके गैजेट्स को भी चार्ज करेगी. जैसे सेलफोन, आईपॉड, डिजिटल कैमरा और जीपीएस उपकरण आदि. इसकी ख़ासियत यह है कि इस जैकेट में एक एडॉप्टर लगा हुआ है, जो आपके सारे उपकरणों को चार्ज करेगा. इतना ही नहीं, इसे पहनने के बाद आप टेंपरेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं. इसके लिए जैकेट के बायीं तरफ़ एक टॉगल स्वीच है, जिसके सहारे आप 100 डिग्री फारेनहाइट तक टेंपरेचर को एडजस्ट कर सकते हैं. इसमें गर्म करने का एक उपकरण लगा हुआ है. माउंटेन हार्डवेयर स्पोक्समैन पेएज बाउचर के मुताबिक़, इस जैकेट को सिर्फ़ आपको चार्ज करना होगा. चार्ज करने के लिए भी आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए महज़ तीन घंटे देने होंगे. सबसे बड़ी बात यह कि तीन घंटे चार्ज करने के बाद यह जैकेट आठ घंटे तक आपको गर्म रखेगी, वह भी सबसे कम तापमान पर. जैकेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे स्की जैकेट के अंदर पहन सकते हैं और बाहर भी. इस जैकेट की ख़ासियत से अब आप परिचित हो गए हैं. आप भी इसे ख़रीदने को उत्सुक होंगे, लेकिन बात पैसे पर आकर रुक जाएगी. हालांकि आप सोचते होंगे कि इसकी क़ीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. पर ऐसा कुछ भी नहीं है. इसकी क़ीमत का हम सिर्फ़ अनुमान ही लगा सकते हैं, वैसे कंपनी बहुत जल्द इसके मूल्य के बारे में घोषणा करेगी. ख़ैर आप दाम की चिंता न करे पहले इसे ख़रीदने का मन बनाए. उसके बाद तो सबकुछ अपने आप ही हो जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एचटीसी ने नया मोबाइल टच-2 लांच किया

आए दिन भारतीय बाज़ार में मोबाइल फोन लांच होते रहते है और मोबाइल फोन प्रेमी उसके फीचर्स के हिसाब से उसकी ख़रीदारी करते हैं. अब देखिए न एचटीसी ने एक नया मोबाइल लांच किया, जो बिल्कुल आपको डेस्क टॉप जैसा अहसास देगा. इतना ही नहीं यह काफी आकर्षक है और इसके फीचर्स का जवाब नहीं है.

एचटीसी ने भारत में रिलायंस कम्यूनिकेशन के जीएसएम नेटवर्क पर एक नया स्मार्ट फोन लांच किया है, जिसका नाम एचटीसी टच- 2 रखा है. इस सेलफोन में माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट विंडो मोबाइल 6.5 ओ एस (ऑपरेटिंग सिस्टम) लगा हुआ है. यह ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट है. जब सिस्टम लेटेस्ट होगा तो काम भी अच्छा ही होगा. इसमें 7.11 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन है और कैमरा 3.2 मेगा पिक्सल का है. इसके अलावा एचटीसी टच-2 में दूसरे भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे. इसमें एक वेदर क्लॉक है, जो आपको समय के साथ-साथ मौसम की भी जानकारी देगा. इस डिवाइस में 3 जी और एक जीपीएस एंटीना लगा हुआ है, जो नेविगेशन- जैसे गूगल मैप को सपोर्ट करता है. सभी इंटरनेट सेवी यूजर्स एचटीसी टच-2 मोबाइल पर डेस्क टॉप स्टाइल की तरह वेब पेज देख सकते हैं. इतना ही नहीं, जूम बार के एक ऑप्शन के ज़रिए आप एक उंगुली के सहारे फोटो को बड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं. जब इस में इतने फीचर्स हैं तो आपका भी दिल इसे ख़रीदने को करेगा. इस सेलफोन पर आप इंटरनेट जैसी सुविधा पाएंगे. एक और ख़ास बात, यह देखने में इतना प्यारा है कि बस देखते ही बनता है, तो जनाब क्या सोच रहे हैं. जाइए बाज़ार और मोबाइल आउटलेट्स से आप अपना पसंदीदा सेलफोन उठा लीजिए.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 9811205225 email : advt@chauthiduniya.com

श्रीसंत पहली बार दक्षिण अफ़्रीका की धरती पर टेस्ट मैचों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत चर्चा में आए.

भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम पर लग सकता है बैन

अगले साल भारत में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं. एशियाड के बाद भारत पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी खेल का आयोजन कर रहा है. लेकिन संभव है, भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम इसमें भाग ही न ले पाए. दरअसल, भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम पर एक साल के प्रतिबंध का ख़तरा मंडराने लगा है. इसकी वजह है भारतीय वेटलिफ्टिंग खिलाड़ियों का डोपिंग में फंसना.

ग़ौरतलब है कि वेटलिफ्टिंग टीम के दो सदस्य पहले ही डोपिंग टेस्ट में दोषी पाए गए हैं. जिनमें शैलजा पुजारी और विक्की बट्टा तो दूसरी बार दोषी पाए गए हैं, जबकि एक महिला वेटलिफ्टर प्रियदर्शिनी का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है.

इस तरह डोप टेस्ट में कुल तीन खिलाड़ियों के दोषी पाए जाने के बाद भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम पर लगभग एक साल के लिए प्रतिबंध लगना तय है. इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के सचिव बी आर गुलाटी की मानें तो ये तीनों खिलाड़ी नेशनल एंटी डोपिंग टेस्ट में दोषी पाए गए हैं. हालांकि भारतीय टीम पर प्रतिबंध लगेगी या नहीं इस मामले में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर टीम को दंडित किए जाने की आशंका से उन्होंने भी इनकार नहीं किया. आशंका इस बात की ज़्यादा है कि भारतीय टीम को अगले साल दिल्ली में हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर होकर इसका ख़ामियाज़ा चुकाना पड़ सकता है. इससे पहले भी भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम 2006 में प्रतिबंध का शिकार हो चुकी है. हालांकि, छह महीने बाद ही टीम पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन अपने अतीत से यह टीम कुछ सीख नहीं पाई और आज एक बार फिर भारतीय वेटलिफ्टिंग खिलाड़ियों का साख दांव पर है.

अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाइ

यदि क्रिकेट का विश्वकप हो और भारत या पाकिस्तान की टीमें ही प्रतियोगिता से बाहर रहे तो इसकी रोमांचकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. कुछ ऐसी ही बात अर्जेंटीना के मामले में कही जा सकती है. दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला खेल है, फुटबॉल और जुनून की हद तक फुटबॉल को चाहने वाला देश है अर्जेंटीना. लेकिन क्वालिफाइंग दौर में ही इस पर फीफा महाकुंभ से बाहर होने का ख़तरा मंडराने लगा. कयास तो यह भी लगाया गया कि ब्राजील के हाथों मात के बाद विश्वकप के लिए अर्जेंटीना के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं. वह भी 1986 में अर्जेंटीना टीम को अपने मशहूर हैंड गोल की बदौलत विश्वकप जीताने वाले खिलाड़ी डिएगो माराडोना जैसे कोच के रहते. एक के बाद एक मैच हारने के बाद अर्जेंटीना टीम के प्रशंसक इस गॉड ऑफ हैंड की तीख़ी आलोचना भी करने लगे थे, यहां तक कि माराडोना ने कोच के पद से इस्तीफ़ा देने का भी फ़ैसला कर लिया था, लेकिन प्रतियोगिता से बाहर होने की दहलीज पर खड़ा अर्जेंटीना के लिए उरुग्वे के साथ हुआ मैच काफी भाग्यशाली साबित हुआ. इस मैच में उरुग्वे को 1-0 से मात देने के बाद अर्जेंटीना ने अगले साल दक्षिण अफ़्रीका में होने वाले फीफा विश्वकप के लिए अपनी जगह भी सुरक्षित कर ली. प्रतियोगिता से बाहर होने के कगार पर खड़ी टीम के लिए इससे बड़ी ख़ुशी की बात नहीं हो सकती थी. लेकिन इस ख़ुशी में कोच माराडोना खेल की तहजीब ही भूल बैठे और अब तक आलोचना झेल रहे माराडोना अभद्र गालीगलौज पर उतर आए. जिसकी जांच के लिए फीफा अध्यक्ष ने आदेश भी दिए हैं. यदि आरोप साबित होता है तो माराडोना की कोच पद से विदाई तय है. इन सबके बीच अर्जेंटीना उत्तरी अमेरिका से विश्वकप के लिए क्वालिफाई करने वाले चार देशों में सबसे निचले पायदान पर रहा. लेकिन एक बात तो तय है, फीफा विश्वकप का आयोजन हो और ब्राजील एवं अर्जेंटीना जैसी टीमें इसका हिस्सा न हो, फिर उस खेल में बच ही क्या जाता है. लेकिन शुक्र है कि दोनों ही टीमें प्रतियोगिता में होंगी और रोमांच भी अपने चरम पर होगा.

कयास तो यह भी लगाया गया कि ब्राजील के हाथों मात के बाद विश्वकप के लिए अर्जेंटीना के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं. वह भी 1986 में अर्जेंटीना टीम को अपने मशहूर हैंड गोल की बदौलत विश्वकप जीताने वाले खिलाड़ी डिएगो माराडोना जैसे कोच के रहते.

फोटो – पीटीआई

खिलाड़ी खेल की भद्रता भूलते जा रहे हैं

क्रिकेट को जेंटल मैन गेम कहा जाता है, लेकिन इसकी भद्रता मानो कहीं खो गई है. खिलाड़ियों की आपसी कहा सुनी तो आम बात है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुज़र जाए तो मानना चाहिए कि हालात वाक़ई गंभीर है. यही स्थिति भारतीय टीम में अंदर-बाहर होते रहे खिलाड़ी श्रीसंत की है. जी हां, भारतीय टीम का यह केरल एक्सप्रेस एकबार फिर सुर्ख़ियों में बना हुआ है. वह भी अपने ग़ैर-ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से. श्रीसंत पहली बार दक्षिण अफ़्रीका की धरती पर टेस्ट मैचों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत चर्चा में आए. लेकिन कहते हैं न कि बच्चा अपना करतब पालने में ही दिखा देता है तो श्रीसंत ने भी वही किया. दक्षिण अफ़्रीकी गेंदबाज़ आंद्रे नेल की गेंद पर छक्का जड़ने के बाद उनका ब्रेक डांस अभी भी सभी को याद ही होगा.

श्रीसंत की कहानी वहीं से शुरू होती है. फिर तो आईपीएल के आग़ाज़ के समय हरभजन के साथ हुआ चांटा विवाद भी भूलने लायक़ नहीं ही है. अब एक बार फिर ईरानी ट्रॉफी के मैच के दौरान विवादास्पद बातें कहकर वह फंस गए हैं. इस प्रतियोगिता के दौरान शेष भारत की ओर से खेलने वाले श्रीसंत ने मुंबई के हरफ़नमौला खिलाड़ी धवल कुलकर्णी को कुछ अपशब्द कहे. इसका ख़ामियाज़ा उन्हें मैचफीस का 60 फ़ीसदी जुर्माने के तौर पर चुका कर करना पड़ा. साथ ही, उन्हें बीसी-सीआई की ओर से सख्त चेतावनी भी मिली, यदि श्रीसंत अपने बर्ताव में बदलाव नहीं लाते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि भारतीय टीम में श्रीसंत ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं. एक से एक उस्ताद भारतीय टीम में भरे पड़े हैं. चाहे वह हरभजन सिंह का श्रीसंत को चांटा मारना हो या साइमंड्स के साथ कुख्यात विवाद. इस तरह के मामले खेल के लिहाज से वाक़ई चिंता के सबब हैं. पैसा कमाने की धुन में खिलाड़ी भद्रजनों के खेल की भद्रता को भूलते जा रहे हैं.

तांत्रिकों के जाल में रोनाल्डो

हम भारतीय हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि तंत्र-मंत्र का सहारा केवल हमलोग ही लेते हैं. अक्सर हमें इस बारे में सुनने को मिलता है कि हमारे क्रिकेटर लकी रूमाल आदि का इस्तेमाल करते हैं. सच में, कितने अंधविश्वासी हैं, हम. लेकिन ऐसा सिर्फ़ भारत में ही नहीं होता है और न ही सिर्फ़ क्रिकेट में. इस बार तांत्रिकों के जादू में उलझा है दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर. क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी हैं. लेकिन इनका कॅरियर ख़त्म करने और बचाने पर घमासान मचा हुआ है.

दरअसल, पुर्तगाल का यह खिलाड़ी आजकल टखने की चोट से परेशान है. हैरानी की बात यह है कि क्रिस्टियानो को यह चोट खेल के मैदान में लगी, पर इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है. जी हां, रोनाल्डो की चोट का क्रेडिट!!! दरअसल, सारा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. रोनाल्डो को प्राय: एक महिला की बांहों में देखा जाता था. अब, इस महिला का कहना है कि रोनाल्डो ने उसे धोखा दिया है. बदले में वह उसे बर्बाद करके ही दम लेगी. इसके लिए उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया. पेपे नाम का तांत्रिक रोनाल्डो की चोट का सारा श्रेय ले रहा है. वहीं दूसरी ओर फनार्डो नोगुइरा नामक तांत्रिक है, जो यह दावा कर रहा है कि रोनाल्डो के क़रीबी मित्र ने उसे पहले वाले तांत्रिक के जादू को काउंटर करने का ज़िम्मा दिया है. खेल के मैदान के बाहर रोनाल्डो से जुड़ा यह बेहद ही दिलचस्प मामला है. फुटबॉल के मैदान से हटकर रोनाल्डो की चोट तांत्रिकों के जादू-टोने में उलझ गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

MURUGAPPA GROUP

BSA MOTORS e-Scooters

BSA मोटार्स आ गया
सबके दिलों पे छा गया।

BSA MOTORS की हर एक इलैक्ट्रीक स्कूटर की खरीद पर पाईये
"एक साल की बैट्री वारंटी" एवम् "Rs. 4000/- का कैश कार्ड मुफ्त"।

Conditions apply##
*Ex. showroom Price starting from Rs.15,450/- for Smile in Delhi after subsidy & cash card.
*$ Battery Warranty of 12 months / 12000 km's whichever is earlier & applicable.
*# Savings Vary from model to model.

SHAHDARA: Binsar Auto Mobiles, 954 - E, Main 100 Ft Road, Babarpur Extn.Shahdara. Phone: 011-22831100 / 22831400/9911994444/9911450121. **NAJAFGARH: CNS Retail Pvt Ltd,** Plot No. 1, Block – G, Gopal Nagar. Phone: 011 - 28015634 / 28010709/ 09958019000/9212365634. **DWARKA-MAIN PALAM DABRI ROAD: CNS Retail Pvt Ltd,** D - 70/5, Main Palam Dabri Road, Mahavir Enclave. Phone: 011 – 28011702/ 45017150/09818239724/ 9212275634/ 9212170006. **NANGLOI: CNS Retail Pvt Ltd,** Plot No 18, Ram Nagar Colony, Main Najafgarh Road, Nangloi. Phone: 9971734599 / 9213899686. **KRISHNA NAGAR: Agrawal Motors,** A-1/14. Krishna Nagar, Chachi Building Chawk,Near Lal Quarter Market. Phone: 011 – 22452829/09312835117. **KAROL BAGH: Imperial Cycles,** 53/2, Deshbandhu Gupta Road, Karol Bagh. Phone: 011-65461542/ 28722276/25717886/9811453355. **ASHOK NAGAR: New Golden Cycle Store,** 36/13, Ground Floor, Ashok Nagar. Phone: 9810807183. **NOIDA: Agrawal Motors,** B-41 & 42, Sector 16 , Near Mirula's Hotel, Gautam Budh Nagar. Phone: 0120-4249906/ 4232242/9312835117/ 09350906906. **ROHINI: Rocky Autolinks,** F 18/61, Rohini, Sector 8. Phone: 9811032353 (Opening Shortly)

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया दिल्ली, 26 अक्टूबर-1 नवंबर 2009

निर्देशक राम गोपाल वर्मा, जिनका हाथ इनके सिर पर था, से इनका अलगाव हो चुका है. ज़ाहिर-सी बात है कि अब उन्हें फिल्मों में काम कौन देगा? एक वही तो थे जो हर फिल्म में उसे कोई न कोई भूमिका ज़रूर देते थे.

बॉलीवुड में काम नहीं करेंगी प्रियंका

आजकल बॉलीवुड की अधिकतर अभिनेत्रियां दक्षिण की ओर रुख़ करती नज़र आ रही हैं. बॉलीवुड में फिल्म *सरकार* से करियर की शुरुआत करने वाली प्रियंका कोठारी ने भी साउथ की तरफ़ जाने का मन बना लिया है. उन्हें लगता है कि बॉलीवुड में उनकी जगह नहीं है. सूत्र बताते हैं कि प्रियंका आजकल साउथ की फिल्में अधिक कर रही हैं.

दरअसल, उन्हें अभी तक बॉलीवुड में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. उन्होंने *जेम्स*, *डरना ज़रूरी है*, *आग* व *अज्ञात* आदि फिल्मों में काम किया है. इतनी फिल्में करने के बाद भी उनकी ट्रेन पटरी पर नहीं आई. गौरतलब है कि निर्देशक राम गोपाल वर्मा, जिनका हाथ इनके सिर पर था, से इनका अलगाव हो चुका है. ज़ाहिर-सी बात है कि अब उन्हें फिल्मों में काम कौन देगा? एक वही तो थे जो हर फिल्म में उसे कोई न कोई भूमिका ज़रूर देते थे. हो सकता है कि इसी वजह से बॉलीवुड में हर ओर निराशा हाथ लगने की वजह से ही उन्होंने साउथ जाने का मन बनाया हो.

प्रियंका ने साउथ फिल्मों में अपने कॅरियर की शुरुआत तमिल फिल्म *जे जे* से की थी. बहरहाल, वह डी-ग्लैमराइज़्ड रोल करना चाहती हैं, इसी वजह से उन्होंने साउथ की फिल्मों में अंग प्रदर्शन करने से मना कर दिया है, ताकि दर्शक उनके अंग के बजाय उनकी ऐक्टिंग के हुनर से रू-ब-रू हो सकें. उन्होंने अचानक से अपने ग्लैमर रोल से क्यों इंकार कर दिया यह तो वही बेहतर जानती होंगी. देखते हैं क्या वह अपनी पहचान साउथ की फिल्मों में बना पाएंगी?

प्रिटी वुमेन छोटे पर्दे पर

छोटे पर्दे पर आजकल बॉलीवुड के स्टार जज के रूप में अधिक देखने को मिलते हैं. पहले अमिताभ, सलमान, शाहरुख, अक्षय और शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े सितारे दिखे. अब प्रीति ज़िंटा भी छोटे पर्दे पर आने को तैयार हैं. लंबे समय से प्रीति फिल्मों में नहीं आ रही हैं. अचानक ही वह फिल्मों से गायब हो गईं. प्रीति अब एक रियलिटी शो में आ रही हैं. उनके शो का नाम *द प्रीति ज़िंटा शो* होगा, जिसके दिसंबर में प्रसारित होने की संभावना है.

प्रीति को इस शो से 10 करोड़ रुपये की आय होगी. शो में प्रीति हर सप्ताह एक सेलीब्रिटीज़ का इंटरव्यू करेंगी. ज़ाहिर-सी बात है कि प्रीति अपने इस टेलीविज़न डेब्यू से बहुत उत्साहित हैं. देखना यह है कि प्रिटी वुमेन का बड़े पर्दे वाला मनमोहक अंदाज़ छोटे पर्दे पर भी बरक़रार रह पाता है या नहीं.

आईपीएल और डीपीएल की रानी

रानी मुखर्जी ने लंबे समय के बाद हालिया रिलीज़ फिल्म *दिल बोले हड़िप्पा* से बॉलीवुड में अपनी वापसी की थी, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लग पाई. अब वह आईपीएल की टीम को ख़रीदना चाहती हैं. साथ ही रियलिटी शो डांस प्रीमियर लीग (डीपीएल) डांस शो में जज की भूमिका में भी नज़र आएंगी. फिल्म जगत से प्रीति ज़िंटा, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख़ ख़ान और जूही चावला जैसे बड़े-बड़े नाम आईपीएल के मालिक बन चुके हैं. हाल ही में सलमान ख़ान का नाम भी टीम ख़रीदने वालों की लिस्ट में शामिल था. इस लिस्ट में रानी मुखर्जी का नाम भी जुड़ गया है. सूत्रों के अनुसार, रानी का कहना है कि वह रियलिटी शो से पैसा कमाकर आईपीएल ख़रीदना चाहती हैं. डांस के इस शो में रानी देश के अलग-अलग हिस्सों से आई टीमों की डांस परफॉर्मेंस को जज करेंगी. यही नहीं, सलमान ख़ान, हिमेश रेशमिया, बिपाशा बसु, सोहेल ख़ान और करीना कपूर भी इन अलग-अलग टीमों का साथ देंगे. जज की कुर्सी पर रानी का साथ देंगे कोरियोग्रॉफर शामक डावर और अभिनेता अरशद वारसी. रानी के अचानक आईपीएल और डीपीएल में शामिल होने की आख़िर वजह क्या है? यह भी हो सकता है कि वह इसी के सहारे अपनी वापसी करना चाहती हों. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रानी वाक़ई में रानी बनने में कामयाब हो पाती हैं.

सल्लू और आमिर साथ-साथ !

कुछ समय पहले बात चल रही थी कि शाहरुख और आमिर ख़ान एक साथ बड़े पर्दे पर नज़र आने वाले हैं. अब शायद वाक़ई सलमान ख़ान और आमिर ने साथ में फ़िल्म करने की सोच ली है. इससे पहले भी कई बड़े फ़िल्म निर्माताओं ने इन दोनों की जोड़ी को लाने की ख़ूब कोशिश की, लेकिन हमेशा ही कोई न कोई मुद्दा आड़े आता रहा जिस कारण यह दोनों जोड़ी फिल्मों में दोहराई नहीं जा सकी. लेकिन बॉलीवुड में चर्चा गर्म है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट फाइनल होने को तैयार है.

ख़बर यह है कि आमिर ख़ान अभिनय करने के अलावा बतौर फिल्म निर्माता भी काम करेंगे और उनका साथ देंगे सोहेल ख़ान.

फ़िलहाल फिल्म का नाम अभी गुप्त रखा गया है. इससे पहले आमिर और सलमान वर्ष 1994 में राजकुमार संतोषी की फिल्म अंदाज अपना अपना में नज़र आए थे और वे दोनों दर्शकों को अपने अंदाज़ से अपना बनाने में कामयाब हुए थे क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने दर्शकों को ख़ूब हंसाया था. अब देखना यह है कि अपनी इस नई फिल्म में इन दोनों की जोड़ी क्या धमाल मचाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आने वाली फिल्में

अजब प्रेम की ग़ज़ब कहानी

अजब प्रेम की ग़ज़ब कहानी 6 नवंबर को रिलीज़ होगी. इस आने वाली नई फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी हैं. संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने. कलाकार हैं चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर, उपेन पटेल और कैटरीना कैफ. यह रणबीर और कैटरीना की एक साथ पहली फिल्म है. फिल्म की कहानी यह है कि रणबीर शहर के बीच में स्थित एक मूर्ति से अक्सर अपने दिल की बात कहते हैं. उन्हें लगता है कि एक दिन वह भी ऐसे ही दिखाई देंगे. इस फिल्म में सलमान ख़ान एक गेस्ट की भूमिका में नज़र आएंगे. फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा कि कैट और रणबीर की यह अजब कहानी बॉक्स ऑफिस पर क्या ग़ज़ब ढाती है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

www.chauthiduniya.com

दिल्ली, 26 अक्टूबर –1 नवंबर 2009

बिहार में सजी है हथियारों की मंडी

अमिताभ ओझा

आपको एके 47 चाहिए या एके 56 इंसास राइफल, कारबाइन चाहिए या फिर देसी बम या ग्रेनेड, यहां सब कुछ मिलेगा क्योंकि यह बाज़ार है हथियारों का. दाम दीजिए और ले जाइए मनचाहा हथियार. यह हाल है बिहार में हथियारों के बाज़ार का. चाहे राजधानी पटना हो या सुदूर का कोई इलाक़ा, हर जगह सजी है हथियारों की मंडी और बेचे जा रहे हैं मौत के सामान. नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद तो इस बाज़ार की रौनक ही बढ़ गई, क्योंकि सस्ते असलहों से यह मंडी भर गई और अपनी ताक़त बढ़ाने के लिए अपराधी व बाहुबली इस बाज़ार पर टूट पड़े हैं.

अपराध जगत के आंकड़ों पर भरोसा करें तो कश्मीर के बाद हथियारों की सबसे ज़्यादा ख़पत बिहार में ही होती है. यहां सिर्फ़ देसी हथियार ही नहीं, बल्कि हर तरह के आधुनिक हथियार मिलते हैं. कई ज़िले तो ऐसे हैं जहां भले ही कल-कारखाने बंद हो गए हैं, लेकिन वहां अवैध हथियार का कारखाना कुटीर उद्योग के रूप में चल रहा है. बिहार में हथियारों की न सिर्फ़ मांग ज़्यादा है, बल्कि यह सबसे बड़ा बाज़ार भी है. आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में हथियारों की चाह रखने वाले बिहार आते हैं. इसका एक कारण यह भी है कि बिहार में हर तरह के हथियारों की बड़ी रेंज है. यहां के आपराधिक गिरोहों के बीच हथियार को लेकर हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई होती रही है. जिस गिरोह के पास जितने ज़्यादा हथियार हैं, वही सबसे बड़ा है. आलम यह है कि बिहार में क़रीब दो हज़ार से ज़्यादा छोटे बड़े गिरोहों के पास हज़ारों की संख्या में असलहे हैं. ख़ासकर एके 47 या एके 56 को तो वे अपना स्टेटस सिंबल मानते रहे हैं. अवैध हथियारों की डिमांड रखने वाले और उसे पूरा करने वालों का यहां एक बड़ा सिंडिकेट है, जिसके संबंध आईएसआई से लेकर माओवादियों तक से हैं.

कहा जाता है कि 1992 में हुए पुरूलिया हथियार कांड का सबसे ज़्यादा हथियार बिहार के एक आपराधिक गिरोह के सरगना सिल्लू मियां के पास पहुंचा था. पुरूलिया हथियार कांड में सबसे ज़्यादा एके 47 गिरे थे और इस अत्याधुनिक हथियार ने हथियारों के बाज़ार को ही नहीं, बल्कि अपराधियों के सिंडिकेट का चेहरा ही बदल दिया था. भोजपुर में

(शेष पृष्ठ 18 पर)

अलग अलग ज़िलों में बनते हैं अवैध हथियार और पटना के बड़े होटलों में लगती है उसकी बोली.

लाइसेंस का गोरखधंधा

बिहार में सिर्फ़ हथियार ही नहीं, बल्कि लाइसेंसों का भी अपना अलग ही गोरखधंधा है. हाल के दिनों में बिहार के विभिन्न इलाक़ों से नगालैंड के बने फर्जी लाइसेंसों की बरामदगी से पुलिस तंत्र के कान खड़े हो गए हैं. सिर्फ़ पटना में ही अलग-अलग घटनाओं में आधा दर्जन से ज़्यादा फर्जी लाइसेंसों की बरामदगी हुई है. ख़ास बात है कि ये लाइसेंस ज़्यादातर प्राइवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी चलाने वाले लोगों के पास से मिले हैं. लाइसेंस बने होते हैं नगालैंड के जबकि हथियारों की ख़रीद की जाती है यूपी के बलिया से. पिछले दिनों पटना के कंकड़बाग थाने में दर्ज़ एक मामले की छानबीन के क्रम में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली थीं. नगालैंड में बने इन लाइसेंसों की जांच सीआईडी भी कर रही है.

क़ीमत एक नज़र में

एके 56	8,00,000
एके 47	7,00,000
राइफल	70,000
बंदूक़	40,000
हैंड ग्रेनेड	8000
रिवाल्वर	5000

बड़ी मनहूस है एके 47

भले ही एके 47 और एके 56 को अपराधी अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, लेकिन हक़ीक़त यह है कि अत्याधुनिक हथियार अपराधियों के लिए मनहूस ही साबित होता आया है. कुछ अपराधी इसे ब्रह्मास्त्र मानते है, जबकि कुछ इसे अपशकुन. बिहार में पहली बार एके 47 लेकर आने वाला कुख्यात सरगना सिल्लू मियां को जान से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि इसके चेले की नज़र इस हथियार पर थी. अंडरवर्ल्ड की चर्चा के अनुसार, सिल्लू मियां की हत्या में उनके ही एक चेले का नाम आया था, जो आज एक बाहुबली विधायक है. लेकिन दहशत का आलम यह रहा की परिवारवालों ने पुलिस में मामला तक दर्ज़ नहीं कराया. मध्य बिहार में आतंक का पर्याय बने पांडव गिरोह के ख़ात्मे की वजह भी यही एके 47 बनी. इसी हथियार के लिए पांडव गिरोह के दो सदस्यों बबलू सिंह और अशोक सिंह को धोखे से मार डाला गया. पटना का कुख्यात अपराधी छोटू सिंह की हत्या का कारण भी एके 47 ही बना. छोटू ने जेल में रहते हुए एक एके 47 ख़रीदी थी, जिसे उसने मुकेश-विकास गिरोह को दे दिया था. जेल से रिहा होने के बाद जब छोटू सिंह ने मुकेश से अपनी एके 47 मांगी तो एक दिन उसने धोखे से छोटू सिंह को अपने गांव बुलाया और उसे गोलियों से भून डाला. आज तक छोटू और उसके दो साथियों की लाश तक नहीं मिली. कोसी का आतंक कहे जाने वाले सहेंद्र गिरोह के साथ भी यही हुआ. उसे दूसरे गिरोह ने धोखे से भोज पर बुलाया और खाने में जहर मिला दिया और इस तरह पूरे गिरोह का सफाया कर दिया.

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास और संरक्षण की बस बातें भर होती रहीं. इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहें या फिर जानबूझकर की गई उपेक्षा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास एक पर्यटक स्थल के रूप में आज तक नहीं हो सका है.

नेपाल से सटा पूर्वी चंपारण का सीमावर्ती शहर रक्सौल. सुबह का समय है और रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे शहर में धुंध छाई हुई है. यह धुंध प्रकृति का कहर नहीं, बल्कि सीमेंट निर्माण में बतौर कच्चा माल इस्तेमाल होने वाली क्लिंकर की धूल है, जो जमते-जमते आसपास के वातावरण में धुंध जैसा प्रतीत हो रही है.

क्लिंकर की धूल से बीमार होता शहर रक्सौल

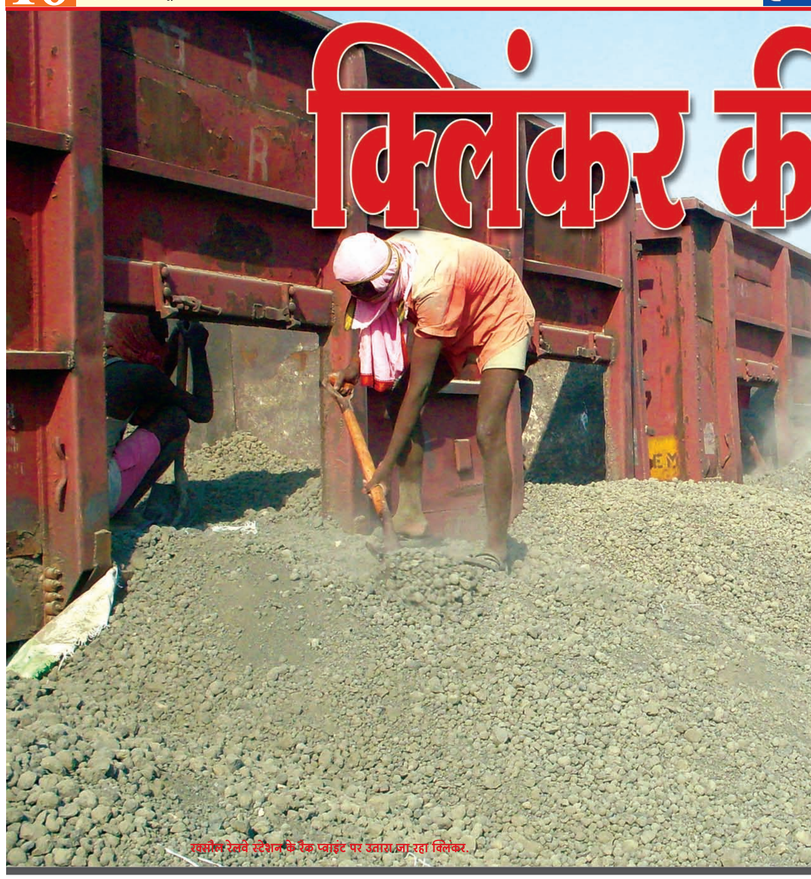

रक्सौल रेलवे स्टेशन के रैक प्वाइंट पर उतारा जा रहा क्लिंकर

मनोज कुमार राव

नेपाल से सटा पूर्वी चंपारण का सीमावर्ती शहर रक्सौल. सुबह का समय है और रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे शहर में धुंध छाई हुई है. यह धुंध प्रकृति का कहर नहीं, बल्कि सीमेंट निर्माण में बतौर कच्चा माल इस्तेमाल होने वाली क्लिंकर की धूल है, जो जमते-जमते आसपास के वातावरण में धुंध जैसा प्रतीत हो रही है.

> “चौथी दुनिया से बात करते हुए यहां के लोगों ने बताया कि पूरे मोहल्ले में अधिकतर लोगों को सांस फूलने और आंखों में जलन की शिकायत है. उन्हें कई दूसरी बीमारियों ने भी जकड़ रखा है. रक्सौल की पूरी आबादी इसकी चपेट में है. इसके चलते बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी बुरी तरह बाधित हो रही है.”

इस शहर में रहने वाला आम नागरिक हो या देश-विदेश से पहुंचने वाले पर्यटक, सभी इस प्रदूषण से बेहाल और परेशान हैं. बच्चे, बुज़ुर्ग व महिलाएं सभी इस धूल से बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. रक्सौल रेलवे स्टेशन के आसपास के कई मोहल्ले तो जैसे न जाने कितने सालों से इस ख़तरनाक प्रदूषण को झेलने को अभिशप्त हैं. अगर आप रक्सौल रेलवे स्टेशन पर उतरें तो प्लेटफार्म नंबर दो के बाहर इस नज़ारे को बड़ी आसानी से देख सकते हैं.

चाहे अधिकारी हों अथवा नेता, समाजसेवी हों या स्वयंसेवी संगठन या पर्यावरणविद, किसी को इतनी फ़ुर्सत नहीं जो इस शहर को क्लिंकर की चपेट से आज़ाद कराने की सोचें. रक्सौल रेलवे स्टेशन के पास स्थित परेइवा टोला निवासी रमेश प्रसाद अग्रवाल ने अपनी व्यथा सुनाते हुए चौथी दुनिया को बताया कि चाहे किसी भी दिशा से हवा आ रही हो, जैसे ही हवा की गति तेज़ होती है, हमारे जीवन को ग्रहण लग जाता है. घर की महिलाएं धड़ाधड़ खिड़कियां बंद करने लगती हैं और बच्चे भागकर कमरों में दुबक जाते हैं. बिस्तर हो या खाने पीने की वस्तुएं, देखते ही देखते सभी क्लिंकर धूल की चपेट में आ जाती हैं. लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है. वह बताते हैं कि उनके छोटे भाई अर्जुन कुमार को क्लिंकर की धूल ने इस क़दर दबोचा की वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाना पड़ा. उन्हीं के मोहल्ले की निवासी योगेंद्र की पत्नी भी क्लिंकर की ज़हरीली धूल के कारण बीमार हो गई हैं.

चौथी दुनिया से बात करते हुए यहां के लोगों ने बताया कि पूरे मोहल्ले में अधिकतर लोगों को सांस फूलने और आंखों में जलन की शिकायत है. उन्हें कई दूसरी बीमारियों ने भी जकड़ रखा है. रक्सौल की पूरी आबादी इसकी चपेट में है. इसके चलते बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी बुरी तरह बाधित हो रही है.

रक्सौल के लोगों ने चौथी दुनिया को बताया कि लगभग दो साल पहले तीन हज़ार लोगों ने क्लिंकर की धूल को लेकर रेल रोको आंदोलन किया था. उस समय तत्कालीन डीआरएम बी हरी ने सात दिनों के अंदर समस्या का समाधान कर दिए जाने का आश्वासन दिया था. समस्या का कोई समाधान तो नहीं निकला, बस इतना हुआ कि स्टेशन प्रबंधक के द्वारा जीआरपी में केस दर्ज़ कर लिया गया और 125 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज़ करवा दी गई. परेइवा टोला, चिकनी गांव, कस्टम ऑफिस के आसपास का इलाक़ा, नया बस्ती, डंकन अस्पताल के आसपास के इलाक़े, सुंदरपुर, मौजे गांव, ब्लॉक रोड व रक्सौल मार्केट के आम नागरिक मुख्य रूप से इस क्लिंकर की धूल की चपेट में हैं.

मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुंआ अगर प्रदूषण फैलाता है तो इस पर सवार व्यक्ति को पुलिस के डंडे का शिकार होना पड़ता है और मोटी राशि बतौर जुर्माना भी देना पड़ता है, लेकिन नेपाल सीमा से सटे रक्सौल के गली-मोहल्ले में क्लिंकर की धूल की परत दर परत जमती जा रही है, लेकिन अधिकारी, नेतागण व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग व पर्यावरणविद को न तो यह धूल दिखाई दे रही है और न ही इस धूल से बीमार जनता की कराह सुनाई दे रही है. रोचक तथ्य तो यह है कि रक्सौल से महज़ तीन किमी की दूरी पर स्थित सिरीसिया में एक ड्राई पोर्ट का निर्माण भी किया गया है, लेकिन क्लिंकर वहां न उतारकर, भारतीय सीमा क्षेत्र में ही उतारा जाता है. इस पूरे कारोबार में शामिल अधिकारी, नेता व अन्य

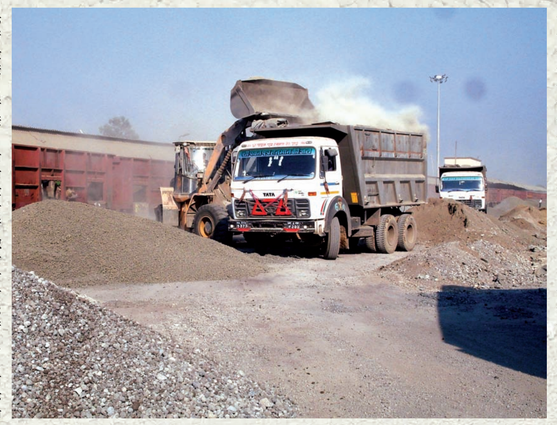

लोगों की तिजोरी का जहां आकार बढ़ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा रफ़्तार में क्लिंकर की धूल से बीमार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है.चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए बीमार लोगों ने बताया कि सरकारी तंत्र और रेलवे को पता नहीं क्या हो गया है, जो हमारी तक़लीफ़ इन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक़, लोगों ने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, सिविल सर्जन व ज़िलाधिकारी को कई मर्तबा अपनी समस्या के बारे में लिख चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. रक्सौल रेलवे स्टेशन के रैक प्वाइंट पर उतारा जाने वाला सीमेंट का यह कच्चा माल जिसे क्लिंकर कहा जाता है, को यहां से नेपाल के वीरगंज, काठमांडू, हेटौडा, कलेया, नेपालगंज व बुटवल आदि शहरों में भेजा जाता है. तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी शंकर बैठा जो स्वयं इस क्लिंकर की चपेट में आ गए थे, ने इस पर रोक लगाने का काम तो ज़रूर किया था, लेकिन उनका आदेश भी ठंडे बस्ते की भेंट चढ़ गया. ज़ाहिर है, रक्सौल में क्लिंकर की धूल उड़ने का कारोबार आज भी जारी है.

बहरहाल रक्सौल में क्लिंकर की ज़हरीली धूल को यहां के भ्रष्ट अधिकारी, रिश्वतखोर सफ़ेदपोशों और सिर्फ़ पहचान के भूखे स्वयंसेवी संगठन के लोगों व संवदेनहीन पर्यावरणविदों का समर्थन हासिल है. ज़ाहिर है अवैध उगाही के दिलचस्प रिश्ते में बंधे इन लोगों के आगे यहां के लोग बेबस हैं. जिन्हें आज भी ऑक्सीजन की जगह मिल रहा है क्लिंकर की ज़हरीली धूल की सौगात.

feedback@chauthidunya.com

बिहार में सजी है हथियारों की मंडी

पृष्ठ 17 का शेष

समानांतर गिरोह चलाने वाला सिल्लू मियां सबसे ज़्यादा एके 47 लेकर बिहार आया था. सिल्लू मियां ने इस हथियार को पहली बार बिहार के अपराधियों को न सिर्फ़ दिखाया, बल्कि इसे उनके हाथों बेचा भी. उस समय सिल्लू मियां ने एक एके 47 राइफल 73 हज़ार से लेकर एक लाख रुपये तक में बेची थी, लेकिन आज इसकी क़ीमत सात लाख से ज़्यादा है. सिल्लू मियां बिहार का पहला अपराधी था, जिसके संबंध दुबई और नेपाल में बैठे अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से थे. इसके कई चेले आज विधायक और सांसद बने हैं. आज हर आपराधिक गिरोह एके 47 जैसे हथियार रखना अपना स्टेटस सिंबल समझता है. वैसे बिहार पुलिस को पहली एके 47 कुख्यात अपराधी अशोक सम्राट के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मिली थी. बिहार के अपराधियों को भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश की खुली सीमा से भी फ़ायदा पहुंचता है. ये दोनों रास्ते विदेशी हथियारों की तस्करी के लिए सेफ़ ज़ोन बने हैं. बिहार में विदेशी हथियारों की खेप पहुंचाने में नेपाल के एक पूर्व मंत्री मिर्ज़ा दिलशाद बेग का नाम लिया जाता है. अब तो आलम यह है कि हर साल करोड़ों के हथियार बिहार में लाए जाते हैं और यहां से दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं. इसके लिए तस्करों का एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है जिसमें कई सफ़ेदपोश लोग भी शामिल हैं.

हाल के दिनों में ख़ुफ़िया विभाग को मिली एक नई रिपोर्ट ने सरकार की नींद हराम कर दी है. इस रिपोर्ट की मानें तो नेपाल में सरकार बनने के बाद वहां सक्रिय माओवादी काफी तादाद में अपने हथियार औने-पौने दामें में बिहार के अपराधिक गिरोहों के हाथों बेच रहे हैं. इस वजह से बिहार में सक्रिय हथियार सिंडिकेट की बांछें खिल गई हैं, क्योंकि नेपाली माओवादियों के पास जो हथियार हैं, वे काफी अच्छी हैं. फ़िलहाल जहां बाज़ार में एके 47 का दाम सात से आठ लाख रुपये हो गया था, इसे माओवादी महज़ एक से डेढ़ लाख रुपये में बेच रहे हैं. इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और एसएसबी की तरफ़ से भी स्थानीय अपराधी गिरोहों पर नज़र रखी जा रही है. अगर विदेशी हथियारों की बात छोड़ दें तो बिहार में बने देसी हथियारों की भी काफी डिमांड है. बिहार के मुंगेर स्थित बंदूक कारखाना में जितनी बंदूकें नहीं बनती होंगी, उससे ज़्यादा इस ज़िले में चलने वाले हथियारों के मिनी गन फैक्ट्री में बनती हैं. मुंगेर में बनने वाले हथियारों में कट्टा से लेकर कारबाइन, स्टेनगन, माउजर, रिवाल्वर और राइफल तक हैं. कहा तो यह भी जाता है कि यहां के कारीगरों ने एके 47 का डुप्लीकेट भी तैयार कर लिया है. मुंगेर में बने हथियारों की डिमांड पड़ोसी राज्यों में खूब है, क्योंकि इन्हें देखकर असली और नकली का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है. यहां से ट्रेन और सड़क मार्ग से झारखंड और बंगाल ही नहीं, दिल्ली और यूपी तक हथियार भेजे जाते हैं. चुनाव के दौरान तो मुंगेर के हथियार कारीगरों को भाड़े पर ले जाया जाता है, जहां ये ठेके पर हथियार और बम बनाते हैं. दरअसल बंदूक फैक्ट्री से रिटायरमेंट के बाद या वहां होने वाली कम कमाई के कारण यहां के कुशल कारीगर अवैध हथियार के निर्माण की तरफ़ मुड़े हैं. इसके अलावा नालंदा ज़िला भी अवैध हथियारों के निर्माण के लिए जाना जाता है. नालंदा के किसकोहरा इलाक़े में तो कई गांव ऐसे हैं जहां अवैध हथियारों के बाक़ायदा शोरूम तक हैं, जहां अवैध हथियारों की ख़रीद-बिक्री होती है. यहां बड़े तो बड़े, बच्चे भी कट्टा और बंदूक बनाना जानते हैं. अवैध हथियारों के कारोबार में एक नया फंडा है हथियारों को भाड़े पर लगाना. यहां पर एक अपराधी दूसरे अपराधी गिरोहों को भाड़े पर हथियार देते हैं. हालांकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल बाहुबली ही करते हैं. बाहुबली राजनेता ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अपने बाहुबल को दिखाने के लिए करते हैं. बिहार के एक बाहुबली विधायक के पास अत्याधुनिक हथियारों का ज़खीरा है. विधायक बनने के पहले इसका वे ख़ुद इस्तेमाल करते थे, अब इनके गुर्गे इसे भाड़े पर चलाते हैं. जबकि एक पूर्व सांसद के गुर्गे तो भाड़े पर हथियार चलाकर अपने गिरोह का संचालन तक कर रहे हैं. उनके ज़्यादातर हथियार पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अपराधी गिरोह और वहां के बाहुबली प्रयोग करते हैं.

सूबे के ज़िलों में अवैध हथियारों का निर्माण होता है तो इसकी बोली पटना के बड़े-बड़े होटलों में लगती है. पिछले 12 अक्टूबर को पटना पुलिस ने गांधी मैदान इलाक़े में दो हथियार तस्करों को पकड़कर उनके पास से 23 सौ कारतूस बरामद किए थे. साथ में ढाई लाख रुपये भी. इन कारतूसों को टेवेरा गाड़ी में छुपाकर कानपुर से लाया गया था. गिरफ़्तार तस्करों में एक मंटू शर्मा है, जो पिछले साल भी अपने आठ अन्य सहयोगियों के साथ हथियारों की तस्करी के दौरान पकड़ा गया था. तब उसके पास से बेचे गए अवैध हथियार के साथ साढ़े चार लाख रुपये नगद भी बरामद किए गए थे. अभी जो कारतूस बरामद हुए हैं, इनमें एके 47 के अलावा 315, 2.5 की गोलियां थीं. ये गोलियां कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी हुई थीं. इससे पहले भी 16 नवंबर, 08 को हथियार तस्करों की गिरफ़्तारी हुई थी, जबकि 13 फरवरी, 09 को दो हथियार तस्करों को साढ़े चार लाख रुपये और एक हज़ार कारतूस के साथ पकड़ा गया था. हालांकि गिरफ़्तारी के बाद ये तत्कर ख़ुद को नक्सलियों का हथियार सप्लायर बताते हैं, जबकि हक़ीक़त यह है कि इनका संबंध आपराधिक गिरोहों के साथ होता है. बिहार में हथियारों की तस्करी और ख़रीद- बिक्री की जानकारी मुख्यालयों में बैठे अधिकारियों को भी है. एडीजी (मुख्यालय) नीलमणि कहते हैं, अवैध हथियारों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती रहती है. हाल के दिनों में एसटीएफ और ज़िला पुलिस की कार्रवाई में ऐसे कई गिरोहों के सदस्य पकड़े गए हैं और इनके कई ज़खीरे को बरामद भी किया गया है. ख़ास बात है कि ऐसे मामलों की त्वरित जांच और दोषियों को सज़ा दिलाने की दिशा में भी अच्छी कार्रवाई हुई है, जिससे हथियारों की ख़रीद-बिक्री करने वालों में ख़ौफ़ छाया है.

feedback@chauthidunya.com

विक्रमशिला विश्वविद्यालय उपेक्षा का दंश झेल रहा है

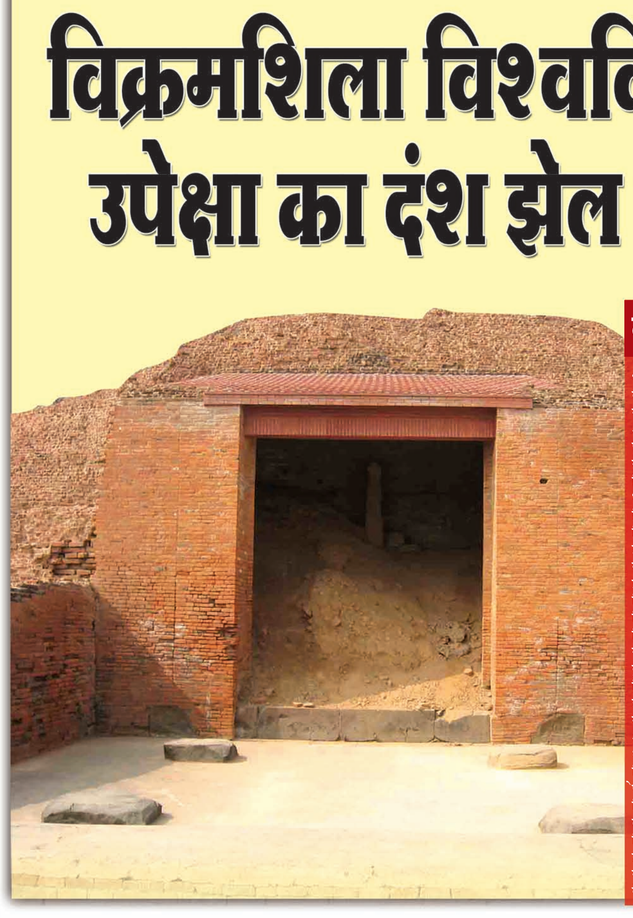

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

भागलपुर संग्रहालय के अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश पांडेय का मानना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हो गया. उनके अनुसार अगर इस क्षेत्र में खुदाई स्थल के आसपास व्यापक पैमाने पर खुदाई कराई जाए तो कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आएंगे, जो शायद विक्रमशिला के इतिहास को भी बदलकर रख देगा. तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्राध्यापक डॉ. राजीव कुमार सिन्हा बताते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास और संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर भी आज तक कुछ नहीं किया गया, जबकि विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसके लिए एक विभाग भी स्थापित है. उनके अनुसार अगर स्थानीय स्तर पर भी इस धरोहर के संरक्षण के लिए कुछ किया गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं रहती. विशेषज्ञों की मानें तो खुदाई स्थल के इर्द-गिर्द अभी भी मिट्टी के कई ऐसे टीले हैं, जिन्हें खुदाई के लिए आज तक नहीं छुआ गया है, जबकि इन स्थलों की पुरातात्विक खुदाई बहुत ज़रूरी है. उनके अनुसार अगर जल्द ही इस प्राचीन और गौरवशाली धरोहर के लिए व्यापक स्तर पर कुछ नहीं किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यहां मैदान के सिवा कुछ नहीं बचेगा.

ई सरकारें आईं और चली भी गईं. सूबे में कई बार सत्ता परिवर्तन के बावजूद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क़िस्मत नहीं बदली. इसके विकास और संरक्षण की बस बातें भर होती रहीं. इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहें या फिर जानबूझकर की गई उपेक्षा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास एक पर्यटक स्थल के रूप में आज तक नहीं हो सका है.

उचित रख-रखाव के अभाव में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष नष्ट होते जा रहे हैं. खंडहर की ईंटों को निकालकर ग्रामीणों ने उससे अपना घर बना लिया. लोग इसके अवशेषों का अलग-अलग तरह से उपयोग कर रहे हैं. परिसर को लोगों ने चारागाह बना दिया है. सुरक्षा बंदोबस्त के अभाव में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य आज मिट चुके हैं.

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास और संरक्षण के साथ-साथ इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा कई बार की गई. बावजूद इसके आज यहां पर्यटकों के ठहरने के लिए न तो किसी गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया और न ही यहां कोई अन्य व्यवस्था ही है. स्थिति यह है कि खुदाई स्थल तक जाने के लिए सड़क भी अच्छी स्थिति में नहीं है. यहां तक कि यदि कोई पर्यटक खुदाई स्थल के आसपास भ्रमण कर रहा हो तो तेज़ धूप या बारिश में सिर छुपाने के लिए भी उसे जगह नहीं मिलेगी. इसके कमरे तो पहले ही ढह चुके हैं और मुख्य अराधना कक्ष पूरी तरह मिट्टी का किला बन गया है. इसके अलावा भित्तियों पर उकेरी टेराकोटा की कलाकृतियां पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं. इन पर आज तक किसी भी प्रकार का रासायनिक लेप नहीं लगाया गया. बस किसी भी तरह सीमेंट और गारे से समय-समय पर उसकी मरम्मत भर कर दी जाती है.

कुमार आदित्य
feedback@chauthidunya.com

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना

40 साल में 44 गुना बढ़ चुकी है लागत

क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि तीस करोड़ रुपये की किसी परियोजना की प्राक्कलित धनराशि बढ़कर लगभग 1300 करोड़ रुपये हो गई है? ऐसा ही हुआ है उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के साथ. औरंगाबाद और गया ज़िले के अर्सेचित भू-भाग की सिंचाई के लिए 70 के दशक में शुरू की गई उत्तर कोयल जलाशय परियोजना झारखंड सरकार की उदासीनता का शिकार होकर रह गई है. किसानों को ख़ुशहाल करने के मक़सद से इस परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया गया था. इसके अब तक पूरा न हो पाने के कारण खेतों के पटवन के लिए हर साल हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहता है. बिहार एवं झारखंड की इस संयुक्त परियोजना का उद्गम स्थल कुटकु (मंडल) झारखंड में है. सोन की सहायक नदी उत्तर कोयल पर कुल 1170 मिलियन घनमीटर जल संग्रहण के लिए 67.86 मीटर की अधिकतम ऊंचाई एवं 343 मीटर लंबाई वाला सोनरी डैम वर्षों से निर्माणाधीन पड़ा है. इस डैम से 96 किलोमीटर नीचे जल प्रवाह के पिकअप के लिए मोहम्मदगंज (झारखंड) में 819.60 मीटर लंबे बैराज का काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है. इससे फसलों को पर्याप्त मात्रा में पटवन के लिए पानी नहीं मिल पाता है और किसानों के बीच मारामारी की स्थिति बनी रहती है. इस परियोजना से गया व औरंगाबाद जिले के 1,11,800 हेक्टेयर भू-भाग सहित कुल 1,24,270 हेक्टेयर भू-भाग की सिंचाई होनी है, परंतु लगभग 40 वर्षों से पूर्ण निर्माण का बाट जोह रहे इस नहर से 40 से 50 हज़ार हेक्टेयर भू-भाग की भी समुचित सिंचाई नहीं हो पाती. आलम यह है कि यह केवल बरसाती नहर बन कर रह गई है.

रवि सिंह
feedback@chauthidunya.com

एस.एन.एस. कॉलेज, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण

श्री नारायण सिंह महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को दीपावली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।यह आग्रह किया जाता है कि अपने-अपने बच्चों को जो श्री नारायण सिंह महाविद्यालय मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के छात्र व छात्रा हैं, को कॉलेज में कम से कम 75 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए प्रेरित करें और उनका मनोबल बढ़ाएं।

सभी छात्र-छात्राओं व अभिभावकों को कॉलेज प्रशासन की ओर से

शुभकामनाएं

श्री एन एन सिंह

प्रचार्य

एस.एन.एस. कॉलेज

मोतिहारी, पूर्वी चंपारण

मोबाइल नंबर 9430051680

किसी को बेवजह पेरशान नहीं किया जा रहा है और न ही किसी को क़ानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त दी जा रही है. पर सरकार के इस दावे को सहरसा की धरती पर आयोजित क्षत्रिय सम्मेलन में ख़ारिज़ कर दिया गया.

सहरसा क्षत्रिय सम्मेलन

नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प

सहरसा में आयोजित विराट क्षत्रिय सम्मेलन में देश के कोने-कोने से आए नेताओं व जुटी लोगों की भारी भीड़ को अगर कोई पैमाना माना जाए तो मतलब निकाला जा सकता है कि नीतीश सरकार में अपनी उपेक्षा से राजपूत समाज बेहद ख़फ़ा है. ख़ासकर आनंद मोहन के मामले में इस सम्मेलन में जुटे लोगों की राय थी कि सरकार उन्हें बेवजह परेशान कर रही है. सम्मेलन से जो राजनीतिक संदेश गया उसका मतलब यह है कि क्षत्रिय समाज उसी राजनीतिक दल का साथ देगा जो उसके मान-सम्मान की हिफ़ाज़त करेगा. सम्मेलन में झूठे वायदे करने वालों को आगामी चुनाव में सबक सिखाने का भी संकल्प लिया गया.

ज़िले के नगर परिषद मैदान में संपन्न विराट क्षत्रिय सम्मेलन में देश के अन्य प्रांतों से आए राजपूत समाज के नेताओं ने एकजुटता दिखाकर यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार की सरकार उनकी हितैषी नहीं है.

ज़िले के नगर परिषद मैदान में संपन्न विराट क्षत्रिय सम्मेलन में देश के अन्य प्रांतों से आए राजपूत समाज के नेताओं ने एकजुटता दिखाकर यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार की सरकार उनकी हितैषी नहीं है.फ़र्ज़ी मुक़दमे में फंसा कर इस समाज के नेताओं व लोगों को परेशान किया जा रहा है. दरअसल आनंद मोहन को लेकर सरकार की कार्रवाई पर इस समाज में बेचैनी है. उन्हें लगता है कि इस मामले में सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन सरकार बार-बार कहती आ रही है कि क़ानून अपना काम कर रहा है. किसी को बेवजह पेरशान नहीं किया जा रहा है और न ही किसी को क़ानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त दी जा रही है. पर सरकार के इस दावे को सहरसा की धरती पर आयोजित क्षत्रिय सम्मेलन में ख़ारिज़ कर दिया गया. सम्मेलन मंच से ही आगामी 19 जनवरी, 2010 को सिंह गर्जना रैली की घोषणा करते हुए पटेल मैदान सहरसा में पांच लाख लोगों के भाग लेने का ऐलान किया गया. क्षत्रिय नेताओं के अनुसार, इस रैली में नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने का शंखनाद किया जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आश्रम खोलेंगे नीतीश

फोटो-प्रभात पाण्डेय

हर किसी की चाहत होती है कि उसके बचपन का सपना पूरा हो. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने बचपन में दो सपने संजोए थे, पहला सांसद बनने का और दूसरा बेसहारा बच्चों और लाचार बुज़ुर्गों के लिए एक आश्रम खोलने का. सांसद बनने का उनका सपना तो कब का पूरा हो गया, मगर दूसरे सपने को लेकर वह इन दिनों कुछ चिंतित दिखते हैं. ज़मीन का इंतज़ाम न होना उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है. वह चाहते हैं कि सौ एकड़ ज़मीन में खुलने वाला यह आश्रम पूरी तरह आत्मनिर्भर रहे और एक ऐसा ठिकाना बने, जहां से कोई नाउम्मीद होकर न लौटे.

मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि एक समाजसेवी के रोल में नीतीश कुमार अपने इस सपने को साकार करने में लगे हैं. वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की हसरत मुझे कभी नहीं रही, पर समय का ऐसा चक्र चला और जनता की मर्ज़ी हुई तो मैं इस कुर्सी पर बैठकर राज्य की सेवा कर रहा हूं. आश्रम खोलने के पीछे उनकी अवधारणा यह है कि उम्र के अंतिम पायदान पर कोई बुज़ुर्ग बेसहारा न रह जाए. ऐसे बच्चों, जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी ठीक से शुरू भी न की हो, को दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें. यह एक ऐसा काम है, जिसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए.

> **“मुख्यमंत्री बनने की हसरत मुझे कभी नहीं रही, पर समय का ऐसा चक्र चला और जनता की मर्ज़ी हुई तो मैं इस कुर्सी पर बैठकर राज्य की सेवा कर रहा हूं.”**

मुख्यमंत्री बताते हैं कि आश्रम का माहौल पूरी तरह से पारिवारिक रहेगा. वहां खेती होगी, डेयरी चलेगी, पशुपालन की व्यवस्था होगी, फूलों की नर्सरी एवं फलों के बगीचे के साथ ही पार्क और बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल भी होगा. कृषि, डेयरी एवं अन्य कारोबार की आय से आश्रम में रहने वाले लोगों का भरण-पोषण होगा. आश्रम के चारों ओर शीशम और सखुआ के पेड़ लगाए जाएंगे, इसके लिए कम से कम सौ एकड़ ज़मीन चाहिए. जितनी ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, आश्रम उतना ही अच्छा बनेगा. वह कहते हैं कि मैं आश्रम की ज़मीन अपने नाम करने के लिए नहीं कह रहा हूं. अगर कोई व्यक्ति आश्रम के लिए ज़मीन देगा तो भी मालिकाना हक़ उसी का रहेगा. आश्रम की ज़मीन को कोई दूसरा व्यक्ति बेच नहीं सकता है. भविष्य में अगर आश्रम नहीं चला तो ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन वापस ले सकता है. नीतीश इस आश्रम को दुनिया के बेहतरीन आश्रमों में से एक बनाना चाहते हैं. उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका यह सपना जनता के सहयोग से एक दिन ज़रूर पूरा होगा.

संतोष कुमार
feedback@chauthiduniya.com

NATIONAL MEDICAL COLLEGE
BIRGUNJ (NEPAL)
ADMISSION NOTICE FOR MBBS/MD/MS COURSE,2009-10
ONE OF THE BEST AND BIGGEST MEDICAL COLLEGE OF NEPAL.THE COLLEGE HAS 1050 BADED TEACHING HOSPITAL AND ISO-9001 CERTIFICATION. DEGREE AWARDED BY INTERNATIONAL RECOGNIZED TRIBHUWAN UNIVERSITY AND RECONIZED BY NEPAL MEDICAL COUNCIL AND ENLISTED IN W.H.O. WORLD DIRECTORY OF MEDICAL SCHOOL

Invited
APPLICATION FOR 9TH BATCH MBBS
And
2ND BATCH MD/MS COURSES FOR 2009-10
For Details Information
PLEASE CONTACT

Dr. Perwez
Internationa Director

Mr. Basruddin Ansari
Managing Director

ADMISSION DEPARTMENT
NATIONAL MEDICAL COLLEGE
BIRGUNJ NEPAL
Mob - 00977-9855020625 (NEPAL)
09431233521,09431233119(INDIA)
E.MAIL-nmcbir@atcnet.com
Web;www.nmcbir.edu.np

LIAISON FOR INDIA AND ABROAD
Dr. Perwez
(INTERNATIONAL DIRECTOR)
M.J.HEART HOSPITAL MOTIHARI,(BIHAR)
PH NO-06252 -232895
MOB No-09431233023,098738003195
EMAIL drperwez_mth@rediffmail.com

Dr. Jainuddin Ansari
Chairman